लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करगा

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

7.14

LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला Third Series

खंड 42, 1965/1887 (शक) Volume, XLII, 1965/1887 (Saka)

20 अप्रैल से 1 मई, 1965 तक/30 चैत्र से 11 वशाख, 1887 (शक)तक April 20 to May 1, 1965/Chaitra 30 to Vaisakha 11, 1887 (Saka)





ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक) Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

खंड 42 में झंक 41 से 50 तक हैं Vol. XLII contains Nos. 41—50

> लोक-सभा सिचवालय नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT NEW DELHI [[यह सोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त ग्रह्यित संत्करण है ग्रीर इस में ग्रंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों का ग्रादि का हिन्दी/ग्रंग्रेजी में ग्रनुवाद है

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

ग्रंक 46--मंगलवार, 27 अप्रैल, 1965/7 वैशास, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित	विषय	पृष्ठ
प्रक्त संख्य	T	-
1032	राजधानी में दुर्घटनायें .	4323-25
1033	सहकारी समितियां	4325-28
1034	उर्वरकों का सम्भरण	432831
1035	राज्यों में सहकारी समितियां	4331-33
1037	गेहूं के जहाजों का ग्रन्य स्थानों को भेजा जाना .	433335
1038	खादी तथा ग्रामोद्योग भ्रायोग के कर्मचारियों के वेतन-क्रम	4335-36
1039	खड़ी फसलों को नुकसान	433639
1040	भ्रनाज संग्रह प्रणाली	4340-43
1041	फार्म-उत्पादों की कीमतों संबंधी रिपोर्ट	. 4343-45
1042	रबी की फसल	. 4345-46
प्रश्नों के लि	ाखित उत्तर	
तारांकित		
प्रदन संख्या		
1036	पटसन की खेती का क्षेत्रफल .	4346
1045	कृषि-उत्पाद मूल्य श्रायोग	4346
1046	ग्रनाज का उतारा जा ना .	4347
1047	चावल की सहकारी मिलें	4347-48
1048	दिल्ली में दुग्ध बस्ती	4348
1049	परिसीमन ग्रायोग	4348-49
1050	एयर कारपोरेशन का विलय	4349
1051	एयरइण्डिया एरोफ्लोट विमान सेवा करार	4349
1052	भूमि सुधार .	4350
ग्रतारांकित		
प्रदन संख्या		
2622	ग्रादिम जातियों ग्रौर पि छ ड़े वर्गों का कल्याणः	4350
2623	मध्य प्रदेश में ग्रादिम जातीय छात्र	4350
2624	मैट्रिक उपरान्त छात्रवत्तियां	4350

^{*ि}कसी नाम पर ग्रंकित यह - चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था

CONTENTS

No. 46.— Tuesday, April 27, 1965/Vaisakha 7, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question	- 7				
Nos.	Subject				PAGES
1032	Accidents in Capital				43232 5
1033	Co-operative Societies .				4325—28
1034	Supply of Fertilizers				4328—3 1
1035	Co-operative Societies in States				433133
1037	Diversion of Wheat Ships .				433335
1038	Pay Scales of Employees of Kha Commission	idi and Village Ind	lustri	es	4335-36
1039	Damage to Standing Crops .				433639
1040	Grain Storage System.				4340-43
1041	Report of Farm Prices				434345
1042	Rabi Crop				4345 -46
WRIT Starred Question Nos.		ONS			
1036	Acreage Under Jute Cultivation				4346
1045	Agricultural Prices Commission				4346
1046	Unloading of Foodgrains .				43.47
1047	Cooperative Rice Mills .				4347-48
1048	Milk Colony in Delhi .				4348
1049	Delimitation Commission .				4348-49
1050	Merger of Air Corporations				4349
1051	Air India Aerofloat Air Agreeme	nt			4849
1052	Land Reforms				4350
Unstarr Question Nos.					
2622	Welfare of Tribal and Backward	Classes			4350
2623	Tribal Students in Madhya Prad				43 5 0
7	Post-Matric Scholarships .				43 <i>5</i> 0
•	-			-	-1.J.J.

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारो

ग्रतारांकित

त्रश्न संख्य	र विष	ब		•	र् ड
2625	दहेज रोक ग्रधिनियम, 1961			4351-	5 2
2626	बंगलीर दिल्ली उड़ान .			. 43	52
2627	मध्य प्रदेश में संघन खेती कार्यक्रम			. 4352	54
2628	चीनी की उपलब्धता			. 43	354
2629	बागबानी का विकास	•,		. 43	54
2630	उत्तर प्रदेश में डेरी फार्म .			. 43	55
2631	मिट्टी ग्रनुसन्धान केन्द्र			. 4355-	56
2632	दिल्ली चिड़ियाघर .			. 43	56
2633	विदेश भेजे गये किसान			. 4356-	57
2634	महाराष्ट्र में भ्रादिवासी खण्ड .			. 43	57
2635	महाराष्ट्र को उर्वरकों का सम्भरण			43 57 –	5 8
2636	महाराष्ट्र में पैकेज प्रोग्राम			4358-	59
2637	विदर्भ में ग्रादिवासी विद्यार्थी .		•	43	59
2638	विदर्भ के म्रादिवासियों का कल्याण			. 43	59
2639	ग्रनाज की नीलामी	•		4359-	•60
2640	धान कर की वसूली			. 43	60
2641	क्विलोन का छोटा बन्दरगाह .			4360-	61
2642	टूटीकोरिन बन्दरगाह .			43	61
2643	केरल में कमी की स्थिति			4361-	62
2645	निर्वाचन चिन्ह		•.	. 43	62
2646	सामुदायिक विकास खंड .			. 4362	6 3
2647	पटसन ग्रौर लाख ग्रनुसंधान केन्द्र .			. 43	64
2648	चाय के बाग			. 4364-	65
2649	उत्तरी बिहार में विमान सेवा			. 43	65
26 5 0	जहाज बनाने का सामान			43	65
2651	खादी उत्पादन			. 4365-	66
2652	कृषि वैज्ञानिकों के तालिका .		•.	43	6 6
2653	राज्यों का चीनी का कोटा .			4366-	67
2654	भारतोय कृषि ग्रन्सन्धान परिषद्			43	67
2655	शहरी सहकारी बैंक			4357 -	68
2656	उड़ीसा में हस्तशिल्प भंडार .			. 43	68
2657	श्रनुसूचित जातियों तथा श्रनुसूचि सहायता	त ग्रादिम जातियो	ंको कान्		69
2658	विधेयकों का हिन्दी रूपान्तर				69
2659	शिल्पकारों के लिये कच्चा माल .				69
2660	पिछड़े हुए क्षेत्रों में चीनी कारखाने				70
2661	उड़ीसा में कृषि उत्पादन .		•		70
2652	गुजरात राज्य को बाजरे का संभरण	r	•	4370-	
2002	नुन रात राज्य मर्गायार यस सामार्थ	•		40 20	

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—contd.

Unstarred Question Subject PAGES Nos. 2625 Dowry Prohibition Act, 1961 4351-52 2626 Bangalore-Delhi Flight 4352 2627 Intensive Agricultural Programme in M.P. 4352--54 2628 Availability of Sugar. 4354 2629 Development of Horticulture 4354 2630 Dairy Farms in U.P. . 4355 4355-56 2631 Soil Research Centres. 2632 Delhi Zoological Park 4356 2633 Farmers sent Abroad. 4356-57 2634 Blocks of Adivasis in Maharashtra 4357 2635 Supply of Fertilizers to Maharashtra 4357-5 2636 Package Programme in Maharashtra 4358-59 2637 Adivasi Students in Vidarbha 4359 2638 Welfare of Adivasis of Vidarbha. 4359 2639 Auction of Foodgrains 4359-6 2640 Collection of Levy on Paddy 4360 2641 Quilon Minor Port . 43**6**0-61 2642 Tuticorin Port 4361 2643 Scarcity conditions in Kerala 4361-62 2645 Election Symbol 4362 **2646** C.D. Blocks 4362-63 2647 Jute and Lac Research Centres 4364 2648 Tea Gardens 4364-65 2649 Air Service in North Bihar. 4365 2650 Ship-building Material 4365 2651 Production of Khadi . 4365-66 2652 Panel of Agricultural Scientists 4366 2653 Sugar Quota of States 4366-67 2654 I.C.A.R. . 4367 2655 Urban Cooperative Banks . 4367-68 2656 Handicraft Emporia in Orissa 4368 2657 Legal Aid to S.C. and S.T. 4369 2658 Hindi Translation of Bills . 4369 2659 Raw Materials for Craftsmen 4369 2660 Sugar Factories in Backward Areas 4370 2661 Agricultural Production in Orissa 4370 2662 Supply of Bajra to Gujarat State. 4370-71

प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी

मतारां वि	त	
प्रश्न संख्य	ग विषय	पुष्ठ
2663	पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन ग्रौर संचार	. 4371
2664	भारतीय खाद्य निगम	. 4372
2665	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के ग्रन्तर्गत कार्यालय .	. 4375-73
2666	राष्ट्रीय राजपथ .	4373
2667	चावल का प्राप्त करना	4373
2638	चावल की बिक्री पर कर	4374
2669	सरसों के बीजों का मूल्य	4374
2670	म्रादिवासी खण्डों में सड़कें	4374-75
2671	म्रादिवासी खण्ड	4375-76
2672	म्रादिम जाति विकास खण्ड .	4376
2673	श्रादिवासी विकास खण्ड	4377-78
2674	पर्यटक कर्मचारियों का प्रशिक्षण	4378
2675	पंजाब में कृषि ग्रौद्योगिक निगम	437 8-79
2676	टोरों के लिये चारा	4379-80
2677	फलों का चूर्ण बनाने वाला कारखाना	4380
2678	सूत्र्रगर पालन	4380-81
2679	गन्ने का मूल्य	4381
2680	ग्रनाज का परिवहन	4381-82
2681	कलकत्ता-ग्रासाम रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी .	4382-84
2682	चावल बनाने पर प्रतिबन्ध	. 4384
2683	खाद्यभण्डार	. 4384
2684	बिहार फ्लाइंग क्लब के त्रिमान का विवशतावश उतरना	4385
2685	ग्रास्ट्रेलिया से उपहार के रूप में बेकरिया <u>ं</u>	4385
2686	गोबर का ईंधन के रूप में प्रयोग .	4386
2687	साताकुज् हवाई ग्रड्डे पर राडार सहायक-यंत्र	4386-87
2688	स्वीडन से दुग्धशाला संबंधी उपकरण की खरीद	4387
2689	मद्रास में भाण्डागार .	4387
2690	मद्रास में समाज कल्याण	. 4388
2691	देहाती कार्य प्रोग्राम	4388-89
ग्रविलम्ब नी	य लोक महत्व के विषय की ग्रोर घ्यान विलाना—	
बाराहोत	ी के निकट चीनी सेना के भारी जमाव के समाचार	4389-96
श्री हु	क्रम चन्द क्छगय	4389-90
श्री य	ाशवन्त राव चव्हाण	439196

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—contd.

Unstarred **Ouestion** Nos. Subject PAGES 2663 Transport and Communications in Hilly Areas 437I 2664 Food Corporation of India. 4372 2665 Offices under Ministry of Food and Agriculture 4372-73 2666 National Highways 4373 2667 Procurement of Rice 4373 2668 Levy on Sale of Rice 4374 2669 Price of Mustard Seeds 4374 2670 Roads in Tribal Blocks 4374-75 2671 Tribal Blocks 4375-76 2672 Tribal Development Blocks 4376 2673 Tribal Development Blocks 4377-78 2674 Training of Tourist Personnel 4378 2675 Agro-Industrial Corporation in Punjab 4378-79 2676 Fodder for Cattle 4379-80 2677 Fruit Powder Manufacturing Plant' 4380 2678 Breeding of Pigs 4380-81 2679 Prices of Sugar-cane. 4381 2680 Transportation of Foodgrains 4381-82 2681 Calcutta-Assam River Steam Navigation Co. 4382-84 2682 Ban on Pounding of Rice . 4384 2683 Food Reserves . . . 4384 2684 Forcelanding of Bihar Flying Club Plane 4385 2685 Bakeries as gift from Australia 4385 2686 Cow-dung used as Fuel 4386 Radar Aid at Santa Cruz Airport. **26**87 4386-87 2688 Purchasing 4387 22689 Ware-houses in Madras 4387 2690 Social Welfare in Madras 4388 2691 Rural Works Programme 4388-89 Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance Reported heavy concentration of Chinese troops near Barahoti 4389-96

4389-90

4391-56

Shri Hukam Chand Kachhavaiya

Shri Y.B. Chavan

सभा पटल पर रखे ग	ये पत्र	•	•	••	••	• ·	439697
कच्छ-सोमा पर पाकि	स्तानी ग्रात्र	भण से उ	त्पन्न स्थि	ति पर च	र्वाके का	रे में	
प्रा वक लन ्स ि	रति		•	• -	• ·	•	4398
ंतिहत्तरवां प्रतिवेद	(न						4398
सरकारी श्राद्यासन	ों सम्बन्धी	समिति	••		• •	•.	4398
कार्यत्राही-सारांश							4398
ब्रनुदानो की मांगें			• •	••	~		43984436
गृह-कार्य मंत्रालय							43984414
श्री मौर्य							4398-99
श्री ग्रन्सार हर	वानी						43994400
श्री हिम्मतसिंह							4400-01
श्री नन्दा							440114
खाद्य तथा कृषि मं	जालय				• ·		4414
श्री नरसिम्हा							441517
श्री विभृति मि	-						4417-18
श्री सरजू पाण्डे			• ·	• ·			4418-19
श्रीपु•र•परं			•	•.			4419-29
श्री चांडक							4429-31
श्री शिवमूर्ति स	त्वामी						443133
श्रीकृ० चं० श	_						4433
श्रीमती स्रकम							4433-34
श्रः कन्डप्पन							4434-35
श्री राधेलाल	च्या स						4435-36
हार्य मंत्रणा ममिति	ī	•	•~	•-	••		44377
कत्तीसवां प्रतिवेद	त् .		•-		• -		44377

Subject		PAGES:
Papers laid on the Table		439 6 –9 7 ′
Re: Discussion on situation arising out of attacks by Pakistan	on	
Kutch border		4398.
Estimates Committee .		4398
Seventy-third Report		4398-
Committee on Government Assurances		4398
Minutes		4398
Demands for Grants		4998-4 436 -
Ministry of Home Affairs		4398-4414
Shri Maurya		4398-99
Shri Ansar Harvani.		4399 -4400
Shri Himmatsinhji .		4400-0I
Shri Nanda		4401-14
Ministry of Food and Agriculture	•	44 T 4
Shri Narasimha Reddy		4415-17
Shri Bibhuti Mishra		4417-18
Shri Sarjoo Pandey .		4418-19
Shri P.R. Patel		441929
Shri Chandak		4429-31
Shri Sivamurthi Swamy		4431-33
Shri K.C. Sharma		4438
Shrimati Akkamma Devi .		4433-34
Shri S. Kandappan .		4434-35
Shri Radhelal Vyas		4435-36
Business Advisory Committee		4437
Thirty-sixth Report	•	4437

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त धनूदित संस्करण) Lok Sabha Debates (Summarised Translated Version)

लोक-सभा LOK SABHA

मंगलवार, 27 भप्रेल, 1965/7 वैशाख, 1886(शक) Tuesday, April 27, 1965/Vaisakha 7, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

श्रिष्यक्ष महोदय पोठासीन हुए Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राजवानी में बुर्घटनायें

+

श्री यशपाल सिंह : श्री स० मो० बनर्जी : श्री रामेश्वर टांटिया : श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री श्रोंकार लाल बेरवा : श्री प० चं० बहन्ना : श्री प० ह० भील : श्री राम हरख यादव : श्री मुरली मनोहर :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि राजधानी में **भा**तक तथा ग्रन्य सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं ;
 - (ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; ग्रौर
 - (ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

ग्रसैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो): (क) में (ग). सभा पटल पर ग्रपेक्षित यूचना देने वास्ता एक विवरण प्रस्तुत है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4285/65]

Shri Yashpal Singh: Have Government ever thought that driving vericles at slow speed makes the mind dull and that vericles in Japan run at the highest speed, but still the number of accidents there, is minimum? Therefore the slow speed should be checked. High speed is checked only during peaceful days, these are war days. In view of this what action Government propose to take to check slow speed so that there be minimum accidents and minds of the people be in good condition?

Shri Kanungo: The engineers and traffic experts are considering this matter.

Mr. Speaker: Here the bullock carts, hand-driven carts and other carts have also to play their parts.

Shri Yashpal Singh: Have Government ever thought that the repairing of roads takes years and this results in a number of accidents? The cause of the murder of Sardar Pratap Singh Kairon was also the repairing. If the repairing is done in a short time, say 15-20 days, the accidents can be avoided to a great extent.

Shri Kanungo: This is one of the aspects that the roads should be widend. But that also requires money.

श्री रामेश्वर टांटिया: 1963 में कितनी दुर्घटनाएं हुई श्री ! उनमें कितने व्यक्ति मरे श्रीर 1963 में कितनी दुर्घटनाएं हुई ?

श्री कानूनयो : दुर्घटनात्रों में कुल 267 व्यक्ति मरे ग्रीर 1963 में इनकी संख्या 245 थे:।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Almost daily we are reading about accidents in newspapers. Have Government evolved any scheme so that accidents can be totally checked in future?

Mr. Speaker: All the measures have been mentioned in the statement. If he wants to make any suggestion he can do so.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: If the Government asks for suggestions, we are prepared to give.

Mr. Speaker: They have mentioned every thing in the statement. Perhaps you have not read that.

श्री प्र० चं० बरुग्रा : बढ़ती हुई दुर्घटनाग्रों को देखते हुए क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच के लिए एक ग्रायोग नियुक्त करने का है ?

श्री कानूनगो : जो हो, इस मास इंजीनियरों, यातायात विशेषज्ञों श्रौर यातायात पुलिस का एक सम्पेजन हो रहा है।

Shri Ram Harakh Yadav: Are there any particular places in Delhi where accidents usually occur? If so, what measures are being taken by Government to make those places safe?

Shri Kanungo: They have been mentioned in the statement.

Shri Sarjoo Pandey: In the statement it is given that many cycles are plying on roads in Delhi, and this is one of the causes of the accidents. And there are some thelas and bllock-carts. Do Government propose to impose restrictions upon them?

Shri Kanungo: Efforts are made to provide separate paths for the cyclists.

Shri Bhagwat Jha Azad: The foreign embassies here have been given diplomatic inpunity. Are Government aware that here most of the accidents occur due to the negligent driving of the foreign embassy cars; if so, whether any action is taken against them or not? So far as foreign countries are concerned, they have got that impunity, but strict action taken there. Why no action is taken against them here?

Shri Kanungo: In cases of accidents with the vehicles of diplomatic missions, they are warned, they are asked to keep qualified drivers and several other actions are taken as a measure.

श्री च० का० भट्टा खार्य : क्या सरकार ने दिल्ली में साइकलों पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार किया है; जो कि रान्नि के समय ग्रिधिकांशत: बिना बत्ती, बिना घंटो ग्रीर शायद क्री को के बगैर भा चलती हैं ?

श्री कातूनगोः जो हां, दिल्लो को यातायात पुलिस को मजरूत कर दिया गया है, यातायात जिलान में एक उड़ान दल्ला है प्रोर समय सन्य वर बहु सहकतों को देखते हैं।

सहकारी समितियां

्रधी द्वा० ना० तिवारी: *1033. < श्री सुबोध हंसदा: श्री स० चं० सामन्त:

मा सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रो यह बताने को कृग करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्र है कि कृषि उत्पादन बोर्ड ने सुझाव दिया है कि दो या तीन राज्यों की हुठ चुने हुए जिनों में हुठ प्रश्नित परियोजनारें चातू को जायें, जिनमें हुठ सुसंगठित सह-कारो सिनित्रिं। विस्तार तथा तेत्रा सुधिबाब्रों तथा उपकरणों के संगरण ख्रोर उनके लिए आदश्य को व्यवस्था कर सकें; ब्रोर
- (ख) यदि हां, तो यि इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है तो उसका म्मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?
- सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीव0 सू0 भूति): (क)

- (ख) योजन। का मसौदा गुजरात, महाराष्ट्र, मैंसूर, मद्रास स्रौर पंजाब की राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणी के लिये भेजा गया है।
- Shri D. N. Tiwary: What are the main features of the draft scheme which has been sent and what time limit has been given to the States for sending their replies?
- श्री ब० सू० मूर्ति: हम नहीं जानते कि राज्य सरकारें ग्रपने उत्तर कब भेजेंगी।
 मोजना उनको गत मास की 23 तारीख को भेजी गई थी ग्रौर हम उनके उत्तर की
 प्रतीक्षा कर रहे है। योजना की एक मुख्य बात यह है कि सहकारी समितियां तकनीकी
 कर्मचारी देगी ताकि वे उत्पादन की जरूरतों के वितरण ग्रोर प्रभावशाली उपयोग में समन्वय
 ग्रौर उनकी देख भाल कर सकें।
- Shri D. N. Tiwary: At what places the pilot projects will be established and what financial arrangements will be made for that? What is the total financial expenditure involved? Has any estimate been made of it?

श्रीब॰ सू॰ सूर्ति : योजना में राज्यों को शामिल करने का विचार है, प्रत्येक राज्य में दो या तीन जिले और प्रत्येक जिले में श्रच्छी तरह से काम करने वाली विपणन समितियां श्रथवा बड़े पेमान की सुगंठित सेवा समितियां होगी । जब तकनीकी कर्मचारी दे दिये जायेंगे, तो राज्य सरकार प्रथम वर्ष में शतप्रतिशत सहायता दे सकेंगी, दूसरे बर्ष में 66 2/3 प्रतिशत श्रीर तीसरे वर्ष में 33 1/3 प्रतिशत।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय उपमंत्री ने श्रभी बताया कि योजना की प्रारूप चार या या पांच राज्यों को भेज दिया गया है । श्रन्य राज्यों को उनकी टिप्पणी के लिए इसे नः भेजने के क्या करण हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति: इसे परियोजना के ग्राधार पर किया जाता है। ग्रभी हम इसः योजना पर तजरबा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री स० चं० सामन्तः इस मंत्रालय द्वारा ग्रारंभ की गई ग्रन्य परियोजनाग्रों से यह परियोजना किन किन बातों में भिन्न है ?

श्रीब०सू० सूर्ति: यह एक नई योजना है। जहां तक सहकारी सिमितियों का सम्बन्ध हैं इस प्रकार की कोई योजना अभी तक आरंभ नहीं की गई है।

श्री शिवनंजप्पा: क्या किसी राज्य में लिफ्ट सिंचाई सिमितियां चालू करने का प्रयासः किया गया है ?

श्री ब॰ सू॰ मूर्तिः जी नहीं, उत्पादन ग्रावश्यकताग्रों के पूर्ण ग्रौर ग्रच्छे उपयोग के लिये यह योजना है। इसिलये ग्रब इस विपणन समितियों को भी ला रहे हैं ग्रौर उनमें तकनीकी सहायता भी होगी।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Often it has been seen that the farmers make great demands for the tractors and the booking companies do not book the tractors. Will Government make efforts for

onward delivery of tractors to the farmers through these Cooperative Societies?

श्रीब॰ सू॰ मूर्ति: इस योजना में ट्रैक्टर शामिल नहीं हैं।

Shri Y. S. Chowdhry: At present besides the various Development Blocks, Co-operative Societies, Agricultural Department and other concerned departments are also working for increasing the production. Apart from the works already taken up under the Pilot Scheme, what other constructive works will be undertaken?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे): इस सारे प्रश्न में कुछ निलंदिक मित्र होती है। जैसा कि स्वयं प्रश्न से पता चलता है, इस विशिष्ट कार्य रूप को, कृषि उत्पादन बोर्ड में किये गये एक निर्णय के अनुसार आरंभ किया गया है। आश्रय यह है कि सरकारी अभिकरण के स्थान पर, जो कि अब तक उर्वरकों और अन्य उत्पादन आवश्यकताओं के उपयोग को बढ़ाने और प्रोत्साहन देने के लिये जिम्मेवार था, सहकारी सिमितियां इसको प्रयोग के तौर पर करेंगे यह देखने के लिए कि क्या सहकारी सिमितियों की बढ़ती हुई संख्या इस का सरकारी अभिकरणों से पहले न करने लगे।

श्री युद्धबीर सिंह : यह केवल एक तजुर्बा है।

Shri Sinhasan Singh: Are Government aware that subsidy is given on the implements which are supplied to the agriculturists through Society or Block? But to get that it is necessary that they should be purchased only from those shops or traders who have been recognised by you. The result of this is that their prices rise about one and a half or two times than the market price. In such circumstances are Government contemplating to grant subsidy if the bill is presented before the Government irrespective of the fact that the implements have not been purchased from the authorised dealers?

श्री सु० कु० डे: सहकारी सिमितियों द्वारा कृषि उपकरणों के वितरण किये जाने से ग्रारोप यह है कि ये उपकरण काश्तकारों को सस्ते दामों पर दिये जायेंगे, शायद बाजर भाव से कम कीमतों पर। यदि इसमें कोई परिवर्तन हुग्रा तो निश्चय ही हम उपायों को सोचेंगे कि काश्तकारों को उन सहकारी सिमितियों द्वारा कोई कठिनाई न हो जो अपेक्षित सेवा नहीं करती हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad: Since the Government always takes pride in foreign know-how and they are always eager to learn that, have any of your team studied the Co-operatives of foreign countries, particularly, Czechoslovakia, where, inspite of the fact that ownership of the land rests in individual farmers, the co-operatives have benefited a lot? Have the Government ever considered this question.

श्री सु॰ कु॰ डें: यूगोस्लाविया सिहत संसार के उन सभी देशों के ग्रनुभवों से हम लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो सहकारी क्षेत्र में काफी भ्रागे हैं।

श्री विश्वनाथ राव : इस योजना के अन्तर्गत कृषि सरकारी सिमितियों की अव-लना क्यों की गई है जिनका गठन प्रथम योजना में किया गया था परन्तु कुछ ऐसी बातें श्री जो उनके काबू से बाहर थीं जिनके कारण वे सफल न हो सके? श्री सु० कु० डे०: किसी ात की स्रवहेलना नहीं की गई है। कोई भी समिति जो बनी रहने योग्य होती है उसको सहायता दो जाती है। अतः स्रवहेलना का प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरकों का सम्भरण

+
श्री कपूर सिंहः
श्री प्र० के० देवः
श्रीमती सावित्री निगमः
श्री रा० गि० दुवेः
श्री प्र० कु० घोषः

क्या साद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि उर्वरक की खपत के 7.50 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में 1964 में उत्तर प्रदेश को केवल 1.70 लाख टन उर्वरक दिया गया था; ग्रीर
- (ख) यदि हां, तो 1965 के लिए लक्ष्य क्या है ग्रौर चालू वर्ष में खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए राज्यों को ग्रिधिक माता में उर्वरक उपलब्ध करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सास्र तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चहाण): (क) तथा (ख). एक विवरण न्सामा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) तथा (ख). 1964-65 के दौरान उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की खपत का लक्ष्य निम्न भकार था:—

	टोन्स
नाईट्रोजिनस उर्वरक (ग्रमोनियम सल्फेट के रूप में)	5,00,000
'फ्रांस्फेटिक उर्वरक (सुपरफास्फेट [े] के रूप में)	1,20,000

1-4-64 को राज्य सरकार के पास ग्रमोनियम सल्फेट का 3,31,000 टोन्स का भारो पूर्वाविश ट स्टाक था उसको दृष्टि में रखते हुए नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों की निम्नलिखित ग्रलाटमेंट की गई:---

		टोन्स
सल्फेट ग्राफ ग्रमोनिया	 	73,445
यूरिया		13,325
अमोनियम सल्फेट नाईट्रेट		15,354
कल्शियम स्रमोनियम नाईट्रेट		1,10,899
नाईट्रोजन के रूप में कुल .		48,000
सल्फेट ग्राफ ग्रमोनिया के रूप में		2,33,000

फासफेटिक उर्वरकों का केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा वितरण नहीं किया जाता । राज्य सरकारें अपनी श्रावश्यकताएं सीधा निर्माणकर्ताग्रीं से खरीदती हैं ।

1965-66 के दौरान नाईट्रोजनपूरक उर्वरकों ग्रौर फासफेटिक उर्वरकों की खपत का लक्ष्य निम्न प्रकार है :--

1964-65 की अपेक्षा 1965-66 में नाईट्रोजनपूरक उर्वरकों की उपलब्धि बेहतर होने की सम्भावना है। इसके अरुसार ऐसी आशा है कि 1965-66 में उत्तर प्रदेश के लिए नाईट्रोजन- पूरक उर्वरकों की कुल सप्लाई में बेहतरी होगी।

जहां तक फासफेटिक उर्बरकों का सम्बन्ध है, 1965-66 के लिए राज्य सरकार ने 50,000 टोन्स सुपरफासफेटिक की मांग का अनुमान लगाया है जो सम्भव है पूरी हो जाये।

श्री कपूर सिंह : जहां तक गंजाब का सम्बन्ध है लक्ष्य क्या थे ग्रीर उर्वरक की कितनी मात्रा का संभरण किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि॰ सुब्रह्मण्यम) : यह प्रश्न केवल उत्तर प्रदेश के संबंध में हैं। सुझे खेद है कि मेरे पास पंजाब के ग्रांकड़े नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं ये ग्रांकड़े दे दूंगा।

Shri Yashpal Singh: How the injustice that has been done to **U.P.** is going to be removed? Will this shortage he met in 1965 or **wheat** will be supplied to meet the deficit reduced due to supply of **fertilizer?** How this disparity is sought to be removed?

श्री चि॰ सुम्रह्मण्यम : प्रश्न उर्वरकों के संबंध में है।

अप्रध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को कम माला दी गई है।

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यमः लक्ष्य ग्रीर उपयोग के तंबंध में मैंने जानकारी दे दी है।

Shri Yashpal Singh: Supplies have not been made according to the demands of M.P.

Mr. Speaker: They lagged behind. They did not use.

डा॰ रानेन सेन: क्या यह सच हैं कि भारत के अधिकांश राज्यों में उर्वरकों की कमी है ? यदि हां, तो स्थिति में शीघ्र सुधार करने के लिये क्या ठोस उपाय किये गये हैं ?

श्री चि॰ सुबह्मण्यम : मैं इस से सहमत हूं कि उर्वरकों की कमी है ग्रीर हम पूर्ण मांग देने की कियाति में नहीं हैं। इसके बावजूद भी कि इस वर्ष हम उपलब्धता को 480,000 टन से बढ़ाकर 650,000 टन कर लेंगे, मुझे भय है कि हम केवल 60-65 प्रतिशत मांग पूरी कर सकेंगे।

श्री रंगाः इस से भी कम।

श्री चि॰ सुम्रह्मण्यम: जी हां, हो सकर्ती है इससे भी कम हो। परन्तु कठिनाई यह है कि स्वदेशी उत्पादन उतना नहीं हुम्रा है जितना कि होने की म्राशा थी। इस वर्ष हम 350,000 टन नाईट्रोज़न पैंदा करने का कार्यक्रम म्रारम्भ कर रहे हैं।

श्री क्याम लाल सर्राफ : काश्तकार बार-बार इस बात की शिकायत करते हैं कि उनको उर्वरक जिन कीमतों पर दिये जाते हैं वे बहुत ग्रधिक हैं ग्रीर संसार के ग्रन्य देशों की कीमतों से यहां इनकी कीमतों बहुत ऊंची हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यमः ग्राज प्रश्न ऊंची कीमतों का नहीं है। इस कीमत पर भी हम सारी मांग को पूरा नहीं कर सकत हैं। जब संभरण बढ़ जायेगा तो हमें कीमतों को नीचे लाना होगा। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री विभूति मिश्र: विभिन्न राज्यों को उर्वरक किन सिद्धांतों के ग्राधार पर ग्रावंटित किया जाता है? क्या यह सच है कि कुछ राज्य खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की नजर में ग्रच्छे हैं ग्रीर इसलिये उन्हें बड़ी मात्रा में उर्वरक दिये जाते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: हम ने उपभोग को ध्यान में रखा है। वास्तव में, विवरण बताता है कि गत वर्ष, 1963 में उनके पास लगभग 233,000 टन एमोनियम सलफेट बच रहा था। फिर हम विभिन्न राज्यों के उपभोग को भी ध्यान में रखना है क्योंकि कुछ राज्य अन्य राज्यों को अपेक्षा अधिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वे उर्वरकों के बारे में पहले से जानते हैं।

श्री पें० वेंकटा सुब्बया: क्या सरकार कुछ राज्यों को ग्रधिक माला में उर्वरक दे कर कोई प्रोत्साहन देती है यदि उनका कृषि उत्पादन अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक हो ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: हमें इन सब बातों पर विचार करना है कि खास तौर पर वर्तमान संदर्भ में, जब कि हम सारी मांग पूरी करने की स्थिति में नहीं हैं, हमें इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है कि कौन-कौन से राज्य ग्रधिक उत्पादन कर रहे हैं।

श्री मा० ल० जाघव: बीज बोने के मौसम से पहले उर्वरकों का तंभरण करने के लियें क्या प्रयत्न किये जा रहं हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : खरीफ ऋतु के लिये हमने ग्रब एक कार्यक्रम बना लिया है। राज्यों को उर्वरकों का ग्रावटन करते समय हम इसको ध्यान में रखेंगे।

श्री शिव मूर्ति स्वामी: क्या कोई शिकायत मिली है कि उर्वरक किसान को सरकार द्वारा सीधे ही नहीं दिया जाता है परन्तु यह राज्य विपणन समिति, जिला विपणन समिति, तहसील ग्रीर ब्लाक समितियों द्वारा दिया जाता है, वे सब की सब 10 प्रतिशत मुनाफा लेती हैं जिसके परिणाम-स्वरूप उर्वरक का मूल्य 40 प्रतिशत बढ़ जाता है? इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या इन ग्रिभ-करणों को कम करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ताकि राज्यों द्वारा उर्वरक किसानों को सस्ते दामों पर दिया जा सके।

श्री चि० सुब्रह्मण्यमः जी, हां । यह एक समिति के विचाराधीन है, मुझे ग्राशा है कि वह अपना प्रतिवेदन ग्रगले कुछ महीनों में दे देगी । यह समिति इन सब बातों पर विचार करेगी ।

श्री रंगा: क्या मंत्री महोदय को इसकी सूचना मिली है कि एक भूतपूर्व मंत्री ने, जो कि आन्ध्र प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस समिति का प्रधान है, खुले ग्राम यह शिकायत की है, ग्रौर जो समाचार-पत्नों में भी प्रकाशित हुई थी कि सहकारी स्टोरों द्वारा दिये गये तथा कथित उर्वरक को जब खोला गया तो उसमें पता लगा कि 50 प्रतिशत तक लवण था ग्रौर केवल शेष मात्रा उर्वरकों की थी ?

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यमः मैंने इस प्रतिवेदन को नहीं देखा है। चूंकि माननीय सदस्य ने मुझे इसकी सूचना दी है, मैं निश्चय ही इसकी जांच करूंगा।

राज्यों में सहकारी समितियां

्रशी प्र० रं० चक्रवर्ती: श्री रामेश्वर टांटिया : *1035. < श्री सुबोध हंसदा : श्री स० चं० सामन्त : श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वे कमजोर स्रौर मोरीबंद सहकारी समितियों के परिसमापन के कार्यक्रम की गतिविधि में तेजी लायें ताकि प्राथमिक स्तर पर कृषि ऋण के सहकारी ढांचे को सुव्यवस्थित किया जा सके ;
- (ख) क्या विभिन्न राज्यों में शिथिल सिमितियों की प्रतिशतता का पता लगाने के लिये कोई सवक्षण किया गया है ; ग्रौर
- (ग) क्या राज्यों को विधिक्षम ग्रौर सिक्रिय सिमितियों को वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत होने के केन्द्र का निर्णय बताने वाले निदेश दे दिये गये हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे): (क) से (ग): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जून, 1964 में हुए सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में किए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उन सिमितियों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करें जो चल सकने योग्य हैं तथा जिनके बने रहने की सम्भावना है। शेष सिमितियों में जो शिथिल हैं उन्हें परिसमाप्त किया जाना है ग्रीर जो कमजोर हैं उन्हें मिला दिया जाना है।

- 2. दिसम्बर, 1964 में वार्षिक योजना सम्बन्धी चर्चा के समय सर्वेक्षण कार्य में हुई प्रगति की समीक्षा की गई थी। यह पता चला था कि कुछ राज्य सरकारों ने सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया था जबिक कुछ राज्यों में सर्वेक्षण कार्य ग्रावश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद शुरू किया जाना था। हाल ही में उपलब्ध जानकारी के ग्रनुसार स्थिति यह है कि छः राज्यों में सर्वेक्षण कार्य लगभग पूरा हो गया है ग्रौर दूसरे राज्यों में चल रहा है। परिसमाप्त की जाने वाली शिथिल समितियों की कुल संख्या का पता सर्वेक्षणों के पूरे होने पर चलेगा।
- 3. सरकार उस सहायता के स्केल के पुनरीक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो कि चल सकने की सम्भावना वाली सेवा सहकारी सिमितियों को पूर्णकालिक वैतिनिक सिचव रखने से होने वाली कमी को पूरा करने हेतु 3 से 4 वर्ष की सीमित अविध के शिए जब तक कि वे अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती हैं, दी जानी है।

श्री प्र० रं० चक्कवर्ती: जहाँ तक सहकारी सिमितियों का सम्बन्ध है, राज्यों में ग्रब तक किये सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप किन मुख्य बातों का पता लगा है जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है तथा दोषों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री शिन्दे: जैसा कि विवरण में लिखा है, सर्वेक्षण ग्रारम्भ किया गया है ग्रीर यह ग्रभी तक पूर्ण नहीं हुग्रा है। लेकिन प्रारम्भिक प्रतिवेदन से पता लगता है कि ग्रनेक राज्यों में निष्क्रिय समितियों की संख्या बहुत है। पूर्व तथा उत्तर भारत के कुछ राज्यों में यह संख्या विशेषतः ग्रधिक है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: श्रम मंत्री के उस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए जिसमें सारे भारत में मजदूरों को यह ग्राश्वासन दिया गया है कि उनको ग्रत्यावश्यक वस्तुएं, विशेषत: ग्रनाज सहकारी समितियों के जरिये दिया जायेगा, सहकार विभाग ने इन्हें वित्तीय सहायता देने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की है ?

श्री शिन्दे : कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ विपणन ग्रथवा ग्रामीण सेवा समितियाँ उपभोक्ता वस्तुग्रों का संभरण कर रही हैं, उन्हें कुछ वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

श्री सुबोध हंसदा: मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि इन सिमितियों की नि-कित्रयता के क्या कारण हैं तथा यह कहा कि केवल प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध है। विवरण में यह कहा गया है कि छः राज्यों में सर्वेक्षण पूरा हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस निष्त्रियता के लिये इन सहकारी सिमितियों को वित्तीय सहायता देने की वर्तमान कार्य-व्यवस्था भी उत्तरदायी है ?

श्री जिन्दे: सिमिति ही निष्कियता के लिये मुख्यतः स्थानीय ढांचा तथा नेता उत्तरदायी हैं। जहाँ तक वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है सारे देश में एक समान व्यवस्था है। यदि मान लें कि कुछ क्षेत्रों में एक व्यवस्था, सिमितियों के लिये सुचारू रूप से काम करने में सहायक सिद्ध हुई हैतो कोई कारण नहीं कि वही व्यवस्था अन्य प्रदेशों में सहायक न हो। इसलिये सहकारिता आन्दोलन तथा सहकारिता नेतृत्व का अध्ययन करने से मालूम हुआ है कि मुख्य कारण स्थानीय स्तर पर कमजोर नेतृत्व है?

श्री स० चं० सामन्तः मैं जानना चाहता हूं कि क्या वित्तीय रूप में कमज़ोर ग्रीर नाजुक स्थिति की सहकारी सिमितियों को, जो भविष्य में बन्द की जा रही हैं, प्रोत्साहित करने के लिये बार बार वित्तीय सहायता दी गई थी ?

श्री शिन्दे: कुछ समितियों को वित्तीय सहायता दें गई थी ; लेकिन स्रब पुनरीक्षण किया जा रहा है तथा निष्क्रिय समितियों की वित्तीय सहायता बन्द करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

Shri Vishwa Nath Pandey: In the statement laid on the Table of the House by the Hon. Minister it has been stated that according to the latest available information survey has been completed in six States and in others it is in progress. May I know the reaction of the States where survey has been completed and the names of the States where it is in progress and when the report thereon is likely to be received?

श्रो शिन्दे वास्तव में सर्वेक्षण सब प्रकार से पूर्ण नहीं है; लेकिन प्रारम्भिक सबक्षण पूरा हो गया है तथा राज्यों के नाम हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा,पजाब, केरल, राजस्थान ग्रौर उत्तर प्रदेश। लेकिन केछ राज्यों में सर्वेक्षण भी केवल प्रारम्भिक है। श्री श्रीनारायण दास: मिर्घा सिमिति भी इस मामले पर विचार कर रही ह। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने निष्क्रिय सिमितियों की संख्या का पता लगाया है; यदि हाँ, तो क्या उन्होंने कोई उपाय सुझाये हैं ?

श्री शिन्दे: मिर्धा समिति स्रभी भी उस को सौपे गये विषयों पर विचार कर रही है। उन्होंने स्रभी तक ग्रपना प्रतिवेदन नहीं दिया है। ग्रौर फिर मिर्धा समिति के विचारार्थ विषय वह नहीं हैं जो माननीय सदस्य ने बताये।

श्री गौरी शंकर कक्कड़: प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन के ग्रनुसार ऐसी समितियों की वास्तिवक कार्यकर पूजी तथा शेयर पूजी कितनी है ?

श्री शिन्दे: इसका हिसाब लगाना पड़ेगा ।

Shri Sarjoo Pandey: The hon. Minister said in his statement that a survey is being made to detect the dormant societies with a view to merge them with bigger societies. May I know whether the factors responsible for the dormant conditions of the societies had also been investigated and whether Government have come to know that societies are becoming defunct on account of political interference? If so, the measures taken by Government in this direction?

श्री शिन्देः जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि एक मुख्य कारण स्थानीय नेतृत्व है। ग्रौर भी कारण हैं; उदाहरण के लिये यदि स्थानीय नेतृत्व कमजोर है तो ग्रवश्य ही समितियाँ निष्क्रिय हो जायेंगी।

श्री मान सिंह पृ० पटेल: कृषि संबंधी सेवा सिमितियों, वस्तुओं के राशन भ्रादि जटिल कामों के लिये एक प्रकार की ही सहकारी सिमिति बनाने के बारे में सरकार का क्या निश्चित विचार है?

श्री शिन्दे वास्तव में सिमितियों का स्वरूप ऐसा ही है जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाया।

गेहूं के जहाजों का ग्रन्य स्थानों को भेजाजाना

+ *1037. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री चांडक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि :

- (क) क्या फरवरी, 1965 में सरकार ने पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना की थी कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत पाकिस्तान द्वारा आयात किये गये अमरीकी गेहूं से लवे जेहांजों को भारतीय पत्तनों को भेज दिया जायें;
 - (ख) प्रार्थना के परिणामस्वरूप भारत को कितना गेहूं दिया गया ;
- (ग) क्या भारत सरकार ने भारत में खाद्य स्थिति में सुधार होते ही पाकिस्तान को गहुं वापस करने का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया है; ग्रीर
- (घ) पाकिस्तान ने जो गेहुं ग्रायात किया है उसे भारत भेजने के करार की विशिष्ट शत क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी, हां।

- (ख) 37,117 टन ।
- (ग) भारत सरकार पाकिस्तान सरकार के अप्रैल, 1965 के अन्त तक गहूं वापस करने के सुझाव को मान गयी।
 - (घ) करार की मुख्य शतें संक्षिप्त रूप में नीचे दी जाती हैं:
 - (1) बदलने के खर्च का भुगतान भारत ग्रमरीकी सरकार द्वारा पी० एल० 480 के ग्रन्तर्गत भारत के लिए ग्रधिकृत निधि में से करेगा।
 - (2) गेहूं के मोड़ने से सम्बन्धित प्रासंगिक खर्चे पाकिस्तान सरकार द्वारा दिये जायेंगे स्त्रीर माल के बदलाव के बारे में इसी प्रकार के खर्चे भारत सरकार द्वारा दिये जायेंगे।
 - (3) मोड़े गये जहाजों के माल का भाड़ा भारत सरकार द्वारा बहन किया गया है स्रीर माल के बदलाव का भाड़ा पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया जाएगा। पाकिस्तान सरकार द्वारा देय स्रधिक भाड़ायदि कोई हो तो उसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाऐगी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत ने पहले भी कुछ ग्रवसरों पर पाकिस्तान को खाद्य-फसलें दी थीं, यदि हां, तो क्या यह भारत द्वारा पहले प्रकट की गई सद्भावना का बदला है ?

स्राद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): मुझे नहीं मालूम यदि हमने पाकिस्तान को ग्रनाज दिया है; लेकिन हमने ग्रन्य देशों को ग्रवश्य दिया था।

भीप्र० रं० चक्रवर्ती: मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को छूट थी कि बदले में खाद्य-फसलें देने की बजाय पिकस्तान को कोई ग्रौर वस्तु दे दें?

श्री चि० सुबह्मण्यम: नहीं, श्रीमान्; यह गेहूं पाकिस्तान को पी० एल० 480 के अन्तर्गत भेजा जा रहा था और हमने इसे यहां संकट के कारण मंगा लिया। अतएव, उनको बदले में पी० एल० 480 के अन्तर्गत प्राप्त गेहूं ही दिया जायेगा।

श्री दी॰ चं॰ हार्मा: माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से ऐसा मालूम होता है कि यह विशेष तथा निश्चित नियमों के अन्तर्गत एक साधारण व्यापारिक सौदा था। क्या सरकार को यह मालूम है कि पाकिस्तान ने इसको भारत के असंख्य भूखें व्यक्तियों की सहायता के लिए मानवोचित कार्य का रूप दे दिया; यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा रेडियो से तथा समाचार-पत्नों में किये गये इस प्रचार के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यम : यह नियमित व्यापारिक सौदा नहीं है ; गेहूं का जहाज जो पाकिस्तान जा रहा था भारत की ग्रोर मोड़ दिया गया था। हमें यह मानना पड़ता है कि उस हद तक पाकिस्तान हमारी कठिनाइयों पर विशेषतः मुझ पर दयालु रहा है। मैं नहीं समझता कि हमें यह स्वीकार नहीं करना चाहिये।

Shri Onkar Lal Berwa: May I know whether the wheat was directed at the instance of America or on our request?

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यम: हमने प्रार्थना की तथा ग्रमरीका की सहमित से पाकिस्तान द्वारा मेह भारत भेजा गया।

Pay Scales of Employees of Khadi and Village Industries Commission

Shri Madhu Limaye: *1038. ≺ Shri Bagri: Shri Kishen Pattnayak:

+

Will the Minister of Social Security be pleased to state:

- (a) whether Government have received the report of the committee appointed to look into the pay-scales of employees of Khadi Commission;
- (b) if so, whether the said committee has given any suggestion regarding the date from which recommendations of the Pay Commission should be implemented; and
- (c) the total additional amount that Government will have to pay as arrears to the employees, if that suggestion is accepted?

विध मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) समिति की रिपोर्ट खादी और ग्रामोद्योग स्रायोग को प्राप्त हो गई है स्रीर उस के विचाराधीन है।

- (ख) समिति ने 1-7-59 से वेतन की दरों में संशोधन करने की सिफारिश की है।
 - (ग) श्रायोग द्वारा लगभग 12 लाख रुपये देने होंगे।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, Sir, in a written reply to my question on 23rd March, it was stated that since the Khadi and Village Industries Commission is an autonomous body, the recommendations of the Pay Commission as such could not be made applicable. It was also stated that the decision to give effect to these recommendations w.e.f., 1963 was taken jointly by the Commission and the Government. On one hand Govrnment plead that recommendations pertaining to them can not be made applicable to the Commission, on the other later on it is said that the decision to give effect to these recommendations has been taken jointly by the Government and the Commission. My point is when their subcommittee decided to give effect to these recommendations w.e.f. 1959, why the Government did not implement it and a reply far from the factual position was given to us?

श्री जगन्नाथ राव : इसमें कोई भी श्रसंगत बात नहीं है। जहां तक 23 मार्च, के प्रश्न के उत्तर का सम्बन्ध है, वह वेतन श्रायोग की सिफारिशों की कियान्वित के बारे में था। उत्तर यह दिया गया था कि खादी श्रायोग कैसे दूसरे वेतन श्रायोग की सिफारिशों को कियान्वित करने के लिए बाध्य नहीं है, जो केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू

होती हैं। लेकिन यह प्रश्न खादी तथा ग्रामोद्योग ग्रायोग द्वारा नियुक्त वेतन पुनरीक्षण समिति के बारे में है। इस समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है ग्रौर सिफारिशों को 1 जुलाई, 1963 से लागू करने का निश्चय किया गया है।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, my question was whether this decision was taken jointly by the Khadi and Village Industries Commission and the the Government or solely by Government. The Commission as well as their Committee had suggested the implementation of the recommendations w.e.f. 1959 and the payment of arrears to the employees arising as a result thereof. But now we are informed that though the Committee had suggested, this decision was taken jointly by the Commission and the Government since it is an autonomous body.

श्री जगन्नाथ राव: इस वेतन पुनरीक्षण सिमिति ने 1 जलाई, 1959 से वेतन-कमों के बदलने का सुझाव दिया था । खादी तथा ग्रामोद्योग ग्रायोग के प्रधान ने वित्त मंत्री से विचार-विमर्श किया था । उनका ध्यान इस बात की ग्रोर दिलाया गया था कि 1 जुलाई, 1959 से वेतन-कमों के बदलने से ग्रायोग पर भारी वित्तीय भार पड़ेगा । ग्रतएव, यह निर्णय किया गया कि यह सिफारिश 1 जुलाई, 1963 से लागू की जाये ग्रौर यह भी निर्णय किया गया था कि 1-7-1959 से कर्म चारियों को ग्रनुग्रहात एक मुश्त रकम दे दी जाये ।

Shri Kishen Patanayak: My question is why a lump sum payment was made. Had the arrears been calculated properly these would have amounted to Rs. 20 lakhs instead of Rs. 12 lakhs?

श्री जगन्नाथ राव: जैसा मैंने कहा प्रश्न श्रितिरिक्त बित्तीय भार उठाने की क्षमता का था। श्रतएव, यह निश्चय किया गया कि कुछ करना ही है तथा श्रनुग्रह के रूप में उनको इकर्ठी एक राशि दे दी जाये।

खड़ी फसलों को नुकसान

श्री लखमू भवानी :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सैवक यादव :
श्री वागड़ी :
श्री रघुनाथ सिंह :

श्री युद्धवीर सिंह :

श्री श्री नारायण दासः

| श्री श्रोंकार लाल बेरवा ः | श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती ः | श्री सरजू पांडेय ः

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि 19.65 में फरवरी, मार्च ग्रीर ग्रग्नैल ुके शरू में वर्षा ग्रीर श्रोलों के कारण खड़ी फसलों को काफी नुक्सान पहुंचा है; ग्रीर
 - (ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में कितना-कितना नुक्सान हुग्रा है।

खाद्य तया कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चह्नाण): (क) ग्रब तक प्राप्ति रिपोर्टों से पता चला है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार महाराष्ट्र, ग्रान्ध्र प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा ग्रौर मध्य प्रदेश के राज्यों में खड़ी फसलों को कुछ हानि हुई है।

(ख) हानि के माल्रा सम्बन्धी ग्रनुमान ग्रभी उपलब्ध नहीं हैं। किसी समय जून, 1965 में जब रबी फसलों के उत्पादन के ग्रन्तिम ग्रनुमान उपलब्ध होंगे तभी हानि का कुछ ग्रन्दाजा लगाया जा सकेगा ।

श्री श्रीनारायण दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन राज्यों में से किसी में इस प्रकार की प्राकृतिक विपदा के मामले के लिए किसानों को मुग्रावजा देने की व्यवस्था की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): कोई मुग्रावजा नहीं; लेकिन मुझे बताया गया है कि राज्य सरकारें लगान में छूट देती हैं।

श्री श्रीनारायण दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे राज्यों की सहायता करने का विचार कर रही है, जो फसल बीमे की व्यवस्था करेंगी ?

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यमः फसल बीमा प्रणाली विचाराधीन है। जैसा मैं पहले एक बार कह चुका हूं हमारा विचार पंजाब में एक प्रारंभिक योजना ग्रारंभ करने का है।

श्री रघुनाथ सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि सारे भारत को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष इन विपदाग्रों के कारण गेहूं की फसल के बारे में क्या संभावना है ? क्या पिछले वर्ष की तुलना में ग्रधिक फसल होगी ?

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यमः पिछले वर्ष उत्पादन लगभग 97 लाख टन हुआ था। इस वर्षे 115 लाख टन उत्पादन होने की श्राशा है।

Shri Buta Singh: Recently in Punjab the entire wheat crop was destroyed by a hail-storm. Inspite of this the State's Minister said that there was not much damage. I want to know how this assessment was made.

Mr. Speaker: The Central Government have no separate machinery of its own for this purpose. Whatever information was received from the State Government, he has given here.

Shri Jagdev Singh Siddhanti: The State's Ministry furnished, an incorrect report and heavy damage has been caused. May I know

whether Central Government will give any compensation for and if they do not want to give any relief let them at least protect the cultivators against the fall in the price of wheat?

Mr. Speaker: This is a suggestion.

श्री भागवत झा श्राजाद : माननीय मंत्री ने लगान में छूट का उल्लेख किया । क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि ऐसे मामलों में लगान में छूट से स्रिभिप्राय केवल यह होता है कि लगान की वसूली स्थिगित कर दी जाती है तथा किसान को ग्रपनी हानि पूरी करने का स्रवसर नहीं मिलता । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि ऐसी प्राकृतिक विपदा के मामले में भूमि का लगान बिल्कुल माफ कर देना चाहिये तथा ग्रगले वर्ष उसकी वसूली नहीं होनी चाहिये?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: मैं मद्रास के बारे में कह सकता हूं। वहां वसूली स्थिगित करने जैसी बात नहीं है। यह क्षिति पर निर्भर करता है। यदि बहुत भारी क्षिति हो तो सारा लगान माफ कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि ग्रन्य राज्यों में भी ऐसी ही प्रणाली होनी चाहिये।

Shri Yashpal Singh: The Government officials have expressed their inability to visit all the places hit by the hail-storm. So, my point is then what relief will be given to them by the Government?

श्री चि० सुप्रवृह्मण्यमः यह तो राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है ग्रीर मैं नहीं समझता कि मैं इसका उत्तर दे सकता हूं।

Shri Yudhvir Singh: On the one hand, Government have stated that standing crops were damaged in some of the States due to hailstorm, but that the assessment of damage had not been made while on the other hand, they say that assessment will be made only after the harvest had been reaped. May I know the method proposed to be adopted by Government so as to make an assessment of the damage so caused?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : राज्यों के राजस्व ग्रधिकारी ही ऐसी हानि का ग्रनुमान लगाते हैं।

Shri Yudhvir Singh: If my question was to be answered in this way; why it was at all admitted?

Mr. Speaker: The centre had no other method of assessment except to call for a report from the states.

श्री कपूर सिंह : माननीय सदस्य का कहना है कि फसल ग्राने के बाद ग्राप रिपोर्ट नहीं मांग सकते हैं। क्योंकि ग्राप को उस समय विदित नहीं हो सकता कि हुग्रा क्या था।

ग्रम्यक्ष महोदय: उन्होंने फसलों का ग्रनुमान पहले ही लगा लिया होगा, फसल कटने पर वे यह पता लगा सकते हैं कि वास्तविक उत्पादन कितना हुग्रा तथा यदि कोई हानि हुई तो कितनी ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The Punjab Minister had stated that no damage had been caused to the crops.

Shri Sarjoo Pandey: The Minister has stated that some States have suffered loss due to hail-storm and rains, but he has no information about the actual loss so suffered. May I know whether for that reason Government propose to increase wheat quota for deficit States?

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यम : हम कमी वाले क्षेत्रों में ग्रागामी वर्ष से पहले उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। किन्तु उन्हें उस सीमा तक ही ग्रधिक कोटा दिया जायेगा जितना वहां नुकसान हुग्रा है।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : जिन राज्यों में वर्षा तथा श्रोलों से फसल नष्ट हो गई है वहां भू-राजस्व में छूट देने के स्रतिरिक्त किसानों को स्रपनी खेती का कार्य करने के लिए "तकावी" ऋण तथा ग्रन्य प्रकार की कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

Dr. Ram Manohar Lohia: According to official figures 30,000 people died during last year due to famine. May I know the arrangements being made to have proper distribution during August next so as to prevent such deaths?

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यम: मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस प्रकार के आंकड़े कहीं प्रकाशित किये गये हैं। मेरी जानकारी के अनुसार अगस्त 1964 में भूख से कोई व्यक्ति नहीं मरा।

Dr. Ram Manohar Lohia: I have already said in my speech that in August 1963 death rate was 12:8 and that the death rate in August, 1964 was 12:7. These are the figures of 250 Municipal bodies. But the hon. Minister does not pay any attention to it. These are their own figures.

Mr. Speaker: You may write to me about it in detail.

श्री कपूर सिंह : पंजाब में किसानों को लगान में छूट देने के अतिरिक्त, जैसा कि वहां किया जा रहा है, क्या सरकार उपयुक्त मामलों में प्रतिकरात्मक अनुदान देने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यम : यह राज्य सरकार का काम है। यदि वे इस बारे में कोई अस्ताव रखेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे।

Shri Vishwa Nath Pandey: The hon. Minister has stated that he has so far not got the actual figures of damage suffered by the States. May I know whether Government have ascertained position from State Governments as to the area and the nature of crops affected by the hail-storm?

श्री चि० सुबह्यपग्रम : जहां तक ग्रोलों से हुई हानि वाले क्षेत्र का सम्बन्ध है हमें इस बारे में राज्यों से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। फसलों को होने वस्त्री हानि का ग्रनुमान फसल कटने के बाद ही लग सकता है।

Shri Rameshwaranand: On a point of order, may I know how the hon. Minister can assess the damage after the harvest season is over?

ग्रनाज संग्रह प्रणाली

+ श्री विश्वनाथ पांडेय : श्री श्री नारायण वास : श्री कनकसबै : श्री तुला राम :

क्या खाद्य तया कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने देश में अनाज के संग्रह तथा वितरण की पद्धित की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की है जिसमें स्वीडिश विशेषज्ञ भी शामिल हैं;
 - (ख) यदि हां, तो उस समिति में कौन-कौन सदस्य होंगे; ग्रौर
 - (ग) समिति कब तक अपना प्रतिवेदन पेश करेंगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी, हां।

(ख) दल में तीन भारतीय ग्रौर तीन स्वेडन के विशेषज्ञ होंगे । दल के भारतीयः सदस्य इस प्रकार हैं :-

श्री के० डी० एन० सिंह—उपमहानिदेशक (खाद्य)
डा० एस० वी० पिंगले-निदेशक, संग्रहण तथा निरीक्षण
श्री वो० मुथाचन—ग्रपर मुख्य इंजीनियर,
केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग।

दल के स्वीडिश विशेषज्ञ निम्न प्रकार हैं:---

श्री टोर ग्रोलवेजर—(संग्रहण विशेषज्ञ) श्री ग्रगने निबर—(संग्रहण विशेषज्ञ) श्री ग्रोल्लर लंडनमार्क —(सस्य विज्ञानी)

(ग) ग्राशा है कि भ्रध्ययन दल दिसम्बर, 1965 के भ्रन्त तक श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ।

Shri Vishwa Nath Pandey: May I know the places where the study team has examined this system?

Shri D. R. Chavan: It has yet to examine the system.

Shri Vishwanath Pandey: May I know the reasons for inviting only the Swedish experts when the foodgrains procurement policy pursued in America and Australia was admitted to be the best.

श्री दा० रा० चह्नाण: स्वीडन की सरकार ने भारत को अनाज संग्रह प्रणाली की सुविधा श्रों का विकास करने के लिये स्वयं सहायता देने की इच्छा प्रकट की थी तथा वे हमारी सहायता करने के लिये तैयार हैं।

श्री श्रीनारायण दास: क्या इस बीच इस कार्य के लिये कोई दूसरी समिति भी नियुक्त की गई थी श्रीर यदि हां, तो क्या समिति द्वारा दिये गये सुझावों को कियान्वित किया गया है ?

श्री दा॰ रा॰ चह्वाण: मैं समझता हूं कि ग्रौर कोई दूसरी समिति नियुक्त नहीं की गई।

श्री रंगा: एक सिमिति ने तो रिपोर्ट दी थी । सरकार एक स्थायी तथा चालू संस्था समझी जाती है । मंत्री बदल जाने पर सरकार तो नहीं बदलती ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि॰ सुब्रह्मण्यम): संग्रह सुविधाग्रों के बारे में रिपोर्टें मिली हैं किन्तु किसी विशेष परियोजना की रूपरेखा तैयार नहीं की गई है। सिमिति विभिन्न स्थानों को चुनने तथा परियोजना को कार्यरूप देने के लिये विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिये नियुक्त की गई है।

श्री पु०र० पटेलः हम संग्रह तथा वितरण के संबंध में विशेषज्ञों की सलाह ले रहे हैं। क्या इस देश में ग्रनुभव ग्रथवा जानकारी की कमी है ?

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यमः हम भारत में 'साइलो' के रूप में नये किस्म के संग्रह भंडार बनाना चाहते हैं। भारत में ग्रभी तक 'साइलो' नहीं बनाये गये हैं। ग्रतः हमें इस तंबंध में नई जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी।

श्री रघुनाथ सिंह: क्या इस दल को उष्ण जलवायु के बारे में ग्रनुभव है तथा क्या उन्होंने कहीं उष्ण जलवायु में कार्य किया है?

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यम: यह 'साइलो' बनाने से संबंधित है चाहे वह उष्ण जलवायु में हो ग्रथवा शीत जलवायु में। हमें बाद में ग्रनाजों को सुरक्षित रखने के लिये रसायनिक कीटनाशि ग्रादि का उपयोंग जैसे ग्रन्य उपाय ग्रपनाने होंगे ग्रीर उनका पृथक् ग्रध्ययन करना पड़ेगा।

Shri Rameshwaranand: We always seek the assistance of foreigners while starting every project. May I know whether we did not know previously how to store grains? Why the foreign experts have been consulted in this regard?

श्राध्यक्ष महोदय : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दिया जा चुका है। प्रश्न के केवल दूसरे भाग का उत्तर दिया जाये।

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यम: मैं बता चुका हूं कि यह अनाजों को साइलो में बड़ी मात्रा में सग्रह करने के लिये नये तरीके से संबंधित है। गांवों में थोड़ी मात्रा में अवश्य अनाज का संग्रह किया जाता है किन्तु हम बड़ी मात्रा में अनाजों का संग्रह करना चाहते हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया: क्या यह सिमिति सहकारी विभाग, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा भांडागार निगम जैसी संस्थात्रों द्वारा अपनाई जा रही द्विकृति संग्रह कार्यवाहियों के प्रश्न पर भी विचार करेगी और यदि हां, तो इस संबंध में क्या सिफारिशें की जायेंगी ?

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यमः यह समिति पत्तन क्षेत्रों में साइलो बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। क्योंकि वहां पर टैकरों से भारी मात्रा में आयात किया जाने वाला सामान उतारा जाता है। यह आन्तरिक संग्रह प्रणाली पर विचार नहीं करेगी।

श्री हिम्मतिसह जी: कांडला पत्तन में एक साइलो बनाने का प्रस्ताव था। क्या यह भी इस योजना में शामिल किया जाएगा?

Shri Onkar Lal Berwa: May I know whether it is proposed to have plastic storage system?

श्री चि० सुब्रह्मण्यमः हमारे यहां प्लास्टिक स्टोर बहुत छोटे पैमाने पर बनाये गए हैं श्रीर वह बहुत श्रच्छा कार्य कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know the time by which this work will be undertaken, how much it will cost and when it will give full benefit?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: रिपोर्ट दिसम्बर, 1965 तक प्राप्त हो जायेगी। इसके तुरन्त बाद ही कार्य किया जाएगा।

श्री ल० ना० विद्यालंकार: इस प्रकार की संग्रह प्रणाली से लागत में कितनी बचत होने की ग्राशा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: अच्छी तरह संग्रह न करने से अनाज की 3-4 प्रतिशत माता का नुकसान होने का अनुमान है। अच्छी तरह संग्रह करने से यह बचत हो जायेगी।

श्री भागवत झा स्राजाद: मंत्री महोदय ने बताया है कि स्वीडन सरकार द्वारा सहायता देने की इच्छा व्यक्त की जाने पर उससे सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। इस विशेष परियोजना के संबंध में भारत सरकार तथा स्वीडन की सरकार के बीच यदि कोई वित्तीय समझौता हुग्रा है तो वह क्या है?

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यमः इस परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा, स्वीडन की सरकार द्वारा, ऋण के रूप में दी जायेगी।

श्री विश्वनाथ राय: सरकार द्वारा संग्रह के बारे में स्थायी निर्णय करने के बाद भी इसे कार्य रूप देने में इतना विलम्ब क्यों हुग्रा?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि माननीय सदस्य किस विलम्ब का उल्लेख कर रहे हैं। हमने संग्रह प्रणाली के प्रश्न पर विचार करने के लिये हाल में यह दल नियुक्त किया। दल की रिपोर्ट प्राप्त होते ही उसे कार्यरूप देने का काम आरम्भ किया जायेगा। जहां तक आंतरिक संग्रह प्रणाली का सम्बन्ध है हम कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं।

श्रीमती यशोदा रेंड्डी: इस समय संग्रह संबंधी क्या प्रणाली ग्रपनाई जा रही हैं तथा देश में अच्छी संग्रह प्रणाली न होने से कितनी हानि हो रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: इस समय हम बोरों में अनाज भर कर संग्रह करते हैं। इससे बोरों पर तथा उनकी ढुलाई पर अतिरिक्त खर्च होता है इसकी तुलना में अधिक मात्रा में एक साथ संग्रह करने की प्रगाली अधिक सरल है।

Shri Buta Singh: May I know the nature of assistance expected from the Swedish Government apart from the advice to be given by them?

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यम: इस पर रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

Shri Sarjoo Pandey: Whenever such problems arise, some committees are formed by the Cabinet and the members of such committee are given T.A. and D.A. allowwances. May I know the difficulties of Government in the matter storage and distribution of food grains for which this committee has been appointed?

श्री चि॰ सुब्रह्मकण्यमः ग्राजकल गेहूं 'टैंकरों' में भारी मात्रा में लाया जाता है। इसे पत्तन में ही उतारना तथा संग्रह करना पड़ता है। इस समय हमें गेहूं उतारने के बाद बोरों में भर कर पत्तन से तुरन्त ग्रन्य स्थानों को भेजना पड़ता है जिससे कठिनाई होती है। इसीलिये हम गेहूं को पत्तनों पर ही संग्रह कर ने के बाद में सुविधा से भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं।

फार्म-उत्पादों की कीमतों सम्बन्धी प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बया: श्री प्र० चं० बरुग्रा : *1041. { श्री रवीन्द्र वर्मा : श्री कृ० चं० पन्त : श्री म० रं० कृष्ण :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) फार्मों के उत्पादकों की कीमतों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिये अमरीकी विशेषज्ञों का जो दल छः महीने पूर्व नई दिल्ली आया था क्या उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;
 - (ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; स्रौर
 - (ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्नाण): (क) से (ग). ऐसा कीई भी विशेषज्ञ, जिसकी प्रकृत में ग्रिभिकल्पना की गयी है, भारत में नहीं ग्राया । तथापि, यू० एस० ए० ग्राई० डी० के तत्वाधान में कुछ विशेषज्ञ जिसमें संयुक्त राज्य ग्रमेरिका के वस्तु उधार निगम के विशेषज्ञ भी थे ग्रगस्त से नवम्बर, 1964 में भारत ग्राये ग्रौर उन्होंने खाद्य निगम ग्रौर उसके कार्य चालन के कुछ पहलुग्रों के बारे में भारत सरकार को परामर्श दिया । इन विशेषज्ञों ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी ।

श्री पें ॰ वेंकटा सब्बय्या: कृषि वस्तुग्रों के निम्नतम भाव निर्धारित करने में इस प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत क्या सरकार ने उसकी यात्रा का पूरा लाभ उठाया है ? करके ग्रमरीक में इन भावों को निश्चित करने के बारे में इस दल का क्या ग्रनुभव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : प्रक्त के मुख्य उत्तर में बताया गया है कि इन लोगों ने खाद्य निगम के संगठन तथा उसके कार्यों की जांच की थी। हम ने निम्नतम मूल्यों के लिये कृषि मूल्य ग्रायोग नियुक्त किया है जो भावों को निर्धारित करने के बारे में विचार करेगा।

श्री पें० वेंकटासुब्ब्या: उन के साथ हुई बातचीत के दौरान क्या सरकार को मालूम हुग्रा है कि विभिन्न कृषि वस्तुग्रों के मूल्य निर्धारित करने में इनका कितना ग्रनुभव है क्योंकि कृषि मूल्य ग्रायोग ने इस ग्राधार पर मूल्य निर्धारित किए हैं ? क्या किसानों के प्रतिनिधि भी श्रायोग में हैं? इस सम्बन्ध में विदेशों के बारे में उन के क्या ग्रनुभव हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: कृषि मूल्य ग्रायोग में केवल तकनीकी विशेषज्ञ ही लिये जाते हैं किन्तु उत्पादन लागत का मूल्यांकन करने के लिए वास्तविक रूप से खेती करने वाले किसान उनकी सहायता करते हैं। इसके लिए हम ने ऐसे किसानों की एक तालिका बनाई है जो भाव निर्धारित करने में मूल्य ग्रायोग की सहायता करेंगे ।

श्री पु० र० पटेल : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि जो लोग ग्रमरीका से ग्राये थे उन्होंने कुछ सलाह दी थी । उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को लाभ प्रद मूल्य देने के संबंध में प्रतिनिधि मंडल ने क्या सलाह दी है, ग्रीर क्या उस ने यह भी सलाह दी है कि भारत में भी मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में कृषक-संगठनों से उसी प्रकार सहयोग किया जाए जिस प्रकार ग्रमरीका में कृषि संगठनों से लिया जाता है तथा भारत में किसानों को उनकी ग्रावश्यकता के ग्रनुसार पूरा ऋण दिया जाय ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यमः यह स्पष्ट है कि बिना इन बातों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती है । हम भी इन्हीं बातों को कार्यरुप देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा: क्या सरकार स्त्रमरीका की पद्धति के समान ही कृषि मूल्यों में फसल के लिए तथा स्त्रन्य कामों के लिए कृषकों को सहायता देगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: हम ग्रपने देश में ग्रमरीका का ग्रनुसरण नहीं कर सकते। वहां केवल 7 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। इस प्रकार यह सहायता ग्रमरीका की 93 प्रतिशत जनता देती है। िकन्तु भारत में ग्रधिकांश लोग खेती करते हैं ग्रतः प्रश्न यह उठता है कि कौन किसको सहायता दे?

श्री क० ना० तिवारी: क्या विशेषज्ञ दल ने भारत में उत्पादन लागत का श्राध्ययन किया स्रीर यदि हां, तो इस के बारे में उनका क्या विचार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उन्होंने उत्पादन मूल्य के बारे में विचार नही किया । इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए कृषि स्रायोग नियुक्त किया गया है ।

Dr. Ram Manohar Lohia: May I know whether Government have received any recommendations regarding a possible ration between the agricultural prices and industrial prices; and if so, the action taken by the Government thereon?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कृषि मूल्य श्रायोग के निदष पदों में श्रौद्योगिक मूल्यों को ध्यान में रख कर मूल्य निर्धारित करना तथा इन दो मूल्यों के बीच समानता बनाये रखना भी शामिल है ।

Dr. Ram Manohar Lohia: I could not hear whether these Indus-

trial prices will remain high?

Mr. Speaker: He has replied that one of the terms of reference is that Agricultural prices should be fixed in view of the Industrial prices.

Dr. Ram Manohar Lohia: In other words it has increased.

श्री ग्रत्वारेस : क्या कृषि मूल्य ग्रायोग लाभप्रद मूल्यों के बारे में सिफारिश करते समय उत्पादन पूंजि ग्रादि पर भी विचार करेगी ?

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यम : जी, हां ।

Shri Yashpal Singh: May I know whether this team has made any recommendations to the effect that farmers should also be made entitled to share the profits earned by the Government on foodgrains due to higher selling prices during the course of a year as these foodgrains are procured by the Government at a cheaper rate from the farmers?

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यम : इस सम्बन्ध में इस दल ने कोई सिफारिश नहीं की है।

श्री रंगा : क्या सरकार की नीति कृषि मूल्यों तथा ग्रौद्योगिक मूल्यों के बीच यथाशी घ्र समानता लाने की है ?

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यमः सरकार की यही मूल नीति है।

Rabi Crop

*1042. Shri Yudhvir Singh:

*Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of Fod and Agriculture be pleased to state:

- (a) whether a proper evaluation of Rabi crop has been made by Government upto the 15th April, 1965;
- (b) the estimated quantity of foodgrains likely to be produced; and
 - (c) the extent to which it would help to solve the food problem?

खाद्य ग्रीर कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चहाण): (क) से (ग) तक जी नहीं । सहसा चुने गये खेतों पर वास्तिविक फसल कटाई के ग्राधार पर ही रबी की फसल का ठीक मूल्यांकन करना सम्भव हैं किन्तु उसके नतीजें ग्रभी तक राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर भी वर्तमाद संकेतों से पता चला है कि 1964-65 के दौरान मुख्य रबी खाद्यान्त्रों का उत्पादन गत वर्ष के उत्तादन की ग्रपेक्षा 15 प्रतिशत ग्राधिक होने की संभावना है । चालू वर्ष में खाद्यान्त्रों के ग्रधिक उत्पादन से खाद्य स्थित के सुधार में सहायता मिली है ।

Shri Yudhvir Singh: Every year it is seen that when there is a poor crop or it is damaged due to heavy rains or floods, it is an excuse to the Government under the cover of Nature's Wrath and when there is a rich crop it is only due to the creditable performance of Government by way of their advancing loans to farmers or providing other means of assistance to them. May I know whether this 15 per cent higher production is due to assistance extended by the Government to the farmers or it is the result of their own efforts and nature's favour? May I also know whether Government are prepared to lay on the

Table of the House a copy of the report showing full details of the crop after the results become available?

श्री चि० सुश्रह्मण्यम : इसकी उल्टी बात सच थी । जब कभी उत्पादन में कमी होती है, तो सरकार पर ग्रारोप लगाया जाता है ग्रीर जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो यह कहा जाता है कि यह प्रकृति के कारण हुग्रा है, इसलिए जब कभी भी उत्पादन में वृद्धि होती है, तो सरकार को उसका श्रेय नहीं मिलता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पटसन की खेती का क्षेत्रफल

*1036. $\begin{cases} श्री रामचन्द्र उलाका : श्री घुलेश्वर मीना : श्री रामचन्द्र मिलक :$

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 1964-65 में उड़ीसा में कुल कितने एकड़ (भूमि में पटसन की खेती की गई;
- (ख) उक्त ग्रवधि में उड़ीसा में कुल कितना पटसन पैदा हुग्रा;
- (ग) क्या पिछले वर्षों की अपेक्षा पटसन का उत्पादन कम हुआ है; और
- (घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य ग्रीर कृषि मंत्री (श्री चि॰ सुब्रह्मण्यम) : (क) 0.55 लाख हैक्टेयर्स ।

- (ख) 4.15 लाख गांठ (ग्रनन्तिम)।
- (ग) 1964-65 में उत्पादन 4.15 लाख गांठें हुम्रा जबिक 1963-64 में उत्पादन 4.71 लाख गांठें हुम्रा था ।
- (घ) 1964-65 में उत्पादन कम होने का सामान्यतया कारण यह है कि फसला के उगने के समय वर्षा कम हुई ।

कृषि उत्पाद मूल्य श्रायोग

श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
*1045. ﴿ श्री किशन पटनायक :
श्री दे० जी० नायक :
श्री पु० र० पटेल :
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल में देनियुक्त किये गये कृषि उत्पाद मूल्य ग्रायोग काः ग्रामाज के भाव सम्बन्धी प्रतिवेदन मिल गया है ;

- (ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; ग्रौर
- (ग) यदि नहीं, तो सह संभवतः कब तक मिल जायेगा ?

खाद्य ग्रौर कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) जी नहीं।

- (ख) प्रश्न ही नहीं होता ।
- (ग) इसके लिये कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है।

श्रनाज का उतारा जाना

*1046. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

- (क) क्या मद्रास बन्दरगाह में ग्रनाज उतारने की ठेका-प्रणाली समाप्त करने के लिए सिद्धांत रूप में कोई समझौता हो चुका है ;
- (ख) क्या बम्बई की तरह वहां भी जहाजों से माल उतारने का काम विभाग को सौंप देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;
- (ग) इस नई व्यवस्था से उन कर्मचारियों को जिन्हें बम्बई की दरों की अपेक्षा कम दरों पर मजूरी मिलती है, कितना लाभ होगा ; ग्रौर
 - (घ) क्या समझौते की शतों में ग्रावश्यकता पड़ने पर नये कर्मचारियों को किराये पर लाने की भी कोई व्यवस्था है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) जो हां । तथापि , फिल-हाल केवल जहाज से माल उतारने ग्रर्थात् (1) घाट पर बोरियां भरनी ग्रौर सिलनी ग्रौर (2) वैगनो/ट्रको में लादने से सम्बन्धित कार्यों के बारे में ठेका पद्धति समाप्त की जा रही है ।

- (ख) हां, किन्तु केवल अपर वर्णित सीमा तक ।
- (ग) मजदूरों को कमाई तथा उन के द्वारा उठाये गये लाभों में विभागीयकरण से पूर्व की तुलना में कमाई ग्रौर लाभों में पर्याप्त वृद्धि होने की ग्राशा है।
 - (घ) जो, हां।

चावल को सहकारी ृीमलें

श्री श्रीनारायण दास:
*1047. श्री रामेश्वर टांटिया:
श्री स० चं० सामन्त:
श्री सुबोध हंसदा:

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र में चावल की ग्राधुनिक सहकारी मिलें स्थापित करने ग्रौर उनको चलाने के लिये भारतीय तकनीशनों के प्रशिक्षण की दिशा में ग्रभी तक क्या प्रगति हुई है; ग्रौर

(ख) राष्ट्रोय सहकारो विकास निगम में चावल की इन सहकारी मिलों को ऋण के रूप में कितानो राशि मंजूर को है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीब॰ सू॰ मित): (क) सहकारी क्षेत्र में स्थापित को जाने वाली पांचों ग्राधुनिक चावल मिलों की मशीनें विदेश से ग्राचुकी हैं ग्रीर तीन यूनिटों की इमारतों के निर्माण का कार्य चल रहा है । ग्राशा है कि शेष दो यूनिटों की इमारतों का निर्माण कार्य शोध हो शुरू हो जाएगा । जहां तक भारतीय तक नीशनों के प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) फोर्ड फाउन्डेशन ग्रीर केन्द्रीय खाद्य तथा टैक्नोलीजोकल ग्रनुसंधान, संस्थान, मैसूर के परामर्श से एक योजना तैयार कर रहा है ।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सम्बन्धित राज्य सरकारों को इन मिलों की स्थापना हेतु सहकारी समितियों को सहायता देने के लिये ऋण तथा उपदान के रूप में 103.25 लाख रुगए (86.50 लाख रुपये ऋण ग्रौर 16.75 लाख रुपए उपदान के रूप में) की कुल राशि दी है।

दिल्ली में दुग्ध बस्ती

श्री यश्यात सिंह: श्री कपूर सिंह: *1045. श्री ग्रोंकार लाल बेरवा: श्री हुकम चन्द कञ्जवाय: श्री यु०द० सिंह:

क्या खाद्य तथा हि व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना को नियमित रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए आरे का ानी को तरह दिल्लो में कोई दुग्धबस्ती बनाने का विचार है; और
- (ख) यदि हां, तो उस बस्तों को शीघ्र स्थापित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य ग्रौर कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं टठता।

Delimitation Commission

- *1049. Shri Yudhvir Singh: Will the Minister of Law be pleased to state:
- (a) when the Delimitation Commission would complete its work; and
 - (b) the States in which the work has been completed till now?

Minister of Law (Shri A. K. Sen): (a) The Delimitation Commission is likely to complete its work by the end of 1965.

(b) The Delimitation Commission has completed the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the States of Kerala and Madhya Pradesh and in the Union Territories of Goa, Daman and Diu and Pondicherry.

Merger of Air Corporations

*1050. Shri Madhu Limaye: Will the Minister of Civil Aviation be pleased to state:

- (a) whether Government propose to amalgamate the Indian Airlines Corporation and Air-India; and
- (b) if so, when and the advantage that will accrue as a result thereof?

Minister of Civil Aviation (Shri Nityanand Kanungo): (a) and (b). The Estimates Committee in their 41st Report on Air-India had also recommended that Government should review the question of a common Corporation. The Government had then examined the position and came to the conclusion that the review proposed by the Committee cannot be undertaken till the end of 1965 in view of the loans secured by Air-India from five U.S. Commercial Banks for financing their Boeing Project. The Corporation subsequently obtained additional loans for financing the cost of more Boeings, repayment of which would be completed in November, 1970.

एयर-इध्डिया एरोपलोट विमान सेवा करार

*1051. ∫श्री प्र० चं० बरूग्राः ेश्री इंद्रजीत गुप्त

क्या असै निक उड़्यन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या हाल में एयर इण्डिया ग्रौर सोवियत एयर लाइन, एरोफ्लोट के बीच विमान सेवा करार हुग्रा था ; ग्रौर
 - (खा) यदि हां, तो करार के मुख्य पद क्या हैं?

स्रमेतिक उड्डयन मंत्री (श्रीकानूनगो): (क) जी, नहीं । 2 तृन, 1958 को भारत स्रोर रूस के बीच वायु सेवा के सम्बन्ध में एक स्रन्तर्राजीय करार हुम्रा था । करार में नियत कालीन पुर्नावलोकन की व्यवस्था की गई थीं जिस के परि-णामस्वरूप एयरोफ्लोट को स्रौर एयर इंडिया के प्रतिनिधियों के बीच मास्को में 12 स्रौर 13 स्रप्रैल, 1965 को बातचीत हुई जिस में एयरलाइन्स ने दोनों एयरलाइन्स की कुछ ग्रावश्यकतास्रों की पूर्ति के लिये वायु-सेवा के करार में कुछ तबदीलियां करने क लिये सम्बन्धित सरकारी स्रधिकारियों को सिफारिश करना स्वीकार कर लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि सुधार

*1052. श्री श्रोतारायण दास: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 1 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 287 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राज्य सरकारों ने कुशल खेती ग्रौर प्रबन्ध के तरीके ढूंढ निकालने ग्रौर उन्हें ग्रपनाने के लिए ग्रावश्यक उपायों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विशास परिषद् की भूमि सुधार कार्या- न्विति समिति के निर्णय के ग्रनुसरण में सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति के प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की है; ग्रौर
- (ख) यदि हां, तो वे कौन कौन से राज्य हैं ग्रौर की गई कार्यवाही का ठीक-ठीक ब्योरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि॰ सुब्रह्मण्यम): (क) तथा (ख) ग्रान्ध प्रदेश, बिहार, ग्रीर मद्रास की सरकारों से ग्रनुरोध किया गया था कि ग्रनुभव प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ चुने हुए सघन कृषि जिला कार्यक्रम या सघन खेती कार्यक्रम क्षेत्रों में समिति के सुझावों का परीक्षण करें। इन सुझावों को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों ने कठिनाइयां व्यक्त की हैं।

ग्रादिम जातियों भ्रौर पिछड़े वर्गों का कल्याण

डा० चन्द्रभान सिंह : 2622. ड्री विद्याचरण शुक्त : श्री उद्दर्भे : श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने कोई ऐसा अभिकरण रखा है जो आदिम जातियों भीर पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये दिये गये अनुदानों के उपयोग पर निगरानी रखे; और
 - (ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर): (क) ग्रौर (ख). संयुक्त सचिव के पद के एक विशेषाधिकारी ग्रर्थात् पिछड़े वर्गों के (कल्याण) निदेशक को सामाजिक सुरक्षा विभाग में नियुक्त कर लिया गया है। वह योजनाग्रों की प्रगति का ध्यान रखने के लिये राज्य सरकारों से प्रगाढ़ सम्पर्क बनाये रखने के लिये उत्तरदायी हैं। इसके ग्रतिरिक्त ग्रनुसूचित जातियों ग्रौर ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियों के ग्रायुक्त का एक संगठन होता है जिस के ग्रधीन सभी राज्यों में प्रोदेशिक सहायक ग्रायुक्त होते हैं। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए योजनाग्रों की उचित कियानित सुनिश्चित करने के लिये ग्रन्थ ग्राभिकरण स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में भ्रादिम जातीय छात्र

डा० चन्द्रभान सिंह : श्रो विद्याचरण शुक्त : श्री उद्दक्ते : श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि फीस न देने के कारण मध्य प्रदेश में शिक्षा संस्थास्रों से क्षुछ स्रादिम जातीय छात्नों के नाम काट दिये गये थे; स्रौर
- (ख) क्या इस का कारण यह है कि केन्द्र से छात्रवृतियां दिया जाना बिलिम्बित व्या ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं। मिंदिक उपरान्त कक्षाग्रों में पढ़ने वाले ग्रादिम जातीय छात्रों के साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न हो नहीं उठता ।

मेद्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां

श्री विद्या चरण शुक्ल : 2624. श्री उइके : श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यः बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 1962-63, 1963-64 तथा 1964-65 में मध्य प्रदेश में मैट्रिक उपरान्त अध्ययन को लिये आदिम जातीय छात्रों को कितनी केन्द्रीय छात्र शृत्तियां दी गईं; श्रीर
 - (ख) उक्त छात्रवृत्तियों के लिये कितने आवदन पत्र प्राप्त हुए थे ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) :

	1962-63	1963-64	1964-65
(क)	521	687	943
(ख)	580	737	995

दहेज रोक माधिनियम, 1961

2625. श्री म० प० स्वामी : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) दहेज रोक अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत इस के लागू होने की तारीख से अब तक राज्यवार कितने मुकदमे चलाये गये ; और
 - (ख) इन मामलों में किस प्रकार के दण्ड दिये गये ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) ग्रीर (ख) दहेज प्रतिष अधिनियम, 1961 का प्रशासन राज्य सरकारों ग्रीर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास है ग्रीर उन से यह अपेक्षित नहीं है कि वे अभियोजनों भ्रादि के सम्बन्ध में कोई स्रांकड़ें केन्द्रीय सरकार को दें। ग्रतः भ्रपेक्षित जानकारी केन्द्रीय सरकार के पास तुरन्त प्राप्य नहीं है। उसे राज्य सरकारों ग्रोर संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से संग्रहीत किया जा रहा है ग्रोरः यथासमय सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

बंगलौर दिल्ली उड़ान

2626. श्री राम हरस यादव: क्या ग्रसैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपाः करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि बंगलीर से दिल्ली को उड़ान करने वाले विमानों कोः मच्छर भारी संख्या में घेर लेते हैं ग्रीर यात्रियों को तंग करते हैं तथा उन के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं ; ग्रीर
- (ख) यदि हां, तो सरकार ने यात्रियों की सहायता के लिये क्या कदम उठाये हैं। तथा यदि इसमें कोई सफलता मिली है तो कितनी ?

प्रसैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो): (क) ग्रीर (ख) बंगलीर विमान पत्तन से दूर स्थानों में संघ्याकाल में मच्छरों के झुंड ग्रा जाते हैं। यार्तियों के विश्रामकक्षों इत्यादि को नियमित रूप से फ्लिट से छिड़का जाता है। ये मच्छर संभवतः मलेरिया रोगः के नहीं हैं। कुछ विमानपत्तनों के निकट ही नीचे क्षेत्र हैं या खुली नालियां हैं ग्रीर वहां मच्छर पैदा होते हैं। समस्त विमानक्षेत्रों के नियंत्रकों ग्रीर विमान क्षेत्र ग्रिधकारियों को ग्रादेश जारी कर दिये गये हैं कि मच्छरों के पैदा होने के समस्त स्थानों की खोज की जाये ग्रीर वहां कीटनाशी उपाय काम में लाये जायें। विमानपत्तनों पर मच्छरों का उत्पात समाप्त करने के लिये विमानपत्तन के स्वास्थ्य कर्मचारियों के सहयोग से उनसे सब संभव कार्यवाही करने के लिये कह दिया गया है।

इंडियन एयरलाइन्स अपने विमानों को उड़ान से पूर्व नियमित समय से धुंग्रारा देतीः है श्रौर फ्लिट छिड़कती है । उन क्षेत्रों में जहां मच्छरों का उत्पात अत्यधिक है वहां यहः पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होती है ।

मध्य प्रदेश में सघन खेती कार्यक्रम

- 2627. श्री लखमू भवानी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें। कि:
 - (व) मध्य प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां सघन खेती का कार्यक्रमः किया पत्र है ; प्रौर
- (ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को क्या सुविधायें दी जा रही हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम लागू किये गये हैं:—

मुख्यतया चावल पैदा करने वाले

मुख्यतया गेहं पैदा करने वाला

(1) बिसासपुर

टिकमगढ़

- (2) दुर्ग
- (3) बालाघाट
- (ख) कृषकों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनमें वृद्धि करने की दृष्टि से सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रपों के अन्तर्गत उन्हें निम्नलिखित विशेष सहायता दी जा रही है :---
 - (1) जिले तथा खण्ड स्तरों पर सुदृइ स्टाफ के नाघ्यम से कुथ हों को रुघन तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता दो जा रहें है ताकि उन्हें शिक्षित किया जा सके ग्रौर उन्नत विधियों को ग्रपनाने में उनकी सहायता की जा सके।
 - (2) स्टाफ की गित-क्षमता बढ़ाना तािक वे क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा कृषकों को मिल सकें, एक ग्राँर जीप देकर जिले में उपलब्ध परिवहन सुविधाग्रों को बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक सघन कृषि जिले को एक ट्रक उपलब्ध कर दिया गया है तािक उत्पादन सप्लाई की गित तेज हो सके।
 - (3) कृषि के विशेष विकास कार्यक्रमों (कैंश कार्यक्रम) के अन्तर्गत 1964-65 के दौरान सघन कृषि क्षेत्र में गोदामों के निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त निधियां स्वीकृत की गईं। इसी प्रकार की सहायता 1965-66 में भी दी जा रही है। इन गोदामों के बन जाने से बीज, उर्वरक, श्रौजार श्रौषधियां श्रादि का स्टाक रखा जा सकेगा जिस से किसानों को प्राप्त करने में श्रासानी होगी।
 - (4) एक कार्यक्रम का ग्रभिरूप तैयार करना है जिसके ग्रनुसार प्रत्येक फसल के मौसम में किसानों के खेतों पर समन्वित रूप से बड़ा संख्या में प्रदर्शन किये जायेंगे। "पैकेज ग्राफ प्रेक्टिसिज" को ग्रपनाने के फलस्वरूप उपज कर पर जो संचयी प्रभाव पड़ते हैं उनको दिखाना इन प्रदर्शनों का उद्देश्य होगा।

विशेष सहायता के स्रतिरिक्त ऋणों तथा उन्नत बीजों, उर्वरकों, उन्नत कृषि स्रौजारों, पौद संरक्षण स्रादि के लिए स्राधिक सहायतास्रों के रूप में सरकार की सामान्य सहायता सवन कृषि क्षेत्रों में जारी रहेगी । यह निम्न प्रकार से है :—

- (क) खाद्यान्नीं तथा दालों के उन्नत बीजों पर 2 रूपये प्रतिमन का एक प्रीमियमः दिया जाता है ।
- (ख) फास्फेटिक उर्वरक पर 25 प्रतिशत उत्पदान किसानों के लिए उपलब्ध है।

- (ग) कीटनाशक ग्रौषधियों, डस्टरों, स्प्रेयर्स ग्रादि की बिक्ती पर 25 प्रतिशत उपदान दिया जाता है। इसके ग्रतिरिक्त पावर से चलने वाली मशोनों ग्रौर पौद रक्षा उपकरण के लिए 100 प्रतिशत ऋण भी स्वीकार्य है।
- (घ) कृषकों द्वारा खरीदे गये उन्नत कृषि ग्रौजारों की लागत पर 25 प्रतिशत तक का ग्रनदान दिया जाता है ।

चीनी की उपलब्धता

- 2628. श्री लखमू भवानी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) वर्ष 1964-65 में मध्य प्रदेश में चीनी की कुल कितनी वार्षिक ग्रावश्यकता भी ; ग्रीर
- (ख) वर्ष 1964-65 में मध्य प्रदेश में चीनी की ठीक प्रकार सप्लाई के लिये क्या कुछ उपाय किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 1'44 लाख मीट्रिक टन ।

(ख) 1965-66 में मध्य प्रदेश ऋौर अन्य राज्यों को शक्कर की सप्लाई शक्कर की उपलब्धि ऋौर उन राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर विनियमित की जाएगी!!

ागवान ः विकास

2629. श्री लखन् भवानी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) मघ्य प्रदेश राज्य को 1964-65 में बागवानी के विकास के लिए क्या ऋण तथा ग्रनदान के रूप में कितनी राशि दो गई;
 - (ख) उक्त अविध में मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी राश्यि का उपयोग किया ;
- (ग) 1965-66 में इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कितनो राशि देने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : पूछी हुई जानकारी निम्न प्रकार है :---

(रुपये लाखों में)

			ऋण	ग्र नु दान	कुल
(有)	¢	,	7.20	4.97	12.17
(ख)			2.27	2.06	4.33
(ग)			8.68	4.40	13.08

दिसम्बर, 1964 तक।

Dairy Farms in U.P.

2630. Shri Sarjoo Pandey: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

- (a) the total amount given to U.P. during the Third Plan period so far, for setting up of dairy farms;
 - (b) whether the entire amount has been utilised; and
- (c) if so, the places at which the said dairy farms have been set up, as also the amount given to them?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan):

- (a) Nil.
- (b) and (c). Do not arise.

मिट्टी अनुसन्धान केंद्र

2631. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देश में केन्द्र द्वारा चलाये जा रहे मिट्टी अनुसंधान केन्द्रों के नाम क्या हैं और वे कहां कहां पर हैं ;
- (ख) किसानों को अनुसंधान के परिणामों से अवगत कराने तथा केन्द्रों के कार्य से सम्बद्ध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; श्रौर
- (ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में कितने केन्द्र खोले जायेंगे भ्रौर 31 मार्च, 1965 तक कितने केन्द्र खोले गए हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) केन्द्र द्वारा चलाई ज) रही निम्न संस्थायें मिट्टी ग्रनुसंधान सम्बन्धी कार्य कर रही हैं :

- (1) केन्द्रीय मरु भूमि अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
- (2) निम्न स्थानों पर स्थित भूमि संरक्षण, अनुसंधान प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र :---

(ख) समस्त केन्द्रों में ऐसा अनुसंघान कार्य हो रहा है जिस का अभिप्राय समस्या-समाधान करना है; इसलिए अनुसंघान सम्बन्धी कार्य वाले अधिकारी लोग आसपास के ग्रामों से सम्पर्क स्थापित करते हैं। कृषकों को भी अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया

जाता है। प्रत्येक केन्द्र में "कृषक दिवस" मनाया जाता है ग्रौर वहां कृषकों को ग्रामन्त्रित करके उन्नत तकनीकों के विषय में परिचित कराया जाता है। खण्ड विकास ग्रधिकारियों तथा जिला कृषि ग्रधिकारी भी उन्नत तकनीकों के विषय में कृषकों को जानकारी देते रहते हैं। कृषकों की नई तकनीकों के बारे में फिल्में भी दिखाई जाती हैं।

(ग) उड़ीसा, ग्रान्ध्र प्रदेश तथा ग्रासाम में भी एक एक केन्द्र को स्थापित करने का प्रस्ताब था। इस समय तक ग्रान्ध्र प्रदेश में इब्राहिमपटन में एक केन्द्र की स्थापना हुई है।

Delhi Zoological Park

- 2632. Shri Sidheshwar Prasad: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- (a) whether the arrangements made for the protection of Delhi Zoo from flood and rain water have been completed;
 - (b) if so, the expenditure incurred thereon; and
 - (c) if not, the reasons for the delay?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Yes. While the construction of a bund to prevent Jamuna water entering into the Zoo and the excavation of lake have already been completed, the work of filling up of low lying areas is in progress and is likely to be completed before the next monsoons.

- (b). Against sanctioned expenditure of Rs. 6:38 lakhs, a sum of Rs. 5:00 lakhs approximately has been spent.
 - (c). Does not arise.

Farmers sent Abroad

- 2633. Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- (a) the names of the countries to which farmers were sent during the last three years and the dates on which they were sent;
 - (b) the State-wise number of these farmers;
- (c) the names of countries from which delegations of farmers visited India during this period and the dates of their visit; and
- (d) the names of those parts of India which were visited by them?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture Shri Shah Nawaz Khan): (a) United States of America on the 9th May, 1964.

- (b) One each from Assam, Bihar, Delhi, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Madras, Maharashtra, Mysore and Orissa.
- (c) United States of America; the farmers arrived in India during September, 1964.

(d) The farmers visited all parts of India except Pondicherry, Manipur, Tripura, Andamans and Nicobar, Laccadive, Mincoy and Amindivi Islands, Nagaland and Goa, Daman-Diu.

The above information relates to the International Farm Youth-Exchange Programme stated by the National 4-H Club Foundation of the United States of America in collaboration with the Government of India. It does not cover the exchange of farmers and young farmers between India and U.S.A., Japan and Israel arranged by the Bharat Krishak Samaj and young farmers' Association of India.

Blocks of Adivasis in Maharashtra

2634. Shri D. S. Patil: Will the Minister of Social Security be pleased to state:

- (a) the present number of Adivasis Blocks in Maharashtra;
- (b) the number and the location of such Blocks proposed to be set up during 1965-66; and
- (c) the number of Adivasis Blocks proposed to be set up in Yeotmal and Akola Districts respectively in Maharashtra?

Deputy Minister of Social Security (Smt. M. Chandrasekhar): (a) Forty Tribal Development Blocks and 4 Special Multipurpose Tribal Blocks.

S1.		District in which located
I.	Warle	Thana
2.	Asawe (Ashagad)	Thana
3.	Borhe	Nasik
4.	Mhaswad	Dhulia
5.	Ashte	Dhu l ia
6.	Nawapur	Dhulia
7.	Rajur	Ahmednagar
8.	Kurkheda	Chanda
9.	Dhanora	Chanda
10.	Bhamragad	Chanda

(c) One in Yeotmal district and more in Akola district

Supply of Fertilizers to Maharashtra

2635. Shri D. S. Patil: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

- (a) the quantities of Ammonium Sulphate, Double Salt, Urea and Calcium Ammonium Nitrate which were demanded by the Government of Maharashtra during 1963-64 and 1964-65;
- (b) the extent to which the demand for these fertilizers was met out of the Central Fertilizer Pool; and
 - (c) the reasons for the shortfall between the demand and supply?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (c). A statement giving the required information is appended.

		Staten	nent	(Figures	in tonnes)
Kind of fertiliser	Quantity demanded by the Govt. of Maharashtra		Quantity allotted from Central Fer- tiliser Pool		Reasons for the shortfall if any
	1963-64	1964-65	1963-64	1964-65	
Sulphate of Am- monia	179,992	214,000	116,451	113,000	Due to limited availability of Ammonium Sulphate the demand could not be met infull.
Urea Calcium Ammo- nium Nitrate	20,000 5,000	22,010 5,000	41,003 23,047	42,950 20,665	The allotment as made in excess of the demand with a view to compensate for the short supply of Sulphate of Ammonia and Ammonium Sulphate Nitrate.
Ammonium Sul- phate Nitrate	20,000	22,521	8,627	10,100	There are no imports of this fertiliser and only a limited quantity is produced by the Sindri factory. Hence the allot ment was low.
Nitrophosphate	15,000	28,500	15,000	28,500	••
Ammonium Phosphate	••	••	••	1,200	The allotment was made to compensate for short supply of Sulphate of Ammonia.

Package Programme in Maharashtra

2636. Shri D. S. Patil: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

- (a) whether the Central Government have given their approval for starting any package programme in Maharashtra during 1965-66.
- (b) whether any grant or loan is proposed to be sanctioned for the package programme in Maharashtra during 1965-66; and
 - (c) if so, the total amount thereof?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): (a) The Intensive Agricultural District Programme (Package Programme) is already in operation in Bhandra district of Maharashtra. The programme was initiated in 1963-64 and will continue during 1965-66 as well. Besides, an Intensive Agricultural Area Programme has also been introduced in all the districts of Maharashtra, except Greater Bombay and Bhandra for stepping up production of paddy and other important crops. This programme will also continue during 1965-66. There is no other proposal to start any package programme.

(b) and (c). The quantum of Central assistance by way of grant to be given to the State Government during 1965-66 for the Intensive Agricultural District Programme as well as the Intensive Agricultural Area Programme is tentatively estimated at about Rs. 30.00 lakhs. This excludes the loans short-term and other to be made available by the State Government as well as Cooperatives.

Adivasi Students in Vidarbha

- 2637. Shri D. S. Patil: Will the Minister of Social Security be pleased to state:
- (a) whether the Adivasi students living in non-scheduled areas in Vidarbha in Maharashtra are getting post-Matric scholarships as students of Backward Classes and not as Adivasis; and
 - (b) if so, the reasons therefor?

Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. M. Chandrasekhar): (a) and (b). No distinction is made between a scheduled area and a non-scheduled area for the purpose of granting postmatric scholarships to Scheduled Tribe students in Vidarbha region of Maharashtra.

However, the Adivasis residing outside the specified areas of Vidarbha have not yet been declared as Scheduled Tribes. The Adivasis living in the areas outside the specified areas of Vidarbha in Maharashtra are, therefore, treated as Economically Backward Classes for the award of post-matric scholarships.

Welfare of Adivasis of Vidarbha

- 2638. Shri D. S. Patil: Will the Minister of Social Security be pleased to state:
- (a) whether Dhebar Commission has made any specific recommendations for the welfare of Adivasis of Vidarbha in Maharashtra;
 and
 - (b) if so, the action taken thereon?

Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. M. Chandrasekhar): (a) No.

(b) Does not arise.

ग्रनाज की नीलामी

$$2639$$
. 3 श्री राम हरख यादव : 3 श्री मुरली मनोहर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय कृषि ग्रनुसंधान संस्था, नई दिल्ली के ग्रनाज ग्रौर ग्रन्य उत्पादों को भारी मात्रा में सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचने का विचार कर रही है ;

- (ख) यदि हां तो बेचे जाने वाले स्रानाज कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है; स्रौर
- (ग) इसके कारण क्या हैं, विशेषतया जबकि देश में ग्रनाज की भारी कमी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) निम्न वस्तुयें बेचने का प्रस्ताव है (मात्राग्रों का ग्रनुमान दिया गया है):—

(1)	गेहूं मिश्रण तथा टूटा ग्रनाज			700	क्विन्टल
(2)	जौ मिश्रण तथा टूटा बरेच			40	,,
(3)	बाजरा मिश्रित .			5	"
(4)	ज्वार मिश्रित			5	"
(5)	बीज कपास .			16	"
(6)	गेहूं भूसा .			1000	,,
(7)	चना भूसा			20	"
(8)	ज्वार तथा मक्का डन्ठल (करबी)			400	"
(9)	तम्बाकू पत्ते तथा डन्ठल	•	•	12	11

(ग) भारतीय कृषि ग्रनुसंघान संस्थान की ग्रधिकांश धान्य तथा कृषि उपज बीजों के लिए बेची जाती है। "सीविंग्ज", मिश्रण ग्रादि ऐसा फालतू स्टाक जो बीज के लिए ग्रनुपयुक्त है, नोलामों द्वारा बेच दिया जाता है। फार्म के फालतू उपज को बेचना पड़ता है क्योंकि भण्डारण के लिए उपलब्ध सीमित स्थान की परीक्षणात्मक सामान के भण्डारण के लिए ग्रावश्यकता पड़ती है। इस प्रकार बेचे जाने वाले ग्रनाज से खाद्य की कमी की भी पूर्ति होती है।

धान कर की वसूली

2640. श्री ग्र० क० गोपालन: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केरल में धान कर वसूली की कैसी प्रगति हो रही है ;
- (ख) क्या कर वसूली के मामले में भूमि के मालिकों द्वारा स्रानाकानी ग्रथवा विरोध दिखाया जा रहा है ;
 - (ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; ग्रौर
 - (घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा॰ रा॰ चव्हाण) : (क) केरल में लेवी द्वारा धान के संग्रहण का कार्य राज्य के कुछ जिलों में ग्रच्छी तरह से हो रहा है जबिक ग्रन्य जिलों में प्रगति सन्तोषजनक नहीं है।

- (ख) ग्रौर (ग). राज्य के कुछ जिलों में रैयत कुछ ग्रानाकानी करते हैं क्योंकि उनका यह विचार है कि भाव पर्याप्त नहीं हैं।
- (घ) सरकार रैयत को इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि भाव अपर्याप्त नहीं हैं अप्रौर उन्हें लेवी देने के लिये राज़ी कर रही है।

क्विलोन का छोटा बन्दरगाह

- 2641. श्री ग्र० क० ग पालन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्विलोन के छोटे बन्दरगाह का निर्माण-कार्य कब आरम्भ किया गया था ;

- (ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि नियत की गई थी ; स्रौर
- (ग) यह काम कब पूरा हो जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्रो राज बहादुर): (क), (ख) ग्रौर (ग) क्विलोन पत्तन के विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय ग्रायोजना में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। फिर भी निंदण्कारा पत्तन का मध्यवर्ती पत्तन के रूप में विकास करने के लिए तीसरी ग्रायोजना में 135.65 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। यह पत्तन क्विलोन पत्तन से 6 मील उत्तर की ग्रोर है। निंदण्कारा पत्तन परियोजना पर केरल सरकार ने 30 सितम्बर, 1964 तक 12.85 लाख रुपया खर्च किया है।

त्तुक्कुडि (दूटीकोरिन) बन्दरगाह

2642. श्री भ्र० क० गोपालन : क्या परिवहन मंत्री यह बाने की कृपा करेंगे कि :

- (क) तूतुक्कुडि बन्दरगाह को वर्ष भर प्रयोग में लाये जाने वाले तथा एक बड़े बन्दरगाह के रूप में बनाने का काम कब ग्रारम्भ किया जायेगा ;
 - (ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ; श्रौर
 - (ग) यह काम कब पूरा हो जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तूतीकोरिन पर सब मौसमों वाला बड़ा पत्तन बनाने का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। सड़कें, रेल की लाइन, कार्यालय श्रौर श्रावास इमारतों जैसे प्रारंभिक निर्माण कार्य या तो पूरे हो गये हैं या प्रगति के काफी ग्रग्रवर्ती कम में हैं। उत्तरी पनकट देवार 250 मीटर तक तैयार हो गयी है। दक्षिणी पनकट दीवार, जो 3 मीटर नीचे की ग्रोर है, का निर्माण कार्य शीध्र ही शुरू किया जायेगा। इस हारबर के ग्रधिकांश निर्माण कार्य के ठेकों को संभवतः दिसम्बर, 1965 तक ग्रंतिम रूप दिया जायेगा।

- (ख) तूतीकोरिन हारबर के विकास के लिये तीसरी पंचवर्षीय भ्रायोजना में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है। 31 मार्च, 1965 तक 3 करोड़ रुपया व्यय हो चुका है 1965-66 बजट अनुमानों में 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
 - (ग) इस हारबर के 1969 तक तैयार होने की संभावना है।

करल में कमी की स्थिति

2643 श्रो ग्र० क० गोपालन: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अब भी केरल में कमी की स्थिति विद्यमान है;
- (ख) क्या ग्रनौपचारिक राशनिंग होने ग्रौर नई फसल के ग्राने के बावजूद भी केरल में चावल के बाजार भाव बढ़ रहे हैं ;
- (ग) केरल में उचित मूल्य पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से कितना चावल व कितना गेहूं दिया जाता है ;
 - (घ) क्या सरकार का विचार केरल में कानूनी तौर पर राशिंग करने का है ; ग्रौर

(ङ) यदि नहीं, तो उचित मूल्य पर ग्रधिक ग्रनाज देने के लिये सरकार का क्या ग्रन्य उपाय करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० २१० चव्हाण): (क) जी, नहीं।

- (ख) चावल के खुले बाजार भाव में थोड़ी बढ़ोतरी का रुख है। कम ग्रामद की ग्रविध शुरू होने से चावल के खुले बाजार भावों में सामान्यतः बढ़ोतरी का रुख ग्राता है।
- (ग) उचित मूल्य की दुकानों पर प्रति प्रौढ़ को प्रतिदिन 160 ग्राम चावल ग्रौर 160 ग्राम गेहूं की मात्रा राशन में दी जाती है ।
 - (घ) मामला केरल सरकार के विचाराधीन है।
 - (ङ) सरकार राशन कार्डों से उचित मूल्य पर खाद्यान्न दे रही है।

निर्वाचन चिन्ह

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या निर्वाचन ग्रायुक्त को भारत के साम्यवादी दल के सभापित, श्री एस० ए० डांगे से कोई शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने भारत के वामपन्थी साम्यवादी दल को "तारे के के साथ हंसिया ग्रीर हथौड़ा" का निर्वाचन चिन्ह देने पर ग्रापित्त की है; ग्रीर
 - (ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी, हां।

(ख) ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् निर्वाचन ग्रायोग ने श्री डांगे को सूचित कर दिया है कि वह "तारे के साथ हंसिया ग्रौर हथौड़ा" निर्वाचन प्रतीक भारत के कम्युनिस्ट दल (मार्क्सवादी) को ग्रावंटित करने का ग्रपना विनिश्चय रद्द् या परिवर्तित करने में ग्रसमर्थ है।

C. D. Blocks

2646. | Shri M. L. Dwivedi: Shri S. C. Samanta: Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of Community Development and Cooperation be pleased to state:

- (a) the number of Post Stage II Development Blocks in the country (State-wise) where development work has been completed;
- (b) the nature of development works now being undertaken in such blocks and the percentage of the finances now made available to

these blocks by the Central Government as compared with the previous years;

- (c) the number of blocks out of them where the required results have not been achieved so far; and
- (d) whether Government have any scheme in hand to restart the intensive development work in the development blocks referred to in part (c) above, if so, the details thereof and when it would be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy):

(a) to (d). The statewise position of the number of Post Stage II blocks is given below:—

6-1	
1. Andhra Pradesh	73
2. Assam	27
3. Bihar	37
4. Gujarat	28
5. Jammu and Kashmir	2
6. Kerala	18
7. Madhya Pradesh	5 9
8. Madras	62
9. Maharashtra	52
10. Mysore	$29\frac{1}{2}$
11. Orissa	23
12. Punjab	41
13. Rajasthan	38
14. Uttar Pradesh	63
15. West Bengal	30
16. Nagaland	3
17. Delhi	3
18. Himachal Pradesh	7
19. Manipur	1
20. Tripura	2
21. NEFA	2
	6001

As the Community Development schematic budget is operative only for Stage I and Stage II blocks, no Central assistance is given by the Ministry for Post Stage II blocks. The State Governments have, however, been requested to route all the funds and schemes of various development departments capable of execution at the block level through the block agency, so that the tempo of development already reached in the Post Stage II blocks could be maintained.

The Programme Evaluation Organisation is undertaking a comprehensive survey of the impact of development in Post Stage II Blocks.

पटसन ग्रौर लाख ग्रनुसन्धान केंद्र

2647. श्री सुबोध हंसदा : श्री दलजीत सिंह :

नया खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का विचार पूर्वी भारत के दो अनुसंधान केन्द्रों अथात् एक पटसन भ्रौर दूसरे लाख के केन्द्रों को पश्चिम बंगाल से कुछ अन्य स्थानों पर ले जाने का है;
 - (ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; ग्रौर
- (ग) इन केन्द्रों के कर्मचारियों को नौकरी देने के लिए सरकार का विचार क्या व्यवस्था करने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) भारतीय लाख अनुसंघान संस्थान इस समय बिहार राज्य के नामकुम (रांची) में स्थित है। पटसन कृषि अनु-संघान संस्थान भीर प्रौद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पटसन) बैरकपुर तथा टौलीगंज (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं। इन संस्थाओं को अपने मौजूदा स्थानों से बदलने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तया (ग). प्रश्न ही नहीं होते ।

चाय के बाग

श्री स० चं० सामन्त : श्री म० ला० द्विवेदी : श्री सुबोध हंसदा : श्री ब० कु० दास :

क्या लाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पिछले पांच वर्षों में चाय के बागों के लिए उर्वरक का जो कोटा नियत किया गया था वह पर्याप्त था ऋौर उसका उचित रूप में प्रयोग किया गया ;
 - (ख) क्या वितरण व्यवस्था में कोई परिवर्तन हुग्रा है ;
 - (ग) क्या यह सच है कि कुछ एजेन्सियों ने ग्रपने कोटे नहीं लिए ;
 - (घ) यदि हां, तो बाद में उनका किस प्रकार वितरण हुआ ; श्रीर
 - (ङ) क्या किसी एजेत्सी को उनका उत्तरदायित्व लेने के लिये कहा गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) यह मंत्रालय उत्तर-पूर्वी भारत के चाय के बागों के लिए उर्वरकों का कोटा वितरणकर्ताओं को देता है। जहां तक दक्षिण भारत के चाय के बागों का सम्बन्ध है, उर्वरकों का कोटा यूनाइटिड प्लांटर्स एसो-सिएशन ग्राफ साउथ इण्डिया को दिया जाता है। यह एसोसिएशन ग्रागे स्वीकृत वितरणकर्ताओं को उर्वरकों का कोटा देता है। पिछले 5 वर्षों में उत्तर-पूर्वी भारत के वितरणकर्ताओं तथा यूनाइटिड

प्लांटर्स एसोसिएशन आफ साउथ इण्डिया को उर्वरकों का जो कोटा दिया गया था वह चाय के बागों की मांग के लिए पर्याप्त था । उत्तर-पूर्वी भारत के वितरणकर्ताओं तथा यूनाइटिड प्लांटर्स एसो-सिएशन आफ साउथ इण्डिया के स्वीकृत वितरणकर्ताओं ने उर्वरकों की जो मान्ना ली उसका चाय के बागों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग किया गया ।

- (ख) जी हां। उत्तर-पूर्वी भारत में वितरणकर्ताम्रों की कुल संख्या को 29 से घटाकर 22 कर दिया गया।
 - (ग) जी हां।
- (व) उत्तर पूर्वी भारत के वितरणकर्ताम्रों ने निर्धारित म्रविध के म्रन्दर जो कोटा नहीं उठाया था, उसे रद्द समझा गया। 1964-65 की म्रविध में 1733 मेंटर टन उर्वकों को जिस मात्रा को कुछ वितरणकर्ताम्रों ने नहीं उठाया था उसे दोबारा म्रन्य वितरणकर्ताम्रों को बांट कर दिया गया।
 - (ङ) जो, नहीं।

Air Service in North Bihar

2649. Shri Bibhuti Mishra: Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of Civil Aviation be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that no air transport facilities exist in the North Bihar especially in the Tirhut Division;
- (b) whether there is any proposal under consideration to develop the existing landing strip at Muzaffarpur or construct a new aerodrome at some other place in North Bihar or at Motihari in the district of Champaran, North Bihar; and
 - (c) if so, the broad outlines thereof.

The Minister of Civil Aviation (Shri Kanungo): (a) There are civil aerodromes at Raxaul and Muzaffarpur.

(b) and (c). The Muzaffarpur aerodrome has already been developed. It has an all-weather runway, apron and taxi track. Another aerodrome is under construction at Jogbani.

जहाज बनाने का सामान

2650. श्री विभूति मिश्र : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

- (क) क्या यह सच है कि नीदरलैंन्ड की सरकार ने भारत को जहाज बनाने का सामान स्रासान तथा सस्ती दरों पर देने का प्रस्ताव किया था ; स्रौर
 - (ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस मामले को आगे बढ़ाया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

बादी उत्पादन

2651. श्री शुलेश्वर मीनाः

नया सनामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खादी के उत्पादन में काफी कमी हुई है;

- (ख) यदि हां, तो कितनी ; ग्रौर
- (ग) सरकार ने चालू वर्ष में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) ग्रौर (ख). जी, नहीं। 1963-64 में उत्पादन में लगभग तीन प्रतिशत की उपान्त कमी हो गई थी जबिक वह 1962-63 में 746.5 लाख वर्ग मीटर की तुलना में 725 लाख वर्ग मीटर हो गया था।

- (ग) उत्पादन में वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :---
 - (एक) स्थानीय ग्रौर प्रादेशिक ग्रात्म-निर्भरता पर बल दे लक बुनाई योजना" को चाल करना ।
 - (दो) बेकार पड़े भ्रम्बर चर्खों का नवीकरण तथा फिर से सिकिय करना।
 - (तीन) कताई की मजूरी की दर में वृद्धि करने से कातने वालों को प्रोत्साहन देना ।

कृषि वैज्ञानिकों की तालिका

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि कृषि-वैज्ञानिकों की तालिका ने जिसकी हाल ही में बैठक हुई थी, सुझाव दिया है कि कृषि के क्षेत्र में ग्रनुसंधान कार्यकर्ताग्रों के विचारों का ग्रन्य राज्यों में उनके जैसे कार्यकर्ताग्रों के साथ विचार विनिमय करने के लिए एक समन्वयकारी निकाय बनाया जाये ; श्रीर
 - (ख) यदि हां, तो इसके निष्पादन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) जी नहीं।
 - (ख) प्रश्न ही नहीं होता।

राज्यों को चीनी का कोटा

वया खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों का चीनी का कोटा कम करने का विचार कर रही है; श्रीर
 - (म) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मत्रालय में उपमंत्री (श्रो दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय कृषि ग्रनुसन्धान परिषव्

26.54. श्री रामचन्द्र उलाकाः श्री घुलेश्वर मीनाः

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 1964-65 में भारतीय कृषि ग्रनुसन्धान परिषद् ने कृषि उपकर के रूप में कितना रुपया प्राप्त किया;
 - (ख) इसमें से मुख्यालय के कर्मचारियों पर कितना व्यय हुग्रा; ग्रीर
 - (ग) अनुसन्धान श्रौर अन्य योजनास्रों पर कितना व्यय हुस्रा?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग) पूछी हुई जानकारी का एक विवरण नत्थी है।

विवरण

श्राय	व्यय			
1964-65	(रुपये)	1964-65 (रुपये)		
(1) कृषि उपज के उपकर से प्राप्ति	70,78,400	(1) प्रधान कार्यालय के 9,60,750 प्रशासनिक स्टाफ पर खर्च	0	
(2) ग्रन्य ग्राय	18,88,100	(2) अनुसन्धान तथा 61,55,00 अन्य योजनाओं जिनमें तकनीकी स्टाफ भी शामिल है, पर खर्च	0	
नुलः 89,66,	500	कुल 71,15,75	 o	

शहरी सहकारी बैंक

2655 श्री प्र॰ रं॰ चक्रवर्ती : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या रिजर्व बैंक शहरी सहकारी बैंकों को ग्रधिक सहायता देने के लिए सहमत हो गया है ताकि वह छोटे व्यापारियों तथा उद्योगपितयों को ग्रधिक ऋण देसके;
- (ख) छोटे उद्योगों की ग्रार्थिक ग्रीर तकनीकी सम्भाव्यताग्रों का ग्रध्ययन करने के लिए ग्रावश्यक क्षमता का विकास करने हेतु क्या शहरी सहकारी बैंकों ने कार्यवाही की है;

- (ग) क्या रिजर्व बैंक ने इस हानि के एक भाग की गारंटी देना स्वीकार कर लिया है, जो उन बैंकों को छोटे उद्योगों को ऋण देने में हो सकती है और; यदि हां, तो उसकी शर्ते क्या है; और
- (घ) सहकारी बैंकों द्वारा शहरी संसाधनों से धन प्राप्त किये जाने से गांवों में चालू ग्रौर पूंजीगत विनियोजन की वित्त-व्यवस्था करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की धन उपलब्ध करने में कहां तक सहायता मिली है?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्राजय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) यद्यपि भारत के रिजर्व बैंक ग्रिधिनियम में घरेलू तथा लघु उद्योगों के उत्पादन ग्रथवा विपणन के त्रियाकलापों के लिए वित्त सुलभ करने की व्यवस्था है, तो भी रिजर्व बैंक ने इस कार्य के लिए ग्रभी तक केवल सूती वस्त्र हथकर्घा उद्योग के लिए ही ग्रनुमित दी है। रिजर्व बैंक ग्रपने ग्रिधिनियम के ग्रन्तर्गत शहरी सहकारी बैंकों को सीधे वित्त नहीं दे सकता है किन्तु केवल राज्य सहकारी बैंक ग्रथवा ग्रनुसूचित बैंक के माध्यम से ही दे सकता है।

- (ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- (ग) भारत के रिजर्व बैंक ने इस हानि के एक भाग की गारंटी देना स्वीकार कर लिया है, जो शहरी सहकारी बैंकों को लघु उद्योगों को ऋण देने में हो सकती है, बशर्ते कि राज्य सहकारी बैंक अथवा भारत के स्टेट बैंक जैसी विशिष्ट ऋण संस्था ऐसे ऋण में 25 प्रतिशत तक भाग ले।
- (घ) सहकारी बैंकों को प्रमुख रूप से उन प्राथमिक सहकारी संस्थाग्रों को वित्त सुलभ करने में लगाया जाता है जो कि मुख्य रूप से किसानों से लेन-देन करती हैं। इन्होंने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों तथा प्राथमिक विपणन समितियों को काफी मान्ना में ऋण दिया है:

उड़ीता में हस्तशिल्य भंडार

श्री रामचन्द्र उलाका : 2656 श्री धुतेश्वर मोना : श्री रामचन्द्र मिलक :

क्या सामाजिक मुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 1963-64 ग्रौर 1964-65 में उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के हस्तिशिल्प भंडारों द्वारा दस्तकारी की वस्तुग्रों के विकय से कितनी राशि प्राप्त हुई ;ग्रौर
 - (ख) इसी अवधि में उन भंडारों के संचालन पर कितना व्यय हुग्रा।

विधि तंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार का कोई हस्तशिल्प भंडार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता

2657. श्री रामवन्द्र मॅलिक: क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गत पांच बर्षों में उड़ीसा सरकार को राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता देने के लिये कोई राशि दी गई थीं; अपैर
 - (ख) यदि हां, तो कितनी?

सानाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रनुसूचित जातियों के लिये 10,000 रुपये तथा ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियों के लिये 17,000 रुपये।

विधेयकों का हिन्दी रूपान्तर

26.58 श्री यशपाल सिंह: क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि संसद् के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विधेयकों का ग्रंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी रूपान्तर भी देने में सरकार को कितना समय लगेंगा?

विधि तंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : विधि मंत्रालय ग्राजकल उन सब मूल विधेयकों का हिन्दी ग्रनुवाद साथ साथ दे रहा है जो संसद् के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं। तंशोधक विधेयकों को भी हिन्दी ग्रनुवाद देना तब संभव हो सकेगा जब मूल ग्रिधिनियमों के हिन्दी रूपान्तर प्राप्य हो जायेंगे। इसमें कुछ समय लगने की संभावना है।

शिल्पकारों के लिए कच्चा माल

2659. श्री यशपाल सिंह: क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है जिससे कि शिल्पकारों को कच्चा माल तथा ऋण बराबर उपलब्ध होता रहे; ग्रौर
 - (ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है।

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि पहले ही लागू योजनाओं के अन्तर्गत शिल्पकारों को ऋण तथा कम मान्ना में उपलब्ध कच्चा माल जैसे आयातित कच्चा रेशम, हाथीदाँत, रंग, रासायनिक पदार्थ तथा मिश्रित धातुएं आदि दी जा रही हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछड़े हुए क्षेत्रों में चीनी कारखानें

श्रीप्र० चं० बरुग्राः 2660. श्रीदे० जी० नायकः श्रीयशपाल सिंहः

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश के कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों में चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए कुछ उद्योगपितयों को सुविधायें देने की किसी योजना पर विचार कर रही है; ग्रीर
- (ख) यदि हां, तो उस योजना का व्यौरा क्या है तथा 1965-66 में इस के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपनंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। (ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में कृषि उत्पादन

2661. श्री धुलेश्वर मीनाः श्री रामचन्त्र उलाकाः

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या उड़ीसा में खाद्य के उत्पादन के बारे में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाये गये कृषि कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई; श्रौर
- (ख) उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने खाद्य उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर लिया है तथा उनमें कृषिजन्य खाद्य उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का ग्रनुमान था ग्रौर वास्तविक वृद्धि कितनी हुई?

खाद्य तथा कृषि मंत्रातय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में खाद्यान्न उत्पादन को 40 लाख टन के आधार स्तर (1960-61) से 1965-66 में 56.15 लाख टन तक बढ़ाने का विचार है। 1961-62, 1962-63, 1963-64 तथा 1964-65 में उड़ीसा में खाद्यान्तों का (प्रत्याशित) उत्पादन क्रमश: 39.48, 39.86, 47.09 तथा 50.08 लाख टनथा।

(ख) उड़ीसा में 1961-62, 1962-63, 1963-64 तथा 1964-65 की अवधि में जिलाबार लक्ष्य तथा उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं उपरोक्त जानकारी उड़ीसा सर कार से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 4286/65]

गुजरात राज्य को बाजरे का सम्भरण

श्री छ० म० केदरिया : 2662. श्री मान सिंह पृ० पटेल : श्रीमती जोहराबेन चावडा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंने किः

(क) क्या यह सच है कि गंजाब सरकार ने गुजरात राज्य को 5,000 मीट्रिक टन बाजरा दिया है ;

- (ख) यदि हां, तो वह कब भेजा गया था;
- (ग) पंजाब सरकार ने किस भाव पर बाजरा खरीदा था; ग्रौर
- (घ) गुजरात सरकार को बाजरा किस भाव पर बेचा गया था?

खाद्य तथा कृषि मंत्राजय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण: (क) जी, हां।

- (ख) जनवरी, 1965 के ग्रन्तिम सप्ताह से फरवरी, 1965 के दूसरे सप्ताह की श्रवधि में।
- (ग) पंजाब सरकार ने रु० 56.45 से रु० 56.75 प्रति विवटल के बी भावों पर बाजरा खीदा।
- (घ) बाजरा गुजरात सरकार को लागत भाव जमा बोरियों की की मत, बिक्री कर स्रीर पंजाब सरकार के संस्थापन सम्बन्धी खर्चीं पर दिया गया था।

पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन श्रौर संचार

2663. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पहाड़ी तथा सीमान्त क्षेत्रों में छोटं नगरों के विकास सम्बन्धी सिमिति ने इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तथा प्राथमिकता क ग्राधार पर परिवहन तथा संचार के विकास की सिफारिश की है;
- (ख) यदि हां, तो विशेषकर त्रिपुरा तथा मनीपुर में सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; ग्रौर
- (ग) इम्फाल को सिलचर से मिलान वाले नए राजपथ का निर्माण करने की क्या संभावनाएं हैं?

परिवहन प्रंत्री (श्री राज बहादुर): (क) ग्रीर (ख). जी हां। पहाड़ों ग्रीर सीमान्त क्षेत्रों के छोटे शहरों के विकास पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिमिति स्थापित की थी ग्रीर उस मंत्रालय ने उस सिमिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों, जिसमें त्रिपुरा ग्रीर मनीपुर भी शामिल है को उसमें की गयी विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए भेज दिया है। ग्रागे की कार्यवाही राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों पर निर्भर करती है।

(ग) ग्रसम/मनीपुर सीमान्त क्षेत्र में पहले ही मोटर गाड़ी चलने योग्य एक सड़क सिलचर से जिरीघाट तक है। जिरीघाट से इम्फाल तक एक सड़क बन रही है। यह सड़क 151 मील लंबी है जिसमें से 9 मील लम्बी सड़क इम्फाल की ग्रोर पहले से ही मौजूद है। शेष 142 मील में से 100 मील लंबाई में सड़क निर्माण के लिए मिट्टी भरने भीर चट्टान काटन का काम पूरा हो गया है। शेष भाग में काम जारी है।

भारतीय खाद्य निगम

2664. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दालों को भारतीय खाद्य निगम के कार्यों के क्षेत्राधिकार के ग्रन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है; ग्रौर
- (ख) क्या सरकार ने उत्तर भारत में मूल्यों में हुई "ग्रसाधारण वृद्धि" को ध्यान में रखते हुए दालों के लिए मूल्य सहायता देने की मांगपर विचार किया है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) फिलहाल नहीं।

(ख) राज्य सरकारों को चने के सहारा देने के भाव रु० 40.00 से रु० 40.50 प्रति क्विंटल के बीच निर्धारित करने का ग्रिधकार देदिया गया है। दालों के लिये सहारा देने के भाव के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Offices under Ministry of Food and Agriculture

Shri Prakash Vir Shastri:
Shri P. L. Barupal:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Rameshwaranand:
Shri Madhu Limaye:
Shri Utiya:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:
(a) the new offices and corporations set up under his Ministry since 1st January, 1964;

- (b) the offices/corporations among them which have been given Hindi or Indian names; and
- (c) the reasons for not giving Hindi or Indian names to the remaining ones?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Following 8 offices/corporations have been set up since 1st January, 1964:—

- (1) Committee for the purpose of Controlling and Supervising experiments on animals.
- (2) Agricultural Prices Commission, New Delhi.
- (3) Eastern Regional Station of National Dairy Research Institute, Calcutta.
- (4) Regional Sugarcane Breeding Station, Lucknow.
- (5) Regional Sugarcane Breeding Station, Motihari, Bihar.
- (6) Scheme for Hybridisation of US and Indian Clones Palghat (Kerala).
- (7) Joint Director (Food) Mehtab Road, Cuttack.
- (8) Food Corporation of India.

- (b) Offices mentioned at 1, 2 and 7 have been given Indian names.
- (c) Offices in serial Nos. 3—6 are part of the National Dairy Research Institute, Karnal and the Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore which had been established long before 1-1-64. Their names follow the pattern of other offices under these two Institutes for the sake of uniformity. But even in their cases, Hindi equivalent are also being used. As for the Food Corporation of India, its All-India character and its activities in non-Hindi speaking regions call for both English and Hindi nomenclatures. The question of giving it a Hindi nomenclature is under consideration.

राध्द्रीय राजपथ

.2666. श्री धर्नालगम: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तीसरी योजना ग्रवधि में ग्रब तक जिन राष्ट्रीय राजपथों का विकास किया गया है उनकी मीलों में कुल लम्बाई कितनी है;
 - (ख) मद्रास राज्य में विकसित यह लम्बाई कितने मील है; ग्रौर
- (ग) मद्रास राज्य में राष्ट्रीय राजपथों के विकास में पर्याप्त प्रगति न होने के क्या कारण हैं?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) ग्रब तक 2540 मील का विकास किया गया है।

- (ख) 210 मील।
- (ग) मद्रास राज्य में पर्याप्त प्रगति हुई है।

चावल का प्राप्त करना

$$_{26\ 67.}$$
 $\left\{ egin{array}{ll} श्री बारियर : \\ श्री बासुदेवन प्नायर : \end{array}
ight.$

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछली कटाई ऋतु में क्या सरकार ने केरल राज्य से कुछ चावल प्राप्त किया था; ग्रौर
 - (ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में प्राप्त किया ग्रौर उसका कितना मूल्य दिया?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) ग्रीर (ख). पिछली कटाई ऋतु में रु० 43.71 प्रति विवटल पर लगभग 18,000 मीट्रिक टन ग्रीर चालू फसल ऋतु में ग्रब तक लगभग 27,000 मीट्रिक टन धान रु० 41.00 प्रति विवटल पर मोटी किस्में ग्रीर रु० 42.25 प्रति विवटल पर मध्यम किस्म की धान खरीदी गयी थी।

चावल की बिक्री पर कर

2665. **ेश्रो वारियार**ः **ेश्रो वासु**देवन नायरः

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने केरल में राशन की दुकानों द्वारा वितरित चावल पर ग्रतिरिक्त कर ग्रथवा ग्रधिमार लगाना शुरू किया है; ग्रौर
- (ख) यदि हां, तो उस कर की राशि कितनी है ग्रौर इससे प्रतिमास कितनी व्यय होने की ग्राशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) ग्रौर (ख) किरल सरकार ने राजन की दुकानों पर बेचे जाने वाले चावल ग्रौर गेहूं के थोक स्तर पर एक रुपया प्रति क्विंटल ग्रिधभार लगाया है। इससे लगभग 9 लाख रुपये प्रति मास ग्राय होने की ग्राशा है।

सरसों के बोजों का मूल्य

2669. श्री लखनू भवानी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने किसानों से सरसों खरीदने के लिये इसके भाव निश्चित कर दिये हैं;
- (ख) यदि हां, तो मूल्य का ब्योरा क्या है ग्रीर सरकार द्वारा प्राप्त की गई सरसों की मात्रा क्या है, ग्रीर
- (ग) सरकार की नोति के कारण क्या सरसों के तेल के मूल्य में कुछ परिवर्तन हुग्रा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) श्रौर (ग) प्रश्न नहीं होता ।

ग्रादिवासी खण्डों में सड़ हों

2670. श्री ह० च० सोय: क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या स्रादिवासी खण्डों के कार्यकरण का कोई स्रध्ययन किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो क्या यह महसूस किया गया है कि ऐसे खण्डों को चालू करने के लिये एक मूल शर्त यह होनी चाहिये कि कम से कम खण्ड मुख्यालय को मिलाने वाली ऐसी सकड़ों का निर्माण, जिन पर जीप चलाई जा सकें पहले से ही हो जाये; ग्रौर
 - (ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गऐ हैं?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) विशेष बहु-प्रयोजनीय ग्रादिवासी खंडों संबंधी समिति ने दूसरी योजना में प्रारम्भ किये गये विशेष बहु प्रयोजनीय ग्रादिवासी खंडों की कार्यप्रणाली का विस्तार से ग्रध्ययन किया था। ग्रानुस्चित क्षेत्रों तथा ग्रानुस्चित ग्रादिम जातियों संबंधी ग्रायोग ने भी उन खंडों तथा तीसरी पोजना में ग्रारम्भ किये गये ग्रादिवासी विकास खंडों की कार्यप्रणाली की जांच की है।

(ख) ग्रोर (ग). ग्रादिवासी विकास खंड चालू करने के लिये यह एक पूर्व गर्त नहीं है कि खंड मुख्यालयों को मिलाने वाली ऐसी सड़कों का निर्माण हो जिन पर जीप चलाई जा सके । यह सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों को पहले ही हिदायतें जारी की गई हैं कि ग्रादिवासी विकास खंड चालू करने से पहले खंड मुख्यालयों को जिला या तहसील मुख्यालयों से उचित रुप से मिलाये जाये । सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा ग्रादिवासी विकास खंड के लिये नियत किये गये पहले चरण में 10 लाख रुपया तथा दूसरे चरण में 5 लाख रुपये के ग्रतिरिक्त परिव्यय में से संचार के लिये प्रथम चरण में 2 लाख रुपये तथा दूसरे चरण में एक लाख रुपये को व्यवस्था की गई है।

ग्रादिवासी खण्ड

2671. श्री ह० च० सोय: क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि पहाड़ी ग्रादिसावी खंडो में विभिन्न योजनाग्रों की देख-रेख तथा कार्यान्विति में अन्दरूनी क्षेत्र को खंड मुख्यालय से मिलाने वाली जीप चलाने योग्य सड़कों की बहुत अधिक कमी के कारण बहुत अधिक बाधा तथा देरी होती है;
- (ख) क्या ग्रादिवासी खंडों में निर्धारित राशि के कम खर्चा होने का एक कारण ग्रादिवासी लोगों की ग्रोर क्षेत्र कर्मचारियों तथा कार्यालय कर्मचारियों का ग्राम तौर से ग्रसहानुभूतिपूर्ण तथा उदासीन खैया भी है ;
- (ग) क्या यह सच है कि बिहार तथा उड़ीसा जैसे राज्यों में श्रनुसूचित श्रादिम जातियों के लोग पर्याप्त संख्या में जिन्हें क्षेत्र कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है; श्रौर
- (घ) क्या ग्रादिवासी खंडों के क्षेत्र तथा कार्यालय कर्मचारियों के लिये खंड विकास ग्राधिकारी पुनरनुस्थापन प्रशिक्षण की तरह की प्रशिक्षण सुविधायों की कोई व्यवस्था नहीं है यदि हां तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गये हैं?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) श्राविसासी विकास खंड में संचार योजनाश्रों के लिये ग्रादिवासी विकास खंड ग्राव्ययक में 2 लाख रुपये की तथा सामुदायिक विकास खंड ग्रायव्ययक में 1.34 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। ग्रादिवासी विकास खंड के सभी ग्रन्दरुनी क्षेत्रों को विशेष कर पहाड़ी क्षेत्रों में खंड मुख्यालय के साथ मिलाने के लिये जीप योग्य सड़कों का जाल बिछाने के लिये यह राशि पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक देहात को पगंडडी तथा गड़डे

योग्य सड़कों से देहातो स्तर तल सर्किल मुख्यालय के साथ तथा देहाती स्तर पर सर्किल मुख्यालय को गड्डे तथा जीप योग्य सड़कों से खंड मुख्यालय के साथ मिलाने पर सामान्य बल दिया गया है। इस से पहाड़ी भ्रादिवास खंडों में योजनायों की देखरेख तथा कार्यान्विति काफी हद तक सुनिश्चत है जाती है।

- (ख) ग्रादिवासी विकास खंडों में काम करने वालों को ग्रादिमजातियों के रहन सहन तथा उनकी संस्कृति के बारे में पुनरनुस्थापन प्रशिक्षण इसिलये दिया जाता है तािक उनमें ग्रादिम जाितयों के प्रति सहानुभूति की भावना पैदा हो इस बात को विवरण में स्पष्ट करना किठन है कि ग्रादिवासी खंडों में निर्धारित रािश के कम खर्च करने का कारण क्षेत्र कर्मचािरयों का ग्रासहानुभूतिपूर्ण तथा उदासीन रवैया है।
- (ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासकों को हिदायतें जारी की गई हैं कि वे स्रादिवासी क्षेत्रों में क्षेत्र स्रिताराप्त स्रादिवासियों को प्राथमिकता दे।
- (घ) खण्ड विकास ग्रधिकारियों तथा श्रादिवासी विकास खण्डों में विस्तार ग्रधिकारियों को रांची, जबलपुर, उदयपुर तथा भूवनेश्वर में सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय द्वारा चालू किये गये ग्रादिवासी पुनरनुस्थापन तथा प्रशिक्षण केन्द्रों में पुनरनुस्थापन प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरे कर्मचारियों को केन्द्रीय सहायता से कुछ राज्य सरकारों द्वारा स्वयं चलाई गई ग्रादिवासी गवेषणा तथा प्रशिक्षण संस्थाग्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे राज्यों/पंघ राज्य-क्षेत्रों में जहां यह व्यवस्था नहीं है वे ग्रपने कर्मचारियों को पड़ोसी राज्यों में या निकटतम राज्यों में भेज देते हैं। ग्रादिवासियों के रहन-सहन तथा संस्कृति का पुनरनुस्थापन प्रशिक्षण, सामुदायिक विकास खण्डों में सामान्य प्रशिक्षण के ग्रतिरिक्त है।

श्रादिम जाति विकास खण्ड

- 2672. श्री ह० च० सौय: क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे
- (क) क्या यह सच है कि ग्रादिम जाति विकास खण्डों के लिये नियत की गई राशि में से शिक्षा ग्रीर ग्राथिक उत्थान की योजनाग्रों के लिये जो धन व्यय किया गया उस पर प्रत्येक राज्य में ग्रलग-ग्रलग महत्व दिया गया है जैसा कि मंत्रालय की वर्ष 1964-65 की वार्षिक रिपोर्ट के व्यय के ग्रांकड़ों में दिखाया गया है;
 - (ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) श्रौर (ख). सामाजिक सुरक्षा विभाग की 1964-65 की वार्षिक रिपोर्ट में श्रादिवासी विकास खण्डों में शिक्षा श्रौर श्राधिक उत्थान की योजनाश्रों के बीच किये गये व्यय के पृथक पृथक श्रांकड़े नहीं दिये गये हैं।

तथापि म्रादिवासी विकास खण्डों के में कार्यक्रम म्राधिक विकास की योजनाम्रों को शिक्षा योजनाम्रों की तुलना में म्रधिक प्राथमिकता दी जाती है।

ग्रादिवासी विकास खण्ड

2673. श्री ह० च० सौय: क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

- (क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के मघ्यकालीन मूल्यांकन प्रतिवेदन में इस विषय पर दिये गये विवरण के पश्चात्, ग्रादिवासी विकास खण्डों के खोले जाने तथा उनके कार्य करने से ग्रादिवासी लोगों पर हुए ग्राथिक प्रभाव का कोई मूल्यांकन ग्रथवा ग्राध्ययन किया गया है;
- (ख) ग्रादिवासी खण्डों के लिये चौथी योजना में वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने का ग्रायिक ग्राधार क्या है; ग्रौर

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) तीसरी योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन प्रतिवेदन के छप जाने के बाद से ग्रादिवासी विकास खण्डों के कार्यक्रम के, ग्रादिवासी लोगों पर हुए, ग्राधिक प्रभाव का कोई विशेष मूल्यांकन ग्रथवा ग्रध्ययन नहीं किया गया है। फिर भी योजना ग्रायोग, राज्य सरकारों ग्रौर ग्रनुसूचित जातियों तथा ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियों के ग्रायुक्त कार्यालय द्वारा समय समय पर इन खण्डों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा विभाग में पिछड़े वर्गों के कल्याण निदेशक को ग्रादिवासी विकास खण्डों की कार्यप्रणाली का विस्तृत ग्रध्यन करने का काम भी सौंप दिया गया है।

(ख) ग्रौर (ग). ग्रादिवासी विकास खण्ड के लिये, सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा, नियत की गई राशि के लिये किसी दुष्परिवर्तनशील योजनायुक्त ग्रायव्ययक की व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि इस प्रयोजन के लिये निम्नलिखित मुख्य तरीका ग्रपनाया गया है:——

(लाख रुपयों में)

	व्यवस्था ग्रादिवासी विकास स्रादिवासी विकास		
व्यय शीर्षक		आदिवासा विकास चरण दो के दौरान	
 मोटरगाडियों की खरीद तथा परियोजना कार्यालय के 			
कर्मचारी	2.00	1.00	
2. ग्रार्थिक विकास	4.80	2.40	
8. संचार .	2.00	1.00	
4. सामाजिक सेवायें	1.20	0.60	
योग	10.00	5.00	

जपर दी गई सारणी से यह स्पष्ट हो जायेगा कि मोटर गाड़ियों तथा परियोजना कार्यालय के कर्मचारियों के लिये व्यवस्था करने के पश्चात् प्रथम चरण में 8 लाख रुपये तथा दूसरे चरण में लाख रुपये के सन्तुलन का शेष योजनाम्रों में प्रतिशत वितरण इस प्रकार है :---

स्राधिक विकास संचार सामाजिक सेवायें

60 प्रतिशत

25 प्रतिशत

15 प्रतिशत

चौथी योजना में इसी तरीके के ग्रपनाये जाने की सम्भावना है।

पर्यटक कर्मचारियों का प्रशिक्षण

2674. श्री श्रीनारायण दास : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पर्यटक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये संयुक्त राष्ट्र ग्रिभिकरणों तथा कोलम्बी योजना के ग्रन्तर्गत दी जाने वाली ग्रिधिछात्रवृत्तियों से लाभ उठाने तथा उनका लाभ पहुंचाने में भारत कहां तक सफल हुग्रा है;
- (ख) क्या विदेशी पर्यटकों के सम्पर्क में स्राने वाले सभी सरकारी विभागों में पूर्ण स्रर्हता प्राप्त तथा पूरी जानकारी रखने वाले कर्मचारियों की उपलब्धता के बारे में कोई स्रनुमान लगाया गया है; स्रीर
 - (ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ग्रभी तक पर्यटन विभाग के दो ग्रिधकारियों ने संयुक्त राष्ट्र ग्रिधछात्रवृत्तियों से लाभ उठाया है।

1962 से इकाफे देशों से पर्यटक ग्रिधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये कोलम्बो योजना के ग्रन्तर्गत पर्यटक विभाग ने तीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संगठन किया है। इन पाठ्यक्रमों में 26 ग्रिधिकारी प्रविष्ट हुए।

(ख) श्रौर (ग) विदेशी पर्यटकों के सम्पर्क में श्राने वाले राजस्व श्रौर श्रप्रवासी कर्मचारियों के सम्बन्ध में 1963 में पर्यटन पर तदर्थ समिति ने इस बारे में प्रारम्भिक निर्धारण किया था। पर्यटन विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा यात्रा व्यापार के पर्यटक श्रधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये पाठ्यक्रम की व्यवस्था करता है। खाद्य श्रौर कृषि मंत्रालय ने होटल प्रबन्ध श्रौर खान पान प्रबन्ध के बारे में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये हैं जो होटलों में तथा इस उद्योग के संश्रित अनुभागों की प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग की पूर्ति करते हैं।

पंजाव में कृषि स्रोद्योगिक निगम

2675. श्री राम सहाय पाण्डेय : श्री ल० ना० भंजदेव:

क्या लाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित कृषि ग्रौद्योगिक निगम में केन्द्र के ग्रंश को बढ़ाने की संघ सरकार से प्रार्थना की है; ग्रौर (ख) यदि हां, तो इस मामले मैं क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। पंजाब सरकार ने र्जि निवेश के 50 प्रतिशत भाग के लिए अंशदान मांगा है जबकि भारत सरकार ने 25 प्रतिशत की पेशकश की थी।

(ख) राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है कि इस प्रार्थना पर विस्तृत योजना के प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा । यह योजना स्रभी प्राप्त होनी है ।

Fodder for Cattle

- 2676. Shri Sidheshwar Prasad: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- (a) whether Government's attention has been drawn to the fact that pastures are gradually becoming extinct in our Country;
- (b) whether Government's attention has also been drawn to the fact that due to the scarcity of fodder the breeding of cattle is generally deteriorating; and
- (c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the arrangement being made for the supply of sufficient fodder for the cattle?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b). While it is generally known that the quality of grazing has declined due to over-grazing in some areas and that mal-nutrition is one of the causes of lack of breeding among cattle, it is not quite correct to say that the pastures are becoming extinct and that the breeding of cattle is generally deteriorating.

- (c) The Government of India and State Governments have taken various measures for increasing the production of feeds and fodder and improvement of grazing areas. Some of the important measures are as under:—
 - (i) A scheme for the development of feeds and fodder resources has been taken up in various States under the Third Five Year Plan.
 - (ii) A Centrally sponsored scheme for the establishment of Fodder Banks has been sanctioned. Under this scheme, a Fodder Bank has been established at Dhulia in Maharashtra and the proposal for establishment of one Fodder Bank each in Andhra Pradesh and Bihar has been sanctioned.
 - (iii) A Fodder Research Scheme for evolving suitable and high yielding variety of grasses and fodder crops have been sanctioned by the Indian Council of Agricultural Research in a number of States.
 - (iv) The Government of India have established the Indian Grassland and Fodder Research Institute at Jhansi in November, 1962. This Institute, when fully established

will collect research information on all aspects of grassland and fodder development, and utilisation, co-ordinate research on this subject in the country and also train up personnel both for research and extension.

(v) A number of States have set up State Fodder and Grazing Committees with official and non-official members, with a view to devoting increased attention to the problems of feeds and fodder development. A Standing Committee has also been set up in the Ministry of Food and Agriculture to review the work connected with the development of feeds and fodder resources in the country.

फलों का चूर्ण बनाने वाला कारलाना

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या जलगांव (महाराष्ट्र) में परिष्करण संयंत्र कुछ फलों का चूर्ण बनाने का कार्य ग्रारम्भ करेगा;
 - (ख) क्या संयंत्र केले, ग्राम तथा प्योते का चूर्ण तैयार करेगा; श्रौर
- (ग) यदि हां, तो क्या परीक्षण के तौर पर किया गया उत्पादन सन्तोषजनक रहा है तथा क्या उत्पादन स्रन्तर्राष्ट्रीय बाजारों को निर्यात किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :(क) जवगांव जिला सहकारी विपणन समिति ने केले का चूर्ण बनाने के लिये जलगांव में एक कारखाना स्थापित किया है।

- (ख) जी, हां; सिमिति ने केला, स्राम ऋौर पपीता का चूर्ण बनाने के लिये परीक्षण किये हैं।
- (ग) सिमिति ने परीक्षण के तौर पर किये गये उत्पादों के गुण जानने के लिये भारत ग्रीर डंनमार्क की प्रयोगशालाग्रों को नमूने विश्लेषण के लिये भेजे हैं किन्तु परिणाम ग्रभी प्राप्त नहीं हुए । सिमिति द्वारा उत्पादित फल चूर्ण को अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में भी भेजने का विचार हैं।

Breeding of Pigs

- 2678. Shri Baswant: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:
- (a) the number of States in which pig breeding scheme has been implemented;
- (b) whether any particular scheme for increasing the reproduction of pigs is under consideration; and
 - (c) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (c). Under the Second and Third

Five-Year Plans and the Special Development Programme recently sponsored by the Government of India, piggery development scheme has been taken up in all States|Union Territories except Gujarat, Jammu & Kashmir, Nagaland, NEFA, Andamans and Laccadive.

Three regional pig breeding stations have been set up in U.P., West Bengal and Maharashtra while one more is being set up in Andhra Pradesh. Each station is expected to produce about 1000 stud boars annually for distribution to State pig breeding units piggery development blocks. All the stations are expected to have bacon factories attached to them. The establishment of similar stations in Bihar, Kerala and Rajasthan has recently been approved by the Government of India.

Under the second phase of the piggery development scheme, 24 pig breeding units each with a foundation stock of 30 sows and 6 boars of exotic breed have been set up all over the country. The superior stock produced at these units is distributed in the piggery development blocks 82 of which have been established. The establishment of two pig breeding farms in Madras and U.P. and 10 piggery development blocks in U.P. has also recently been approved.

Prices of Sugar-Cane

2679. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

- (a) whether Government have fixed the prices of sugar-cane for 1965-66; and
 - (b) if so, when the rates so fixed will be announced?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan): (a) Not yet, Sir.

(b) The minimum sugarcane price payable by sugar factories in 1965-66 season will be announced before the commencement of that season.

ग्रनाज का परिवहन**ं**

श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री किशन पटनायक : 2680 र्शी स० मो० बनर्जी : श्री नवल प्रभाकर : श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या खाध तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1961, 1962 ग्रौर 1963 के दौरान टेंडरों की गलत गणना करने ग्रौर कार्यग्रादेशों की कार्यान्विति के कारण बम्बई, कांडला ग्रौर विशाखापट्टनम के पत्तनों को निम्नलिखित केन्द्रीय भंडार डिपों पर ग्रनाज के परिवहन मैं गड़बड़ी के कारण सरकार को कुछ हानि उठानी पड़ी;

दिल्ली, हरडोया गंज, मेरठ, कानपुर, इताहाबाद, ग्रागरा, शाह्जहांपुर, हैरराबाद, हापुड़, बरेली, लखनऊ, बाराबंकी, मतौदा, इटाबा, राजपुर, ग्रजमेर, बोकानेर, नागुर ग्रौर बम्बई।

- (ख) क्या इस विषय में किसी जांच के लिये ब्रादेश दिया गया है;
- (ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है; ग्रीर
- (घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ग्रथवा करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय म उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं । खाद्यान्नों की सम्भाल ग्रीर ढुलाई के ठेके, सामान्य नियम के ग्रनुसार, टेंडर देने वालों के सामने टेंडर खोलकर, सब से कम टेंडर देने वाले को दिये जाते हैं । पहले टेंडर देने वालों को काम की प्रत्येक मद के लिए दरें बतानी पड़ती थीं ग्रीर कुछ टेंडर देने वाले काम की कुछ मदों के लिए कम दरें ग्रीर कुछ के लिए अंची दरें बताते थे । टेंडर ग्रामंत्रित करते समय पूर्वानुमानित कार्य के प्रतिरूप के ग्राधार पर प्रत्येक टेंडर देने वाले द्वारा बतायी गयी दरों से सरकार की तुलनात्मक लागत बना ली जाती थी । ठेके की ग्रवधि में कभी कभी काम का प्रतिरूप एक या दूसरे कारण से बदल जाता तो उस से ठेके देने के समय में लागत की की गयी मूल गणना में कुछेक मामलों में गड़बड़ी हो जाती थी । इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक नई पद्धित लागू की गयी है जिसके ग्रन्तर्गत टेंडर फार्मों में प्रत्येक सेवा के लिए श्रनुसूचित दरें दी जाती हैं ग्रीर टेंडर देने वालों के लिए यह ग्रपेक्षित है कि वे श्रनुसूचित दरों से एक प्रतिशत ग्रधिक या कम दर जिस पर या उसके बराबर दरों पर वे काम करने के लिए तैयार हों, बतावें । इससे काम के पूर्वानुमानित प्रतिरूप में परिवर्तन होने से तुलनात्मक लागत की गणना में होने वाली गड़बड़ी की सम्भावना दूर हो गयी है ।

(ख), (ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

कलकत्ता-भ्रासाम रिवर्स स्टीम नेवीगशन कम्पनी

 \int श्री प्र० चं० ब \mathbf{t} ग्राः $\mathbf{2}^{681}$ श्री श्रोंकार ल ल बेरवाः

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) स्टीमर सर्विसों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वित्तीय प्रश्नों पर विचार करने के लिये क्या 8 ग्रीर 9 ग्रप्रैल को भारत ग्रीर पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों तथा कलकत्ता-ग्रासाम रिवर्स स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के प्रबन्धकों ग्रीर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक बुलाई गई थी; ग्रीर
- (ख) यदि हां, तो वहां किन विशेष विषयों पर विचार हुम्रा स्रौर उसके क्या परिणाम िकले ?

परि हन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

- (ख) पाकिस्तानी कर्मीदल की निम्नलिखित मांगों पर विचार विमर्श हुआ था :--
 - 1---सब पाकिस्तानी कर्मचारियों की मजदूरी का 50 प्रतिशत तथा उपदान, भविष्य निधि, क्षतिपूर्ति का भुगतान पाकिस्तान में किया जाये ; ग्रौर
 - 2---ग्रब जितने पदों पर पाकिस्तानी राष्ट्रिक हैं उन पर पाकिस्तानी ही रहेंगे जब तक कि कोई पद मृत्यु, निवृत्ति, इस्तीफा, पदच्युति के फलस्वरूप रिक्त न हो ग्रौर उसी दशा में उस पर गैर-पाकिस्तानी नियुक्त किया जा सकेगा।

निम्तलिखित निर्णय किये गये :---

(1) मजदूरी:

- (क) चंिक मौजूदा विनिषयों के अन्तर्गत जो पाकिस्तानी राष्ट्रिक कम्पनी में नियुक्त हैं उन में से अधिकांश रिजर्व बैंक आफ इंडिया से बिना किसी प्रकार की विशेष इजाजत अप्त किये 50 रुपये प्रति मास अपने परिवारों को भेज सकते हैं और इससे अधिकांश कर्मधारियों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, अतः यह निर्णय हुआ कि इस सम्बन्ध में तुरन्त ही किसी प्रकार के विशेष परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।
- (ब) जहां तक बेड़ा-कर्मवारियों का सम्बन्ध है, जिनकी मजदूरी भत्ता मिला कर 150 रुपये मासिक या उससे अधिक है पाकिस्तान में उनके परिवारों के खर्चे के लिये 50 रुपये मासिक अपर्याप्त समझा गया। अतः यह सिफारिश की गयी कि जिन कर्मचारियों को भत्ता मिलाकर 150 रुपये मासिक या अधिक मजदूरी मिलती है उन्हें विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के ढांचे के भीतर, बजाय 50 रुपया मासिक के अपनी मजदूरी का 50 प्रतिशत और अधिकतम 250 रुपये भेजने की अनुमति दे दी जाये।
- (ग) जिन बेड़ा-कर्मचारियों को 150 रुपये मासिक से कम् मजदूरी मिलती है उन की स्थितिसे सम्बन्धित प्रश्न बाद में विचार-विमर्श करने के लिये खुला रखा गया है ।

(२) निषृत्ति लाभः

(क) भविष्य निधि में जमा पूजी भ्रीर उपरान का भुगयतान

सिमित ने सिकारिश की कि कर्मचारियों की भिविष्यनिधि ग्रौर उपदान के रूप में पाकिस्तान में (208868.81 ह०) ग्रौर भारत में (114665.04 ह०) जमा राशिया एक देश से दूसरे देश में लौटाने की अनुजा दी जाये ग्रौर दोनों ग्रोर के बाकी दावे निबटा दिये जायें। पाकिस्तान की जो राशि भारत में है उसे भारत की पाकिस्तान में स्थित राशि से निकालने के बाद बाकी बची 94200 ह० की राशि का निबटारा समानता के ग्राधार पर नीचे (ख) में दी गयी रीति से किया जा सकता है। इन राशियो का दोनों देशों में कम्पनी के खातों से सत्यापन होना है।

(ख) भविष्य में निवृति देय का भुगतान

यह निर्णय हुन्रा कि कम्पनी के कर्मचारियों की समस्याएं पारस्परिकता के सिद्धान्त के स्राधार पर निपटायी जा सकती है। ग्रतः उसकी यह भावना थी कि कम्पनी के कर्मचारियों के निवृत्ति देय पाकिस्तान को भेजने की ग्रनुमित दी जाय बगर्ते उन भारतीय रायष्ट्रिकों के निवृत्ति देय भी समानता के ग्राधार पर भारत भेजने की ग्रनुमित दी जाये, जिन्होंने गैर सरकारी संस्थानों में सेवा की ग्रीर जो पहले निवृत्त हो गये थे।

२---पाकिस्तानी राष्ट्रकों का श्रपने पदों पर बना रहना

यह तय हुन्ना कि दोनों सरकारों के बीच, जिसमें समुचित स्तर के प्रतिनिधि भाग लेंगे, शीघ्र ही होने वाली बैठक में विचार विमर्श के लिये यह प्रश्न खुला रखा जाय ।

Ban on Pounding of Rice

2682. Shri Rananjai Singh: Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

- (a) whether there is any proposal under Government's consideration to lift the ban on the pounding of paddy by mechanised methods in the rural areas with a view to remove the scarcity of rice and to increase its production in the country; and
 - (b) if so, when the ban is likely to be lifted?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan): (a) There is no ban as such on the pounding of paddy by mechanised methods.

(b) Does not arise.

खाद्य भण्डार

2683. श्री दी० चं० शर्मा: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या म्रास्ट्रेलिया सरकार से खाद्य का रक्षित भण्डार बनाने में भारत की सहायता करने के लिये कहा गया है ; ग्रौर
 - (ख) यदि हां, तो इस पर उस सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) समीकरण भण्डार तैगर करने के लिये ग्रास्ट्रेलिया के प्राधिकारियों के साथ कुछ विशेष प्रबन्धों के ग्रधीन गेहं सप्लाई करने के बारे में ग्रनीपचारिक बातचीत हुई बी।

(ख) इस समय ग्रास्ट्रेलिया सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में बताना सम्भव नहीं है क्योंकि । ।मला ग्रभी भी उनके विचाराधीन है ।

बिहार पलाइंग क्लब के विमान का विवशतावश उतरना

 \int श्री तुला राम ः 2684 े श्री विश्वनाथ पाण्डेय ः

क्या ग्रसैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे पिक :

- (क) क्या यह सच है कि पटना फ्लाइंग क्लब का टाइगर मोथ विमान को 11 अप्रैल, 1965 को सदाकत आश्रम, पटना के सामने गंगा की रेती में विवशतावश उतरना पड़ा और विमान में बैठे कुछ व्यक्तियों को चोटें आईं;
 - (ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या हैं ; स्रौर
 - (ग) इस कारण कुल कितनी हानि हुई ?

ग्रसैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो): (क) भारत सरकार का एक टाइगर माउथ विमान को, जो बिहार फ्लाइंग क्लब, पटना द्वारा चलाया जा रहा था, 11 ग्रप्रैल, 1965 को पटना हवाई ग्रड्डे के 8 मील पूर्व में, गंगा के पूर्वी किनारे पर जबरदस्ती उतरना पड़ा। विमान ट्रेनिंग उड़ान के समय ग्रस्त हो गया ग्रौर विमान में बैठे एक इन्स्ट्रक्टर ग्रौर विद्यार्थी चालक क मामूली चोट ग्राई।

- (ख) दुर्घटना की जांच की जा रही है।
- (ग) विमान को भारी क्षति पहुंची है स्रौर इससे भारी नुक्सान हो सकता है।

श्रास्ट्रेलिया से उपहार के रूप में बेकरियां

 2^{685} श्री तुला राम ः 2^{685} श्री विशवनाथ पाण्डेय ः

वया लाद्य तथा कृषि मत्नी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि ग्रास्ट्रेलिया सरकार कोलम्बो योजना के ग्रन्तर्गत भारत को उपहार के रूप में छः स्वचालित बेकरियां दे रही है ;
 - (ख) यदि हां, तो कब तथा उनका कुल मूल्य कितना है ; ग्रौर
 - (ग) ये क्षेकरियां भारत में कहां कहां स्थापित की जायेंगी ? खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां।
- (ख) 6 स्वचालित बेकरियों की कीमत 250,000 ग्रास्ट्रेलियन पौण्ड है ग्रौर इन की शीघ्र सप्लाई होने की ग्राशा है।
- (ग) इन 6 बेकरियों को कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, दिल्ली, ग्रहमदाबाद श्रौ एरनाकलम में स्थापित करने का विचार है ।

गोबर का इँधन के का में प्रयोग

श्री रा॰ बरुग्रा :
श्री कोया :
2686. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री बूटा सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले गोबर की मात्रा का कोई ग्रनुमान लगाया गया है ; ग्रीर
- (ख) यदि हां, तो दूसरा सस्ता ईंधन देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि गोबर का खाद के रूप में प्रयोग किया जा सके ?

खाद्य तथा कृषि मंत्राजय में उरमंत्री (श्रो शाह नवाज खां) : (क) जी, हां । व्यावहारिक ग्रर्थशास्त्र गवेषणा सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् द्वारा किये गये ग्रध्ययन के ग्रनुसार देश में कुल गीला गोबर लगभग 13350 लाख टन होता है जो 2670 लाख टन सूखे गोबर के बराबर होता है । परिषद् ने यह ग्रनुमान लगाया है कि 522 लाख टन सूखा गोबर (कुल उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत) ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

- (ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रार्थना की है कि वे वैकल्पिक सस्ता ईंधन देने के लिये निम्नलिखित उपाय करें :--
 - (एक) गोबर की गैस के संयंत्रों को लगाना जो किसान की ईंधन तथा खाद की स्राव-श्यकतास्रों को पूरा करते हैं।
 - (दो) देहातों में शामलात भूमि पर, बेकार पड़ी भूमि पर तथा खेतों की सीमाम्रों पर, जल्दी उगने वाले वृक्षों को तथा जंगलों का लगाना । इस के म्रतिरिक्त राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे कच्चे कोक के डिपुम्रों म्रादि के सम्बन्ध में उदार नीति वस्त कर कच्चे कोक का इंधन के रूप में म्रधिक प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहन दें ।

सांताकूज हवाई म्राड्डे पर रेडार सहायक-यंत्र

2687. श्री दी० चं० शर्मा: क्या श्रासैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या बम्बई के सांताऋूज हवाई ग्रड्डे पर ग्रधिक ग्रच्छा रडार सहायक-यंत्र लगाया जा रहा है ; ग्रीर
 - (ख) यदि हां, तो उस की विशेषताएं क्या हैं?

ग्रसैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो): (क) ग्रौर (ख). यथावत् ग्रवतरण रेडार (पी० ए० ग्रार०) सांताक्रूज हवाई ग्रड्डे पर लगाया जा रहा है। वर्तमान हवाई ग्रड्डा निगरानी रेडार

(ए० एस० ग्रार०) के साथ पूर्ण थल नियंत्रित पहुंच (जी०सी०ए०) प्रणाली की व्यवस्था भी होगी। प्रिसीजन ग्रप्रीच राडार (पी०ए०ग्रार०) से पायलट पूर्वनिश्चित एथ पर रनवे की समाप्ति के स्थान पर ग्रासानी से उतर सकें। इससे विमान यातायात कंट्रोलरो को विमान के रेन्ज के ग्रांकड़ों के बारे में मालूम हो सकेगा कि विमान रनवे पर उतरने के स्थान पर वायु में 10 मील से नीचे ग्रा सकता है या नहीं। इस जानकारी से विमान यातायात कंट्रोलर पायलटों को उतरते समय दाहिने बायें, ऊपर-नीचे ग्रादि के बारे में हिदायतें दे सकते हैं।

Purchase of Dairy Equipment From Sweden

2688. Shri Tula Ram:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

- (a) whether Government have sent a team officers to Sweden in connection with the purchase of dairy equipmnt from that country; and
 - (b) if so, the particulars of the officers included in the said team?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Yes.

- (b) (i) Dr. K. K. Iya, Dairy Development Adviser.
 - (ii) Shri V. A. Mehta, S. T. C. representative in Homand and
 - (iii) Shri D. N. Chaudhuri, Joint Financial Adviser, State Trading Corporation.

मद्रास में भाण्डागार

2689 श्री धर्म लिंगम : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) मद्रास राज्य में इस समय केन्द्रीय भाण्डागारों की संख्या कितनी है ऋौर उनमें कितना माल रखा जा सकता है ;
 - (ख) क्या उन की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है ; श्रौर
 - (ग) यदि हां, तो काम कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा• चव्हाण)ः (क) इस समा-चार केन्द्रीय भाण्डागार हैं जिनकी कुल क्षमता 10,528 टन है।

- (ख) जी, हां । 2,23,690 टन की क्षमता बढ़ाने का विचार है।
- (.) कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

मद्रास में समाज कल्या ण

2690. श्री धर्नीलगम : क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क') 1963-64 तथा 1964-65 में मद्रास सरकार को समाज कल्याण विस्तार परि-योजनाम्रों, सामाजिक तथा नैतिक म्रारोग्य भ्रौर बाद की देखभाल के कार्यक्रम के लिये कितनी रकम की केन्द्रीय सहायता दी गई ; स्रौर
 - (ख) इस सम्बन्ध में वास्तव में कितनी रकम खर्च हो चुकी है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) ग्रीर (ख) ग्रपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है:

	मंजूर की गई राशि	खर्च की गई राशि
	रुपये	र.पये
(एक) कल् याण विस्तार परियोजनायें 1963—64 1964—65	*कोई नहीं *कोई नहीं	कोई नहीं कोई नहीं
(दो) सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य विज्ञान स्रौर उत्तर-स्रवेक्षा कार्यक्रम		
1963-64	22,000.00	जानकारी एकत्नित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।
1964-65	* * कोई नहीं	कोई न हीं ।

^{*}मद्रास सरकार योजना को लागू नहीं कर रही है।

**केन्द्रीय सहायता इसलिये नहीं दी गई क्योंकि मद्रास सरकार ने 1963-64 में वास्त-विक व्यय तथा 1964-65 में ग्रनुमानतः व्यय नहीं किया ।

देहाती कार्यक्रम प्रोग्राम

- 2691. श्रीश्रीनारायण दास: क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) चालू वर्ष में ग्रारम्भ की जाने वाली देहाती कार्य प्रोग्राम योजना की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ;
 - (ख) इस योजना के ग्रन्तर्गत कितना क्षेत्र ग्रायेगा ; ग्रौर
 - (ग) इस प्रयोजन के लिये विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि नियत की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब॰ सू॰ मूर्ति): (क) व (ख) चालू वर्ष में इस कार्यक्रम को नए खंडों में लागू नहीं किया जायेगा। इसे सुदृढ़ करने ग्रौर प्रबल बनाने पर बल दिया जा रहा है। राज्य सरकारों को भी कहा जायेगा कि वे कुछेक चुने हुए खंडों, जहां यह कार्यक्रम चल रहा है, को गहन कार्य की गुंजाइश का ग्रध्ययन करने ग्रौर भावी ग्रायोजन के प्रतिमान स्थापित करने के लिए लें।

(ग) चालू वर्ष के लिये राज्यों को जो धनराशि दी जानी है, उस का विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। [देखिये संख्या एल० टी०-4287/65]।

ग्रविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ग्रोर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बाराहोती के निकट चीनी सेना के भारी जमाव के समाचार

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I call the attention the of the Minister of Defence on the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

"Reported heavy concentration of Chinese troops near Barahoti".

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): ग्रध्यक्ष महोदय, सदन को मालूम है कि हमारी उत्तरी सीमाग्रों के साथ साथ चीनी सेनाग्रों का जमाव है। कुछ समय पहले, मैंने सहायी यूनिटों तथा ग्रन्य सेनाग्रों सिहत जो वहां जमा हैं, 13 से 16 चीनी डिवीजनों का उल्लेख किया था। ग्रक्तूबर—नवम्बर 1962 के ग्रतिलंघन के समय काम में लाए गए सैनिकों से, उनकी शक्ति कई बार ग्रधिक रही है, ग्रौर है। मुझे विश्वास है, कि सदन हर स्थान पर चीनियों द्वारा नियुक्त की गई वास्तविक सैनिक शक्ति व्यक्त करने की प्रत्याशा नहीं करेगा। तदिप, मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं, कि बाड़ाहोती के सामने चीनियों द्वारा पांच डिवीजनों की नियुक्ति ग्रत्युक्ति है। हमें ऐसी भी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कि चीनियों ने बाड़ाहोती के निकट कोई हवाई ग्रहुा बना लिया है। तदिप इस बात की हमें जानकारी है, कि उन्होंने कई ग्राधुनिक हवाई ग्रहुों का निर्माण कर लिया है, ग्रौर कईयों में सुधार भी; साथ ही उन्होंने तिब्बत के विभिन्न क्षेत्रों में विमान उतारने के लिए पट्टियों का भी निर्माण कर लिया है।

2. यह सच नहीं है, िक बाड़ा होती क्षेत्र में चीनी ग्रौर पाकिस्तानी एजेंट काम कर रहे हैं, जिस से स्थानीय जनता में ग्रांतक फैलता है। यह भी सच नहीं है, िक उस क्षेत्र से ग्रिधिक संख्या में लोग भाग गए हैं। बाड़ाहोती डेढ़ वर्ग मील का एक छोटा सा चरागाह क्षेत्र है, जिस में कोई ग्राबादी नहीं है, परन्तु जहां तक ग्रास पास के भी क्षेत्रों की ग्राबादी का प्रश्न है, उस में किसी प्रकार का ग्रांतक नहीं छाया है, ग्रौर रिपोर्ट का यह ग्रंश बिलकुल गलत है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know whether Government will be pleased to apprise this House of the exact deployment or

(Shri Hukam Chand Kachhavaiya)

the extent of the heavy concentration of the Chinese troops on the northern border of India including Barahoti; whether there is any connection between this concentration and the attack made by the Pakistanis troops in Kutch; and whether it is also a fact that this information was received late by the Government and it was given to the public after much delay?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि मैंने ग्रपने वक्तव्य में सेना के जमाव के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : केवल इस बात का उत्तर देना शेष है कि क्या सेनाग्नों के उस जमाव का कच्छ में पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे ग्राक्रमण से किसी प्रकार कोई सम्बन्ध है।

श्री यशवन्तराव चह्नाण: मैं ग्रामतौर पर यही कह सकता हूं कि वहां पर चीनी सेनाग्रों का जमाव कुछ समय पूर्व से हो रहा है । पाकिस्तान सीमा पर जो कुछ हो रहा है उसका इससे ग्रवण्य ही सम्बन्ध होगा । यह स्वयं निष्कर्ष निकालने ग्रौर स्थिति का मूल्यांकन करने का प्रश्न है । ग्रौर हम समय-समय पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Sir, one part of my question regarding late receipt of information pertaining to the concentration of Chinese troops there, still remains to be answered.

Shri Y. B. Chavan: There was no delay anywhere.

श्रीमती रेणुका बड़कटकी (बारपेटा) : क्या चीन बाराहोती क्षेत्र में भारी संख्या में ग्रपनी सेनाग्रों का जमाव करके वास्तिविक नियंत्रण रेखा को पाकिस्तान की ग्राड़ में ग्रपने हक में बदलने का प्रयत्न कर रहा है क्योंकि वह समझता है भारतीय सेनाग्रों का ध्यान कुछ कच्छ की ग्रोर केन्द्रित है; ग्रौर यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में चीन की इस चाल को कामयाब न होने देने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है?

श्री यशवन्तराव चह्नाण: जैसा कि मैंने कहा, चीनी सेनाग्रों का जमाव मुख्यतः केवल बाराहोती में ही नहीं है ग्रापितु यह जमाव समस्त सीमा के साथ-साथ है। निश्चय ही हम स्थिति के बारे में पहले से जागरूक हैं।

Shri Bagri (Hissar): It is absolutely necessary for the people of any country to have a high morale in order to depend and protect their country, and that is possible only when the Government comes forward with a clear cut policy as we have strained relations with China, and the Chinese Embassy . . .

Mr. Speaker: He may put a question.

Shri Bagri: I want to give some background.

Mr. Speaker: It should not be lengthy enough.

Shri Bagri: I would like to know whether this Government is prepared to formulate and follow a clear cut policy about China instead of wavering policy?

Mr. Speaker It becomes difficult to understand your lengthy question hence your question may not be replied.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur): I would like to know whether Government envisages attacks on any Indian border or it presuposes full preparedness on their part to meet any situation?

Shri Y. B. Chavan: The Defence Minister has accepted the responsibility of defending the borders of the entire country.

Shri Brij Raj Singh (Bareilly): It is a welcome feature that a very big aerodrome has been built at Bareilly. But the link roads to Barahoti are not in a good condition as to render a satsfactory service. The culverts are very weak. May I know whether the Defence Minister proposes to further construct the remaining link roads?

श्री यशवन्तराव चह्नाण : सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण उत्तरदायित्व सीमा सड़क संगठन ने ग्रपने ऊपर लिया हुग्रा है । सामरिक दृष्टि से ग्रावश्यक सभी सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है । सदस्य महोदय ने ग्रपने पत्र में भो किसी विशेष सड़क का उल्लेख किया है ग्रीर मैंने उन्हें ग्राश्वासन दिया है कि मैं मामले की जांच करवाऊंगा ।

Shri Vishwanath Pandey (Salempur): The hon. Minister has stated that there has been a heavy concentration of the Chinese troop near Barahoti and that there is panic in that area. May I know whether the security of the place is a subject of U.P. Government or it is to be taken over by the Centre?

श्री यशवन्तराव चह्नाण: मैंने यह बताया है कि उस क्षेत्र में कोई भी स्रांतक फैला हुस्रा नहीं है। सारा प्रश्न इसी स्रांतक के स्राधार पर पूछा गया है। किन्तु निश्चय ही उस क्षेत्र में उचित सैनिक कार्यवाही की जायेगी।

श्री दो॰ चं॰ शर्मा (गुरदासपुर): श्राज हमारे देश को पाकिस्तान श्रीर चीन दोनों से खतरा है। स्पष्टतः इन दो देशों के बीच सांठणांठ चल रही है। यदि ये दोनों देश किसी प्रकार हम पर एक साथ हमला कर दें, तो नया उस स्थिति में हमारा देश उनका मुकाबला कर सकेगा ?

श्री यशवन्तराव चह्नाण : जी, हां ।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद): क्या यह सच है कि बाराहोती तथा ग्रन्य सीमों क्षेत्र में कुछ चीनी समर्थक साम्यवादियों ग्रीर कांग्रेस पार्टी तथा सरकार के कुछ सदस्य के देश द्रोही गतिविधियों के परिणाम-स्वरूप स्थिति ग्रीर भी ग्रिधिक बिगड़ हुग है, जैसा कि राजस्थान के मंत्री के हाल ही के भाषण से स्पष्ट हुग्रा है, यदि हां, तो कांग्रेस पार्टी ग्रीर सरकार के ऐसे सदस्यों की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री यशवन्तराव चह्नाण: मैं इस ग्रारोप को कतई नहीं मानता कि कांग्रेस दल ग्रथवा सरकार में कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो चीन के समर्थक हैं। किन्तु निश्चित रूप से हम इस क्षेत्र में होने वाली राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर सावधानी पूर्वक निगरानी रखते हैं। हम इसके बारे में बहुत सावधान हैं। इस विशेष क्षेत्र में ऐसी कोई भी राष्ट्र-विरोधी गतिविधि देखने में नहीं ग्राई । (ग्रन्तर्बाधायें)।

Mr. Speaker: How can the proceedings go on it. Members talk freely in this manner? After all we have to maintain the decorum in the House and the dignity of the House is going down. All Members are responsible for this. Exercise of the control is absolutely necessary. But I cannot exercise it without the co-operation of the hon. Members. I am prepared to give opportunity to all the Members. Every Member should exercise restraint on himself we are being rediculed outside.

Shri Hari Vishnu Kamath: Opposition Parties are not responsible for all this.

Mr. Speaker: All are responsible.

श्री पें० वेंक्टासुब्बया : (ग्रडोनी) : क्या सरकार ने राजनियक सूत्रों द्वारा कोलम्बो राष्ट्रों को यह जानकारी देकर उन्हें प्रभावित किया है कि बाराहोती क्षेत्र में चीनी सेनाग्रों का जमाव उचित नहीं है?

श्री यशवन्तराव चह्नाण : इस विशेष मामले के सम्बन्ध में कोलम्बो राष्टों के साथ बातचीत करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी: (कानपुर): मंत्री महोदय ने बताया कि सभी सीमा-क्षेत्रों पर चीनी सैनिकों का जमाव है। क्या यह सच है कि हाल ही में चुम्बी घाटी के ग्रास-पास चीनी सेनाग्रों का बहुत बड़ी संख्या में जमाव हो गया है ग्रीर जहां चीनी सम्भवतः ग्राक्रमण करने वाले हैं यदि हां, तो सरकार चुम्बी घाटी से होने वाले ग्राक्रमण को विफल करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री यशवन्तराव चह्नाण: चुम्बी घाटी क्षेत्र एक संवेदनशील क्षेत्र समझा जाता है। मैंने स्वयं इसकी चर्चा प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों पर चल रहे वादिववाद के दौरान इसकी चर्चा की थी, मैं सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र में हमारे सीमान्त क्षेत्रों की रक्षा के लिए सभी ग्रावश्यक कदम उठाये गये हैं:

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): Both, the small and the great Barahoti areas are ours, but the whole of Barahoti area which has been taken as a disputed area is now in Chinese occupation. May I know whether Government are making any preparations with a view to throw them out or face them; and what is the area of all the borders where there is concentration of Chinese forces?

श्री यशवन्तराव चह्नाण: मैंने पहले भी कहा है कि सेना का जमाव बाराहोती से उनकी श्रोर है।

Shri Yudhvir Singh: Ever since Pakistan and China have entered into agreement the concentration on our northern border has increased. Pakistan has increased its aggressive activities. Has the number of provocative activities also increased on northern border?

श्री यशवन्तराव चह्नाण: हम सभी गतिविधियों पर ध्यान दे रहे हैं। मैं इस विषय में ग्रौर जानकारी नहीं दे सकता।

श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा: यह कहा गया है कि चीनियों ने हवाई पट्टियां बना ली हैं ग्रीर बहां से हेलीकोप्टर को उड़ा कर वे हमारी सेना की गतिविधि को देखते हैं। क्या हमने अपनी सेनाम्रों को हिदायत करदी है कि वे इन को नीचे गिरादें?

श्री यशक्तराव चव्हाण: मेरे विचार में ये स्थायी ग्रादेश पहले ही दिये हुए हैं।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker Sir, I rise on a point of order. About 15 or 20 days ago I had given a calling notice on this subject, **but** it was rejected. I am glad that you have admitted it today though my name is not there on the notice. Now I want to know whether I can put question on this subject.

Mr. Speaker: No Sir, Not only you but a few more hon. Members asked this. Mr. Kapur Singh has written to me in this regard to-day. I had received a notice from Shri Madhu Limaye, on this subject. Shri Kapur Singh, Shri Prakash Vir Shastri and a few more—the subject was:—

बाराहोती के निकट चीनियों द्वारा नई चौकी बनाने का समाचार

Shri Madhu Limaye: Sense of fear is prevalent in the border area on account of concentration of Chinese forces. That is why it is linked with that.

Mr. Speaker: When I received this notice, I enquired from Government about it and was informed that no such post has been established and accordingly I rejected the notice on that day. Now a new question has been raised. I cannot link both. The subject of your notice was entirely different from this notice.

Dr. Ram Manohar Lohia: Those who are alert should be listened to by you first.

श्री कपूर सिहं (लुधियाना): श्रीमन, यह प्रश्न लगभग 30 मार्च को उत्तर प्रदेश विधान सभा में उठाया गया था। वहां पर राज्य सरकार के वक्तव्य के अनुसार चीनियों ने सीमा के पास चौंकी स्थापित कर ली है और इस से लोगों में भय की भावना फैल गई है, परन्तु विधान सभा में इस प्रश्न को उठाया नहीं जा सकता। इसे तो संसद में ही उठाया जा सकता है, क्योंकि इसका केन्द्र से सम्बन्ध रहेता है। ग्राप को सरकार ने सूचना दी है कि कोई चौकी नहीं बनाई गई है। यह सब कैसे हो रहा है?

ग्रध्यक्ष महोदयः मैं इस बारे में छानबीन करूंगा। मैं सदन को बता रहा था कि मैंने प्रस्ताव क्यों ग्रस्वीकृत कर दिया है। इन दोनों प्रस्तावों में कही गई बातें भिन्न हैं।

इसी लिये मैंने इसे अस्वीकार कर दिया था। क्या वे तथ्य ठीक थे अथवा नहीं अलग बातः है।

Shri Madhu Limaye: Please listen me.

Mr. Speaker: No, it is different from his notice.

Shri Madhu Limaye: I feel that our calling attention notices are not allowed. I gave a notice regarding the direct message sent by China to the King of Sikkim. My notice was disallowed. A statement has been issued today by External Affairs Ministry on that subject. Had you allowed my notice this situation would not have arisen. Likewise so many things in regard to foreign policy and defence policy are taking place, but our suggestions are not allowed.

Mr. Speaker: Calling attention notices are now treated more lightly than question. Questions are admitted keeping in view some conditions, but now I receive about 10 calling attention notices from one member.

Shri Madhu Limaye: What can we do, the number of happenings has increased.

Mr. Speaker: What can I do? Hon. Members should realise at the time of giving notices and should lay stress on one notice, otherwise a group should send one notice.

Shri Madhu Limaye: It depends on happenings.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: जब स्थिति इस प्रकार की हो तो उस समय पार्टी के लिये प्रस्तावों की संख्या सीमित करना कठिन होगा।

ग्रथ्यक्ष महोदय: यदि यह कठिन है तब मुझे तो 40, 50 ग्रौर 60 तक की संख्या में प्रस्ताव मिलते हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia: You can fix limit on notices say two or three that are given by a group. I want to draw your attention to the fact that some people are very alert. They give notice in advance on the basis of information that they have with them. At that time Government is not ready with details. We have been bringing to your notice this during the last 20—22 days but Government was not agreeable. Barahoti has been taken over by China due to carelessness of our Government. It is on the way to Badrinath. Later on this type of thing becomes controversial. This question has been there during the last 11 years. We tried to raise this question about 20 days before. We are being punished for that. That is not good. We should be given priority.

Mr. Speaker: I have read it and said that that is a separatematter.

Shri Madhu Limaye: Just now the Defence Minister has said that on account of Barahoti panic . . .

Mr. Speaker: He said there is no panic.

Shri Onkar Lal Berwa: I have also given a calling attention notice....(Interruption).

Mr. Speaker: I cannot take up each calling attention notice.

Shri Gulshan: Mr. Speaker, I have given a calling attention notice bearing ten or twelve signatures. It is regarding the breach of promises given to Sikhs. These promises in regard to regional formula, the problem of Punjabi language. Apart from this, at Ludhiana . . .

Mr. Speaker: How can I take this as a calling attention notice?

Shri Gulshan: The Sikh religion is in danger.

Mr. Speaker: I have informed you. You please sit down now.

Shri Gulshan: At Ludhiana the recitation of Guru Granth Sahab has been disturbed and at Doraha Mandi it has been burnt . . .

Mr. Speaker: It is not proper for you to go on speaking in spite of my requests not to go further.

Shri Gulshan: I will sit down but I should be given opportunity to say something.

Mr. Speaker: I will not allow you to say anything.

Shri Gulshan: If I am not allowed I will go out of the House but I would like you and the House to know that injustice is being done to the Sikhs.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री रंगा : उन्हें अपनी बात कहने दीजिये।

स्रध्यक्ष महोदय: यदि मैं अस्वीकृत ध्यान दिलाने वाली सूचनास्रों पर भी बोलने की स्रनुमित दूं तो कार्य कैसे चल सकता है? स्रौर उन पर बहुत समय लग जायेगा।

श्री रंगा: मुश्किल यह है कि जब कोई सदस्य बात कहना चाहते हैं तो श्राप उस को गलत समझ जाते हैं श्रीर मान लेते हैं कि वह सदस्य गड़बड़ कर रहे हैं इस से कठिनाई खड़ी हो जाती है।

ग्रध्यक्ष महोदय : इस प्रकार प्रश्न उठा कर बात नहीं की जा सकती।

Shri Gulshan: Disrespect has been shown to Guru Granth Sahab at Ludhiana. Sikhs' hair has been removed. In this way the religion is in danger. If you do not allow me to say something, I go out of the House.

[इस के पश्चात श्री गुलशन सदन से बाहर चले गये]

[Shri Gulshan left the House at this stage]

Shri Buta Singh: If you do not allow me to say something, I go out of the House.

इस के पश्चात श्री बूटासिंह सदन से बाहर चले गय हे Shri Buta Singh left the House at this stage

श्रो रामेश्वरानन्द: * * * *

श्री जयपाल सिंह (रांची-पश्चिम): मैंने श्राप को गलत नहीं समझा है। श्रापने कहा है कि ग्राप ध्यान दिलाने वाली सूचनाग्रों की संख्या सीमित

Shri Onkar Lal Berwa: As he is speaking in English, he is being allowed to speak. Whereas those who speak in Hindi are asked to sit down.

Mr. Speaker: Does he want to say something in regard to calling attention notice?

Shri Jaipal Singh: Yes Sir, I have to say something about that.

Dr. Ram Manohar Lohia: He is speaking in Hindi. Let him say.

श्री जयपाल सिंह: ग्रापने कहां है कि प्रत्येक पार्टी एक प्रस्ताव देगी। मेरा श्रनुरोध है कि मैं इस से सहमत नहीं हूं। मेरा निवेदन है कि इस से सभी सदस्यों के ग्रिधकारों का हनन होगा।

ग्रध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा नहीं किया है।

Shri Rameshwaranand: I want to make a submission.

Mr. Speaker: When I take some action, it is resented. I find that some hon. Members i nspite of my repeatedly asking them to sit down stand up again and again. I have asked Swamiji many times to sit down, if he stands up again, I will have to take action. He should now sit down.

Shri Rameshwaranand: I walk out of the House in protest against your behaviour.

इसके पश्चात् श्री रामेश्वरानन्द सदन से बाहर चले गये े Shri Rameshwaranand then left the House

सभा पटल पर रखे गये पत्र PAPER LAID ON THE TABLE

ग्रसैनिक उड्ययन मंत्रो (श्री कानूनगो) : मैं श्री राज बहादुर की ग्रोर से निम्नलिखित पत्नों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:---

(1) मोटर गाड़ी ग्रधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के ग्रन्तर्गत ग्रधिसूचना संख्या एफ, 12(95)/72-पी ग्रार (टी) की एक

^{**}कार्यवाही के वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

^{**}Not recorded.

प्रति जो दिनांक 28 जनवरी 1965 को दिल्ली राजपत्न में प्रकाशित हूई थी तथा जिसके द्वारा दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, 1940 में कुछ संशोधन किये गये थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०--- 4280/65 1]

- (2) विणक् नौपरिवहन ग्रिधिनियम, 1958 की धारा 16 की उप-धारा (6) के ग्रन्तर्गत नौपरिवहन विकास निधि समिति की वर्ष 1962-63 की रिपोर्ट तथा प्रमाणित लेखे तथा उनकी परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--4281/65]
- (3) कम्पनी ग्रिधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के ग्रन्तर्गत हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1963-64 की वार्षिक रिपोर्ट परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--4282/65 ।]

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० सा० राजू)ः श्री जगन्नाथराव की ग्रोर से मैं निम्नलिखित पत्न की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूं:

- (1) कर्मचारी भविष्य निधि ग्रिधिनियम, 1962 की धारा 7 की उप-धारा (2) के ग्रतन्तर्गत निम्नलिखित ग्रिधिसूचनाग्रों की एक-एक प्रति:--
 - (एक) कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा सशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 6 मार्च, 1965 की ग्रधिसूचना संख्या जी० एस० ग्रार० 351 में प्रकाशित हुई थी।
 - (दो) कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 13 मार्च, 1965 की ग्रिधिसूचना संख्या जी०एस०ग्रार० 401 में प्रकाशित हुई थी।
 - (तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 27 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 475 में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-4283/65]
- (2) कर्मचारी भविष्य निधि ग्रिधिनियम, 1952 की धारा 4 की उप-धारा (2) के ग्रन्तगंत ग्रिधिसूचना संख्या जी० एस० ग्रार० 402 दिनांक 13 मार्च, 1965 की एक प्रति, जिसके द्वारा पाव रोटी उद्योग को उक्त ग्रिधिनियम की ग्रनुसूची 1 में सम्मिलित किया गया था। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4284/65]

कच्छ सीमा पर पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में RE: DISCUSSION ON SITUATION ARISING OUT OF ATTACKS BY PAKISTAN ON KUTCH BORDER

ग्रथ्यक्ष महोदय: मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे प्रधान मंत्री से निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना मिली है ग्रौर इसे स्वीकार कर लिया गया है। इस पर कल ग्रर्थात् 28 ग्रप्रैल, 1965 को चर्चा होगी:---

"िक कच्छ सीमा पर पाकिस्तान के सशस्त्र सेनाग्रों द्वारा बार बार ग्रौर लगातार किये जा रहे ग्राक्रमणों से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाये।" मैंने इसे पढ़ लिया है ताकि जो माननीय सदस्य संशोधन भेजना चाहें, भेज सकें।

प्राक्कलन समिति ESTIMATES COMMITTEE तिहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री ग्र० चं० गुह (बारसाट) : मैं प्राक्कलन समिति का खाद्य मंत्रालय (कृषि विभाग)—केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र ग्रनुसंधान संस्था, जोधपुर—के बारे में तिहत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी ग्राश्वासनों सम्बन्धी सिमिति COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES कार्यवाही सारांश

श्रो सिद्धनजण्या (हसन): श्रीमन, मैं सरकारी ग्राश्वासनों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई ग्यारहवीं बैठक की कार्यवाही का सारांश सभापटल पर रखता हूं।

ग्रनुदानों की मांगें--- जारी DEMANDS FOR GRANTS-Contd,

गृह-कार्य मंत्रालय-जारी

Shri Maurya (Aligarh): The problem of corruption has been subject of discussion here. It is good that this problem is focussing attention and I thank the hon. Home Mnister for having realised the

importance of eradication of corruption. He is doing a lot to root out corruption from our public life. It is not an easy job. There will be many impediments in the way. Shri Nanda will have to be bold and encounter the difficulties bravely. Corruption is entrenched in such way that it will require strenous efforts to be removed. Moreover, he will have to be very cautious. Only then he will succeed in his endeavour. All of this will have to do our bit to get rid of the malady of corruption.

At the time of communal riots, Shri Nanda had done splendid work. I am all praise for him for that. I would like that opposition parties should appreciate the work of hon. Home Minister.

Disruptionist tendencies are coming up in the country. We should take such action as would make the Central Government more powerful. Ours is a big country. There are numerous problems facing our country. If Central Government were strong, it would tackle these problems effectively or there will be disintegraton.

The Minister of Home Affairs admits that not more than three or four percent officers of the I.A.S. Cadre belong to Scheduled Castes. I urge that special recruitment should be made in the Central Government services from amongst the people belonging to Scheduled Castes. It is also my suggestion that there should be nine members of the Union Public Service Commission instead of seven as at present. One member each from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be appointed as early as possible.

I do not say that there is no need of Defence of India Rules, but innocent persons should not be entangled under these rules. These rules should be used with great care and caution. It appears that those rules are being used against certain political workers to protect the interests of Congress.

An officer of I.A.S. cadre belonging to Scheduled Castes has resigned. How is it that untouchability was practised against him in spite of the fact that he belonged to I.A.S.? I request Shri Nanda to take steps against the practice of untouchability with the same firmness with which he took steps against corruption.

श्री ग्रन्तार हरवानी (बिसौली) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री को देश की दो सब से बड़ी बुराइयों ग्रर्थात् भ्रष्टाचार तथा साम्प्रदायिकता के विरुद्ध ग्रान्दोंलन जारी रखने पर बधाई देता हूं। उनके शासन के दौरान पंजाब के स्वर्गीय मुख्य मंत्री श्री करों के विरुद्ध दास ग्रायोग की नियुक्ति की गई ग्रौर उन्हें ग्रपने पद से हटना पड़ा। उड़ीसा के मामले में भी उनके ही काल में जांच करवाई गई।

जब सर्वोच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का प्रगन उत्पन्न हो तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच नहीं कराई जानी चाहिये। इस उद्देश्य के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त स्वतंत्र निकाय स्थापित किया जाना चाहिये।

17 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं बन सका है। पश्चिमी आकिस्तान ग्रीर पूर्वी पाकिस्तान में क्या बात समान है? भाषा भिन्न है, संस्कृति भिन्न

है, भूगोल भिन्न है, सभी कुछ भिन्न भिन्न है। जबिक पाकिस्तान में ग्रल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है भारत में उनसे उचित व्यवहार हो रहा है। लोगों को यह कहने का ग्रवसर नहीं दिया जाना चाहिये कि भारत धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र के सिद्धान्त से हट रहा है जिसे इस देश के महान पुत्र, श्री जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था। इस देश में ग्रल्प-संख्यकों के विरुद्ध भेदभाव बिल्कुल नहीं है ग्रीर इस का श्रेय सरकार को मिलता है।

मद्रास में जो घटनायें हुई हैं उससे हम सब का सिर लज्जा से झुक जाता है। हमें यह जानना चाहिये कि जब से संविधान सभा के हिन्दी को हमारी राष्ट्रीय भाषा माना तब से वह हमारी सरकारी भाषा हो गई है। हिन्दी समर्थकों को ग्रधिक संयम से काम लेना चाहिये। जनता पर कोई भाषा एकदम नहीं लादी जा सकती है। 17 वर्षों में हिन्दी को समृद्ध बनाने की बजाये उन्होंने इसे ग्रौर दुर्बल बनाया है। इस प्रकार हिन्दी का विकास नहीं हो सकता है।

माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान उर्दू भाषा की स्थिति की जांच करने के लिए दिये गये ग्रभ्यावेदन की ग्रोर दिलाता हूं। इसके साथ पिछले 17 वर्षों से सोतेली मां जैसा व्यवहार किया गया है। उर्दू केवल म्सलमानों की भाषा नहीं है। वह किसी एक सम्प्रदाय की भाषा नहीं है। वह हिन्दुग्रों ग्रौर मुसलमानों की समान भाषा है। उर्दू भाषी क्षेत्रों में हिन्दी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिये परन्तु उद्दूं को सह भाषा बनाया जाना चाहिये।

श्री हिम्मतिंसहजी (कच्छ): श्रीमन्, मैं ग्रपने जवानों को देश की रक्षा के लिए जीवन बिलदान करने पर बधाई देता हूं तथा ग्राज समूचे देश ग्रौर विशेष रूप से कच्छ के लोगों का ध्यान सीमा पर स्थिति की ग्रोर दिलाता हूं। मुझे यह कहने में गर्व हैं कि वहां के लोग घबराये नहीं हैं ग्रौर वे स्थिति का सामना करने के लिए सरकार की हर सम्भव सहायता करने के लिए तैयार हैं।

ग्राठ महीने पहले गुजरात सरकार का ध्यान कच्छ-सिन्ध सीमा की ग्रोर दिलाया गया था ग्रौर काश्मीर के सम्बन्ध में चीन ग्रौर पाकिस्तान की कार्यवाहियों पर ध्यान रखने के लिए कहा था। मैंने गुजरात के गृह-मंत्री को एक पत्र लिखा था कि वह सीमा सम्बन्धी सावधान रहें। दुर्भाग्य की बात है कि हम लापरवाही में पकड़े गये हैं।

हमारी सरकार की सदा यह नीति रही है कि घटनाओं पर पर्दा डाला जाये जब गुजरात विधान सभा में इस घटना पर मामला उठा तो गृह-मंत्री ने पहले कह दिया कि यह ठीक नहीं हैं। फिर हमारी पुलिस चौकियों पर ग्राक्रमण हुन्ना ग्रौर गृह-कार्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रौर पाकिस्तान के बीच बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक गोलीबारी बन्द नहीं होगी। बाद में प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए कोई शर्त नहीं रखी जायेगी। ऐसी बातों से केवल गत्र कि शक्ति बढ़ती हैं। सरकार की एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये।

नी वर्षों बाद इस सीमा पर फिर घटनायें हुई हैं। गुजरात ऋार्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुम्रा राज्य होने के कारण प्रतिरक्षा की पूरी ऋावश्यकताम्रों को पूरा नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए भुज से खोड़ा तक सीमान्त सड़कें बनाई जानी चाहियें। वे ग्रभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इस क्षेत्र में नदी पर एक पुल बनाने का भी प्रश्न है। इन सब बातों की जिम्मेदारी केन्द्र को लेनी चाहिये। गृह-कार्य मंत्रालय को सीमा पर ध्यान रखना चाहिये। कच्छ, ग्रसम तथा पिश्वमी बंगाल की सीमाग्रों का सर्वेक्षण कराना उसका काम है। यह भी देखना चाहिये कि वहां के लोगों को कोई किठनाई न हो।

गृह-कार्य मंत्री ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए ग्रच्छा काम ग्रारम्भ किया था परन्तु बाद की घटनाग्रों ने उनकी सारी योजनाग्रों को विफल बना दिया है या वह इतने दुर्बल हैं कि यह सब काम नहीं कर सकते।

हाल ही में राजस्थान के विधायकों तथा संसद् सदस्यों ने वहां के मुख्य मंत्री की भ्रष्ट कार्यवाहियों के विरुद्ध प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था। गृह-कार्य मंत्री को इस ग्रवसर पर पूरा उतरना चाहिये ग्रौर उचित जांच करानी चाहिये।

सीमा क्षेत्रों में, चाहे कच्छ हो या कहीं ग्रौर, राजनीतिक दलों को राजनीतिक हितों के लिए साम्प्रदायिक भावनायें भड़काने नहीं दिया जाना चाहिये, चाहे वह दल कांग्रेस हो, स्वतंत्र दल हो या कोई ग्रौर दल । मुझे ग्राशा है कि गृह-कार्य मंत्री केन्द्रीय जांच ब्यूरो ग्रथवा किसी ग्रन्य एजेंसी द्वारा इस बात की जांच करायेंगे कि क्या कोई दल वहां पर साम्प्रदायिक भावनायें भड़का रहा है।

कुछ दलों की राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री ने कुछ वामपक्षी साम्यवादियों को गिरफ्तार किया है। यदि वामपक्षी साम्यवादी दल तोड़फोड़ की कार्यवाही ग्रथवा किसी ऐसी कार्यवाही के लिए जिम्मेवार हैं जो देश की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल है तो उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए। उन्होंने वामपक्षी साम्यवादियों को चुनाव लड़ने क्यों दिया? इससे गलत प्रभाव पैदा हुग्रा है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): मैं उस स्रालोचना तथा प्रशंसा के लिए स्राभारी हूं जो गृह-कार्य मंत्रालय को इस चर्चा के दौरान मिली है। गृह-कार्य मंत्रालय के कार्य को परियोजनास्रों स्त्रीर उत्पादन स्रादि की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। परन्तु यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा राजनैतिक तथा सामाजिक ढांचे के महत्वपूर्ण भाग की व्यवस्था होती है जिसके बिना देश के स्राधिक तथा सामाजिक जीवन में ठीक उन्नित सम्भव नहीं। प्रशासनिक ढांचा, विधि तथा व्यवस्था के साधन तथा सुरक्षा के साधन इस ढांचे के महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। संविधान द्वारा सरकार तथा जनता पर कुछ जिम्मेवारियां हैं स्त्रौर जिस प्रणाली के लिए गृह-कार्य मंत्रालय की मुख्य जिम्मेवारी है, वह प्रणाली इस प्रकार बनाई जानी है कि वह ऐसे कार्य करे कि इससे हमारे लिए संविधान द्वारा निर्धारित जिम्मेवारियों को पूरा करने में सहायता मिले।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हम उग्र तथा लगातार परिवर्तनों के समय में रह रहे हैं जो जीवन के सभी क्षेत्रों में हो रहे हैं। लोकतत्र की शक्तियों तथा विकास की कार्यवाहियों के प्रभाव से परिवर्तन की गित में बहुत वृद्धि हुई है। नई सामाजिक शक्तियों का निर्माण हो रहा है जिनका प्रभाव राजनैतिक क्षेत्रों पर पड़ रहा है।

श्रिः नन्दा]

में विरोधी सदस्यों का ग्राभारी हूं कि उन्होंने पाकिस्तानी ग्राक्रमण द्वारा उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति पर ठीक रवैय्या ग्रपनाया है। जिन सदस्यों ने भाषण दिये हैं, उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। हमें ग्रपनी सेनाग्रों को यह विश्वास देना है कि वे सदा हमारे विचारों में हैं ग्रौर हम जहां भी हैं, ग्रपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सरकार को हर स्तर पर यह दिखाना है कि हम ग्रापातकाल की भावना में काम कर रहे हैं। राज्य के समूचे संगठन में कार्य कुशलता ग्रौर ईमानदारी से सेवा की भावना बनी रहनी चाहिये। इस समय इस बात की बहुत ग्रावश्यकता है। परस्पर झगड़े ग्रौर फूट, चाहे कांग्रेस में हो या समाज के किसी भी भाग में, समाप्त होनी चाहिये। हमें ग्रपनी भावनाग्रों पर नियंत्रण रखना चाहिये ग्रौर परीक्षा के इस समय में स्थिर रहना चाहिए।

सभी को कठिन परिश्रम करके ग्रपना कर्तव्य निभाना होगा। कहीं भी उत्पादन, संचार या परिवहन में रुकावट नहीं ग्रानी चाहिये। हमें इस बात पर सहमत होना चाहिये कि किसी प्रकार के 'बन्ध' न हों। काम नहीं रुकना चाहिये। देश के ग्रन्दर राष्ट्र के शत्रुग्रों से कड़ा व्यवहार किया जायेगा। ऐसे लोगों के लिए कोई दया नहीं दिखाई जायेगी जो साम्प्रदायिक दंगों को भड़काते हों या ग्रराजकता की हालत पैदा करते हों।

हमें ऐसी समस्याग्रों के हल के नये मार्ग ढूंढने होंगे जिससे ऐसी समस्यायें हल हो सकें जो लोगों के मनों में भरी हुई हैं। सभी समस्याग्रों को, चाहे वह भाषा सम्बन्धी हों या धर्म सम्बन्धी, किसी सम्प्रदाय के सम्बन्ध में हों या किसी ग्रौर के बारे में, उन्हें ग्रांदोलनों द्वारा हल नहीं किया जाना चाहिये बल्कि उन्हें नये तरीकों ग्रौर ढंगों से हल किया जाना चाहिये। ऐसी स्थित में हमारे राष्ट्र का सम्मान तथा शक्ति बढ़ेगी।

मुसलमानों का इस देश में वैसा ही स्थान है जैसा कि अन्य लोगों का । परन्तु यदि उन में भी ऐसे लोग होंगे जिन पर सन्देह होगा तो मैं उन्हें बता दूं कि वे इस देश में स्वतंत्रता से ऐसी कार्यवाही नहीं कर सकेंगे । मैंने कलकत्ता के साम्प्रदायिक दंगों के समय जो बात कही थी, उसे दोहराता हूं । मैंने कहा था कि एक भी मुस्लिम के जीवन की रक्षा के लिए देश की पूरी शक्ति लगा दी जायेगी ।

सीमा की स्थिति का महत्व ग्रौर सभी बातों से ग्रधिक है। हमें कुर्बानियों के लिए तैयार रहना चाहिये। हमें देश के सभी तत्वों के एकीकरण के ग्राधार पर चलना है। उन लोगों को, जो देश की कठिनाइयों से ग्रपने लिए ग्रवसर ढूंढना चाहते हैं, यह जान लेना चाहिये कि उनके साथ दृढ़तापूर्वक व्यवहार किया जायेगा।

गिरफ्तारियों का मामला उठाया गया है। जो लोग देश की मूल स्वतंत्रता बर्बाद करने पर तुले हों, उनको कोई रियायत नहीं दी जा सकती। यदि कोई गिरफ्तार व्यक्ति यह सिद्ध कर सके कि वह चीन समर्थक नहीं है ग्रौर तोड़-फोड़ की किसी कार्यवाही से उसका बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है तो उसके मामले पर ग्रवश्य ही विचार किया जावेगा।

श्रापातकाल के दौरान इन शक्तियों के प्रयोग की बजाय समाज के सहयोजन के प्रयत्नों पर श्रिषक विश्वास करना होगा। मुझे श्राशा है कि जब तक स्थिति सामान्य न हो जावे श्रापात-काल को समाप्त करने की कोई बात नहीं की जानी चाहिये। विधि तथा व्यवस्था की स्थिति को ठीक प्रकार से बनाये रखने के लिए भारत सरकार ने पुलिस के दृष्टिकोण में नवीनता लाने ग्रीर जांच के नये तरीके ग्रपनाने के लिए उपाय किय हैं। ग्राधुनिक तरीकों के प्रशिक्षेण की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र तथा राज्यों में सशस्त्र पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए भी उपाय किये हैं। कई राज्यों ने पुलिस ग्रायोगों या समितियों की नियुक्ति की है। गृह-कार्य मंत्रालय ने भी विभिन्न पुलिस ग्रायोगों के प्रतिवेदनों का ग्रध्ययन किया है यद्यपि कुछ ग्रीर काम की ग्रावश्यकता है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो को न केवल ग्रपराधों की जांच के लिए ही बल्कि विशेष रूप से भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी ग्रौर केन्द्रीय ग्रधिनियमों का उल्लंघन करने के ग्रपराधों की जांच के लिए ग्रौर कुछ प्रकार के ग्रपराधों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी करने के लिए भी सुदृढ़ बनाया गया है।

पुलिस की महत्वपूर्ण समस्याग्रों में से एक यह है कि राज्यों में उनके लिए पर्याप्त संख्या में मकानों की कमी है। पुलिस कर्मचारियों की मकानों के बारे में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जा रही है।

विधि तथा व्यवस्था की समस्या के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक साधारण अपाराधों के बारे में है और दूसरा बड़ें पैमाने पर आंदोलनों के सम्बन्ध में है। हाल ही के वर्षों में हमारे देश में अपराधों को ठीक प्रकार से दर्ज कराने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस से यह जरूरी है कि कुछ और समय तक अपराधों की संख्या अधिक दिखाई दे।

इस क्षेत्र में हमारी किठनाइयों का एक बड़ा कारण गुंडों, अपराधियों और समाज विरोधी तत्वों का विद्यमान होना है। जब भी अवसर मिलता है तो यह लोग अपना काम आरम्भ कर देते हैं। उनके पास संसाधन हैं और काले कामों के लिए उनके पास प्रशिक्षित व्यक्ति हैं। इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये हमें दृढ़ नीति अपनानी होगी क्योंकि ये हमारे नागरिकों की सुरक्षा को संकट में डालते हैं।

जहां तक साम्प्रदायिक दंगों का सम्बन्ध है, हमारे संविधान में यह उपबन्ध किया गया है कि ग्रल्प-संख्यकों का पूरा-पूरा संरक्षण किया जाये। सभा को ज्ञात ही है कि पिछले वर्ष पूर्वी पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंगे होने के कारण हमें यहां भी कठिन समय देखना पड़ा। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि चालू वर्ष में कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं रहा है।

हम ने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये निर्णयों के ग्रनुसरण में भारतीय दण्ड संहिता की कुछ धाराग्रों में संशोधन किये ताकि विभिन्न जातियों तथा सम्प्रदायों में घृणा तथा श्रातुता की भावना बढ़ाने को एक ग्रपराध माना जाय श्रीर किसी धर्म ग्रथवा जाति पर ग्राघात करने वाले को कड़ा दण्ड दिया जाये। हम इस कानून को ग्रीर कड़ा बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। [श्रीं नन्दा]

हाल ही के वर्षों में विद्यार्थियों ने बहुत अनुशासनहीनता दिखाई है। इसका कारण कुछ तो उनकी वास्तविक कठिनाइयों की और कुछ राजनैतिक दलों द्वारा उन्हें भड़काया जाना था। विद्यार्थियों की सच्ची शिकायतें हो सकती हैं और उन्हें दूर करने के लिये कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी और राजनैतिक उद्देश्यों के लिये विद्यार्थियों को उत्तेजित किया जाना बन्द करना पड़ेगा।

जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सम्बन्ध है, मैं इस बारे में जागरूक हूं कि हमारी इस में बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिये मैं यह विस्तारपूर्वक नहीं बताना चाहता कि वया उपाय किये जा रहे हैं। सभी राज्यों में जासूसी के मामलों में ध्यान देने के लिये मुसंगठित एकक हैं, जिनमें प्रशिक्षित व्यक्ति हैं और उनके द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये प्रयास काफी सफल रहे हैं। कई वर्षों से स्थानीय पाकिस्तानी पदाधिकारियों का जासूसी में हाथ रहा है और कई मामलों में उनको वापस भेजा गया। हम पूर्ण रूप से जागरूक हैं और भारत में चीन-समर्थक लोगों की अवांछनीय गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। ऐसे लोगों द्वारा तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों को रोकने के लिये राज्यों में सम्बद्ध संगठनों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इन उपायों के परिणामस्वरूप शतु के एजेंटों का भारत में अवैध रूप से घुस आना बन्द हो गया है।

पाकिस्तानियों के ग्रवैध रूप से भारत में घुस ग्राने के प्रश्न पर काफी बातें चर्चा के दौरान कही गई हैं। यह समस्या ग्रसम तथा त्रिपुरा में ग्रधिक है। जो उपाय वहां किये गये हैं उनसे यह समस्या काफी सीमा तक हल हो गई है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसी भारतीय राष्ट्रजन को भारत से न निकाल दिया जाये उन्हें न्यायाधिकरण के पास ग्रपना मामला ले जाने के लिये पूरा ग्रवसर दिया जाता है।

ग्रब मैं काश्मीर की स्थित के बारे में कुछ कहूंगा। भारत के संविधान में ग्रनुच्छेद 370 का समावेश, जम्मू तथा काश्मीर संविधान सभा के प्रतिनिधियों की सम्मित से किया गया था। मैं यह इसलिये कह रहा हूं ताकि गलतफहमी पैदा न हो। भारत के किसी ग्रन्य राज्य की तरह जम्मू तथा काश्मीर राज्य का सभी व्यावहारिक प्रयोजनों से भारत संघ में पूरी तरह विलय हो चुका है। यह बात दोहरानी पड़ती है क्योंकि कुछ बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके द्वारा सन्देह प्रकट किया जाता है।

जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो परिवर्तन हुए, उनसे प्रशासन व्यवस्था के लिये नई जिम्मेदारियां पैदा हुईं। योजनाग्रों के ग्रारम्भ किये जाने से समस्यायें जिटल होती गईं ग्रौर उनके सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्ष-प्रति-वर्ष बढ़ता चला गया। इसलिये प्रशसान व्यवस्था में बड़े पैमाने पर सुधार किये जाने कीं ग्रावश्यकता है ताकि बदलती हुई परिस्थितियों का सामना किया जा सके। प्रशासन व्यवस्था में सुधार की समस्या के सम्बन्ध में दो प्रश्न उठते हैं। वर्तमान प्रशासन व्यवस्था में काफी सुधार किये जाने की ग्रावश्यकता है ताकि इसे दक्ष बनाया जा सके। दूसरा प्रश्न यह है कि इस व्यवस्था में ग्रामूल परिवर्तन किये जायें ताकि यह वर्तमान राजनितिक, सामाजिक तथा ग्राथिक स्थिति का सामना कर सके।

मैं पहले प्रशासन व्यवस्था में सुधार के बारे में कहूंगा। बहुत सी समितियों के प्रतिवेदन हुमें प्राप्त होते हैं जिनमें बड़ी संख्या में सिफारिशों की गई होती हैं। परन्तु यह देखा गया है कि इन सिफा-

रिशों पर ठीक प्रकार ग्रमल नहीं किया जाता। नई दिशा की ग्रोर जो एक बड़ा कदम उठाया गया है वह मार्च, 1964 में प्रशासनिक सुधार विभाग का स्थापित किया जाना है। इस नये विभाग ने व्यवस्थित विश्लेषणात्मक ग्रध्ययन ग्रारम्भ किया है। इस के मुख्य कार्यों में से एक कार्य, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ग्रायोजित करना है जहां से ऐसे व्यक्ति निकलेंगे जो केवल केन्द्र में ही नहीं परन्तु राज्यों में भी ग्रध्ययन-दल स्थापित करेंगे ग्रीर उन से सम्बन्धित कार्य करेंगे। इस समय ऐसे दो पाठ्यक्रम चल रहे हैं जिनमें से एक मध्यम वर्ग के ऐसे ग्रधिकारियों के लिये है जो प्रशासनिक सुधार के कार्यक्रम चलायेंगे ग्रीर दूसरा निचले स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये है जो ग्रनुसंधान-विश्लेषक के रूप में कार्य करेंगे। दोनों पाठ्यक्रमों को मंत्रालयों तथा राज्यों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वीकार किया गया है। ग्रगले वर्ष के लिये ऐसे बहुत से पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम बनाया गया है ग्रीर इसके फलस्वरूप भारी संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी निकलेंगे, ग्रीर यह ग्राशा है कि वे प्रशासन में सुधार करने के कार्य में काफी योग देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए DEPUTY SPEAKER in the Chair

इस सम्बन्ध में दूसरा ग्रारम्भिक कार्य, जिस की ग्रोर ध्यान दिया जाना चाहिये, यह है कि जिन क्षेत्रों में प्रशासन-सम्बन्धी समस्या ग्रधिक है, वहां यह ग्रध्ययन पहले किया जाये । उदाहरण के तौर पर यह समस्यायें ये हैं : कर्मचारी-वर्ग प्रशासन में सुधार, वित्तीय प्रशासन के प्रत्येक पहलू पर पुनर्विचार तथा मंत्रालयों ग्रौर विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में कर्मचारियों की नियुक्ति ग्रादि ।

उदाहरण के तौर पर कर्मचारियों के प्रशासन ढांचे के सम्बन्ध में निर्माण तथा गृह मंत्रालय में सघन अध्ययन चल रहा है और मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के पारस्परिक संबंधों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे प्रयत्न किये जा रहे हैं कि किसी मामले के बारे में मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध कार्यालयों में दोहरा काम न हो। वित्तीय प्रशासन की दिशा में कुछ विभागों में योजनायें मंजूर करने का अध्ययन आरम्भ किया गया है। विस्तृत रूप से अध्ययन करने की योजना बनाई जा रही है।

ग्रन्य ग्रौर समस्यायें हैं जो किसी विशेष मंत्रालय से सम्बन्ध रखती हैं। सभा में यह पहले ही कहा जा चुका है कि संसद्-सदस्यों के चार ग्रध्ययन-दल इस सम्बन्ध में कार्य कर रहे हैं। ग्रगले वर्षों में हमने तीन ग्रौर विभागों के कार्य के बारे में ग्रध्ययन-मण्डल स्थापित करने का निर्णय किया है।

फिर राज्य प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन की समस्या है जिसे केन्द्रीय सरकार महत्वपूर्ण समझती है। जहां तक राज्यों के प्रशासन की समस्या है हमें ग्रावश्यक तौर से समझाने-बुझाने की नीति ग्रपनानी पड़ेगी। क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था है। पिछले वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् की बैठक हुई। इन क्षेत्रीय परिषदों में दूसरी समस्याग्रों के ग्रतिरिक्त प्रशासन की समस्याग्रों पर चर्चा हुई ग्रौर यह हर्ष का विषय है कि कई राज्यों ने पूर्ण उत्साह से प्रशासन में सुधार करने के लिये कार्यवाही ग्रारम्भ की है। जहां तक जिला प्रशासन का सम्बन्ध है, हमने इस दिशा में भी कार्य ग्रारम कर दिया है। इन सब प्रयत्नों का यह ग्रथं है कि हमने कई प्रकार के ग्रध्ययन ग्रारम्भ किये हैं ग्रौर ग्रागामी वर्षों में ग्रौर ग्रध्ययन किये जायेंगे ग्रौर ज्यों ही ये पूरे होंगे ग्रौर इनके बारे में प्रतिवेदन

[श्रो नन्दा]

प्रस्तुत किये जायेंगे, सिफारिशों को यथासम्भव शी घ्र लागू किया जायेगा । प्रशासनिक सुधार के सम्बन्ध में हुई प्रगति पर सचिवालय समिति नज़र रख रही है। हाल ही में सरकार ने प्रशासन के बारे में मन्त्रिमण्डल समिति स्थापित करने का निर्णय किया है ताकि इस सम्बन्ध में ग्रारम्भ किये गये कार्य की गति तेज की जाये।

सन्थानम् सिमिति के प्रतिवेदन में दो बातें थीं। एक बात तो सतर्कता के पहलू के बारे में थी ग्रीर दूसरी ग्रिधकारियों द्वारा स्विवेक के प्रयोग के बारे में। इन से यह ग्रिभिप्राय था कि इन दोनों पर नियंत्रण रखने के लिये एक ग्रायोग होना चाहिये। मेरे विचार में इस देश की परिस्थितियों में केवल एक ही ग्रायोग के लिये यह इतना बड़ा उत्तरदायित्व होगा कि वह इसे भली प्रकार नहीं निभा सकता। इसलिये इन दोनों बातों के लिये दो पृथक-पृथक ग्रिभिकरण होने चाहियें। हाल ही में शिकायतों का निवारण करने के लिये व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है। बहुत से मंत्रालयों में ग्रब ऐसे केन्द्र खोल दिये गये हैं जहां शिकायतों दर्ज की जाती हैं ग्रीर सूचना प्राप्त की जाती है। इन शिकायतों की जांच वरिष्ठ ग्रिधकारियों द्वारा की जाती है ग्रीर उचित स्तर पर उनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है।

हमने इन सभी कार्यवाहियों का समन्वय करने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय में एक पदाधि-कारी नियुक्त करने का निर्णय किया है। लोगों की यह भावना है कि शिकायतों के बारे में देर की जाती है। इस प्रणाली से, जो ग्रब जारी की जा रही है, लोगों को यह ग्राश्वासन दिलाया जायेगा कि इन बातों की ग्रोर ध्यान दिया जा रहा है ग्रौर यदि किसी प्रकार का विलम्ब हो रहा है तो यह सुनिश्चित करने के लिये ग्रावश्यक जांच की जा रही है कि विलम्ब न हो।

जब हम भ्रष्टाचार के उन्मूलन की बात करते हैं, जब हम प्रशासन में सुधार की बात करते हैं, तो यह सब कौन करेगा ? यह सब कार्य कर्मचारीवर्ग द्वारा किया जायेगा । इसलिये जब हम इन कर्मचारियों के ग्रर्थात् प्रशासन की ग्रालोचना करते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिये। यदि हम उनकी निन्दा करते हैं, उन्हें ग्रदक्ष कहते हैं तो हम ग्रपने लिये ग्रथवा देश के लिये ग्रच्छा नहीं कर रहे हैं।

भारतीय प्रशासन सेवा में ग्राने वाले नये व्यक्तियों की इस प्रकार तुलना की गई कि वे कुछ वर्ष पहले के ऐसे अधिकारियों से कम दक्ष हैं। यह गलत है। ये सब योग्य अधिकारी हैं ग्रीर जो नीतियां हम यहां बनाते हैं, उनको ये भली प्रकार लागू करते हैं। सेवाग्रों से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये इन अधिकारियों के सहयोग की बड़ी ग्रावश्यकता है।

भ्रष्टाचार के बारे में बहुत से सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। प्रशासन में नैतिकता लाने के लिये सरकार ने काफी उपाय किये हैं। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही न केवल एक नैतिक मामला है बल्कि हमारे सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति से भी इसका घनिष्ट सम्बन्ध है। यदि प्रशासन तथा अन्य क्षेत्रों में समाज-विरोधी तत्व, विकास के प्रयोजन के लिये समाज द्वारा इकट्ठें किये गये साधनों को हड़प कर जायें, तो कल्याणकारी समाज स्थापित करने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है जिसके फलस्वरूप लोगों में असन्तोष फैलता है और सामाजिक ढांचे में उन का विश्वास कम हो जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था के कारण नियंत्रण तथा दूसरे निर्वधन लगाये गये हैं और इन से दुराचार के अवसर बढ़ गये हैं। हमें शीघ्र ही भ्रष्टाचार के इन अवसरों को कम

करना होगा। इस प्रवृत्ति को हर प्रकार से दबाना होगा। हमें सामाजिक वातावरण पैदा करना है।

श्री हरि विष्णु कामत: श्रापने उड़ीसा के मामले में कुछ नहीं कहा है।

श्री नन्दा: जहां तक उड़ीसा के प्रश्न का सम्बन्ध है केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सराहनीय काम किया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कुछ रिकार्ड इकट्ठे किये जाने का काम दिया गया था। इसके बाद इस मामले में ग्रागे कार्यवाही करने के लिये प्रधान मंत्री द्वारा एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के सामने बहुत सी सूचना तथा बहुत से रिकार्ड थे। इस समिति के सदस्य कानून के मामले की पूरी जानकारी रखते थे। इस समिति ने बड़े परिश्रम के साथ रिकार्ड ग्रादि की जांच की ग्रौर इस समिति द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गये, उन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि यदि किसी स्वतंत्र निकाय ने यह जांच की होती तो निष्कर्ष इस से भिन्न नहीं होते। मेरे विचार से इस प्रकार की गई कार्यवाही से हमें शिक्षा लेनी चाहिये। हम यह देखते हैं कि हम चाहे जो कुछ भी करें, हम किसी को सन्तुष्ट नहीं कर सकते।

प्रधान मंत्री ने यह फैसला किया है कि इस प्रकार की समस्या को हल करने के लिये कोई ग्रीर प्रिक्रिया ग्रपनाई जानी चाहिये। निराधार ग्रारोपों के मामले किसी दूसरी जगह जांच के लिये भेजना बिल्कुल भी ग्रावश्यक नहीं है। प्रधान मंत्री ऐसे मामलों की जांच करेंगे ग्रीर उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर निपटायेंगे। परन्तु यदि किसी जांच की ग्रावश्यकता हो, तो वह एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष एजेंसी द्वारा कराई जायेगी।

सन्थानम समिति की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। हम तीन प्रकार का कार्य इस सम्बन्ध में कर रहे हैं। श्रष्टाचार का पता लगाना, जांच करना तथा श्रष्टाचार के मामले में कार्यवाही करने की प्रक्रिया को आधुनिक बनाना ; केवल आर्थिक अपराध सम्बन्धी मामलों के लिये एक आर्थिक अपराध विभाग स्थापित किया गया है। श्रष्टाचार के मामलों के बारे में विशेष विषयों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लागू किये गये हैं। अनुशासन-सम्बन्धी कार्यवाही के बारे में प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये नियमों में संशोधन किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनुपात से श्रधिक सम्पत्ति रखे जाने को अपराध माना गया है और सम्पत्ति जब्द करने का उपबन्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रशासन में श्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही करने के लिये विशेष प्राधिकार नियुक्त किये गये हैं, जिनको व्यापक अधिकार दिये गये हैं।

फरवरी, 1964 में केन्द्रीय सतर्कता श्रायोग स्थापित किया गया था। श्राठ राज्यों ने भी इसी प्रकार सतर्कता श्रायोग स्थापित किये हैं। दो राज्यों ने ऐसे श्रायोगों को स्थापित करना मान लिया है श्रीर दो राज्य इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। चार राज्यों में केन्द्रीय श्रायोग से भिन्न प्रकार के संगठन हैं।

मैं श्री माथुर से सहमत नहीं हूं जिन्होंने यह कहा है कि सतर्कता ग्रायोग का कोई लाभ नहीं है। इसे स्थापित किये जाने के लिये एक महत्वपूर्ण सिफारिश की गई थी ताकि भ्रष्टाचार के मामलों को दबाया न जा सके बल्कि उनके सम्बन्ध में जांच की जा सके।

इसके साथ-साथ जो दूसरी कार्यवाही हमने करनी है, वह भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में है। इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारी ग्राचार नियमों में संशोधन, उपहार स्वीकार करने तथा

[श्री नन्दा]

सम्पत्ति के बारे में जानकारी देना, सत्यनिष्ठा का पालन करना—ये सब कदम ठीक ही उठाये गये हैं। ऊंचे प्रशासनिक पदों के लिये ग्रिधकारियों को छांटने में बड़ी सावधानी बरती जा रही है ग्रौर जिन ग्रिधकारियों को सत्यनिष्ठा में सन्देह हो उन्हें पदोन्नत नहीं किया जाता ग्रौर उनकी सेवाविध नहीं बढ़ाई जाती। जो ग्रिधकारी ग्रपनी सत्यनिष्ठा के लिये बहुत प्रसिद्ध हैं उन्हें ही दोबारा नौकरी पर लगाया जाता है। जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है, राजनीतिक स्तर पर, मंतियों के लिये ग्राचार संहिता बनाई गई है।

यदि हम प्रशासिनक प्रित्रिया में सुधार करें तो बहुत सीमा तक भ्रष्टाचार समाप्त हो सकते हैं। इसिलये विलम्ब को दूर करने ग्रौर भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये प्रशासिनक सुधार के बारे में उन विभागों में जहां ग्राथिक मामलों सम्बन्धी कार्य होते हैं, एक विशेष कार्यक्रम ग्रारम्भ किया गया है ग्रौर इसके ग्रच्छे परिणाम निकल रहे हैं।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा घूस लिये जाने के मामलों, जिनके बारे में 1964 में कार्यवाही की गई, की संख्या 1963 की तुलना में 40 प्रतिशत ग्रिधिक है। न्यायालयों में भेजे गये मामलों में से 83' 6 प्रतिशत मामलों में दण्ड दिये गये तथा विभागीय कार्यवाही में 85. 9 प्रतिशत मामलों में दण्ड दिये गये तथा विभागीय कार्यवाही में 85. 9 प्रतिशत मामलों में दण्ड दिये गये।

उन विभागों में जहां जनता साधारणतया प्रशासन के सम्पर्क में स्राती है स्रौर सरकारी धन की हानि की स्राशा है। कई विशेष उपाय किये गये थे। 1965 में सार्वजनिक उपक्रमों में 205 ऐसे मामले पकड़े गये थे जहां लोगों के पास स्राय के साधनों से बहुत स्रधिक धन था।

कुछ चुने हुये विभागों की ग्रोर विशेष रूप से ध्यान देने के लिये चालू वर्ष में एक कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। परिमट, लाइसेंस ग्रौर कोटे के दुश्पयोग को रोकने के लिये बहुत बड़ी माता में कार्यवाही की जा रही है ग्रौर इस सम्बन्ध में मैं सदस्यों से बातचीत भी करना चाहता हूं। इस जोरदार कार्यवाही के प्रारम्भिक कार्य तो सम्बन्धित मंत्रालय करेंगे, परन्तु सरकारी कर्म-चारियों ग्रौर उन्तके संगठनों तथा सार्वजनिक संगठनों ग्रौर संस्थाग्रों का सहयोग भी प्राप्त किया जायेगा। मेरा ग्रभिप्राय यह है कि सरकारी कर्मचारी भी इन कार्यक्रमों में ग्रपना सहयोग दें। इन उपायों द्वारा भ्रष्टाचार में कितनी कमी हुई है, ग्रांकड़ों द्वारा नहीं बताया जा सकता।

श्रव हमने सीमा-शुल्क ग्रौर ग्रन्य विभागों में ग्राकिस्मिक जांच की प्रणाली ग्रारम्भ कर दी है। ग्रौर इस ग्राकिस्मिक जांच से जो सुधार हुग्रा है उससे मैं काफी सन्तुष्ट हूं।

चुनावों में भ्रष्टाचार दूर करने के मैंने प्रयत्न किये हैं परन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने एक सिमति नियुक्त की थी जिसने यह प्रतिवेदन दिया है। हमने छः या सात विभाग चुने हैं ग्रौर स्थिति का ग्रध्ययन कर रहे हैं; यदि स्थिति में सुधार हुग्रा तो इससे हमें काफी सन्तोय होगा ग्रौर यदि हमारे सब प्रयासों के बावजूद कोई सुधार नहीं हुग्रा तो हमें बहुत खेद होगा।

श्री स॰ मो॰ बनर्जी (कानपुर) : ग्राप दिल क्यों छोड़ रहे हैं।

श्री नन्दा: मैं इसे यथासम्भव शीघ्र करना चाहता हूं। लोगों में जो जागृति है, जो स्राशा जगी है, उसको हम तो इना नहीं चाहते। मेरे रास्ते में कुछ किठनाइयां स्रायेंगी ौर मैं स्रपने ही तरीके से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करंगा और मुत्रे ब्राशा है कि इस सम्बन्ध में मुझे सभी तरफ से समर्थन मिलेगा।

ब्यावार्य कुरनानी ने, वाद-विवाद के दौरान, गृह-मंत्री के आचरण पर ग्रीर उन संगठनों पर, जिनका गृह-मंत्री का समार्क है, अक्षेप किये हैं। उन्होंने उपदेशक का स्थान ले लिया है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और महात्मा गांधों का शिष्य कहलाने से पहले मुझे बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। श्री कुपनानी के उपदेश बिलकुल अन वश्यक हैं। जब गृह-मंत्रालय की मांगों पर चर्चा चल रही थी तो श्रो कुरलानी ने इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नाम क्यों घसीटा? अब इस संगठन से मेरा कोई समार्क नहीं। कोई समय था जब मेरा इससे सम्पर्क था। यह मजदूरों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है ग्रीर देश में सबसे बड़ा संगठन है; ग्रीर श्री कृपलानी ने इसे बहुत हानि पहुंचाई है। श्री रंगा ने भारत सेवक समाज पर लाखन लगाया है। परन्तु ग्रभी मैं इस संगठन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता; ग्रभी मैं हूवर ग्रायोग के प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

इस समस्या को सुलझाने के दो तरीके हैं—पहला तो यह है कि प्रत्येक विभाग को बारी बारी लिया जाय, उनके कार्य को जांच की जाय श्रौर फिर व्यवहारिक रूप में परिणत कर दिया जाय। हमारे पास ऐसी सिमितियां हैं जो इन सिफारिशों पर कार्यवाही करती हैं।

दूसरा तरीका है सम्पूर्ण व्यवस्था की जांच करना। परन्तु यह कार्य नहीं किया जा सकता; यह कार्य इतना बड़ा है कि इसका ग्राप अनुमान भी नहीं लगा सकते। ग्रतः हमने कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना ग्रारम्भ कर दिया है, जिससे वह इस बारे में ग्रध्ययन कर सकें। इस मामले को हम ग्रानिश्चित काल के लिये स्थिगत नहीं करना चाहते। हमने ग्रपने मंत्रालय की एक ग्रानीप-चारिक सलाहकार समिति बनाई है जिसके लिये 21 सदस्य चुने गये हैं जो इस समस्या का ग्रध्ययन कर रहे हैं। वह लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं ग्रीर जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री स॰ मो॰ बतर्जी (कानपुर) : ग्राप विट्ले परिषद् के बारे में क्यों नहीं कुछ कहते ?

श्री नन्दा: मुझे अफ नोस है कि विट्ले परिषदों के सम्बन्ध में कार्य में कुछ विलम्ब हुआ है अगैर मामला ग्रटका हुआ है। यह मामला हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने पर अटका हुआ है। हमने संस्थाओं से यह प्रस्ताव किया है कि क्योंकि हम मध्यस्थ निर्णय के लिये तैयार हैं उन्हें ऐसा संकल्प पारित करना चाहिये कि कोई हड़ताल नहीं होगी। परन्तु वे इसके लिये तैयार नहीं हैं।

श्री स० मो० बनर्जी: हम डिफेंस फैंडरेशन की ग्रोर से घोषणा करने के लिए तैयार हैं। श्री नन्दा: योगणा हो जाने दीजिये ग्रौर मैं इसे स्वीकार कर लूंगा ग्रौर उनको पता होगा कि मैं कुछ हो दिनों में एक सम्मेलन बुलाने वाला हूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने श्री बिज कृष्ण चांदीवाला का नाम यहां लिया जो कि इस सभा के सदस्य नहीं हैं। क्योंकि किसी ने ग्रापको कुछ सूचना दे दी थी, माननीय सदस्यों ने बिना मामले की जांच किये उनके चरित्र पर लांछन लगाया है माननीय सदस्यों ने ग्रपने विशेषाधिकारों का दृरुपयोग किया है।

श्री हरि विष्ण कामत: हम केवल इस मामले की जांच चाहते .

श्री नन्दा: मैंने फाईल देखी है ग्रीर यह निष्कासन का मामला है। इन सज्जन से मेरे सम्बन्ध के बारे में कुछ कहा गया है ग्रीर कहा गया है कि मेरा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। परन्तु इन सज्जन से सम्बन्ध बनाना मेरे लिये बड़े मान की बात है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने आपके सम्बन्ध के बारे में कुछ नहीं कहा था।

श्री नन्दा : ग्रापने नहीं तो किसी ग्रौर ने कहा होगा। यह सम्पत्ति 20 लाख रुपये के करीब है ग्रौर उन्होंने गांधीजी को दे दी थी। ग्रपनी ग्रावश्यकताग्रों के लिये उनकी थोड़ी सी ग्राय है। हो सकता है जो उन्होंने किरायेदारों को निकाला है वह गलत हो परन्तु उन्होंने ग्रपना सारा जीवन सामाजिक कार्यों में बिताया है।

श्री मौर्य : उन्होंने ग्रनुसूचित जातियों तथा ग्रादिम जातियों के लिये संविधान के ग्रन्तर्गत जो रक्षित स्थान हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा ।

श्री नन्दा: मैं इस सम्बन्ध में ग्रभी कुछ नहीं कह सकता परन्तु मैं इस प्रश्न पर विचार करंगा ग्रीर देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। मुझसे भाषा के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है मैं सभा को ग्राश्वासन देना चाहता हूं कि इस समस्या पर हम पूरा ध्यात दे रहे हैं ग्रीर मंत्रिमंडल की एक उपसमिति इस पर कार्यवाही कर रही है। यह बहुत ही जटिल समस्या है ग्रीर इसमें शी घ्रता करना ग्रच्छा नहीं होगा। इन चीजों पर विचार किया जा रहा है।

उन् ग्राश्वासनों को कान्न की रूप में लाने के लिये राजभाषा ग्रधिनियम का संशोधन करना जो इस ग्रिविनयम के वर्तमान उपबन्धों के ग्रधीन नहीं ग्राते। दूसरे, ग्रिखिल भारतीय ग्रीर उच्च केन्द्रीय सेवा परीक्षाग्रों के प्रादेशिक भाषाग्रों को माध्यम बनाने का सुझाव। ग्रीर वि-भाषीय फार्म्ले को कार्यान्वित करना। फिर हिन्दी ग्रीर प्रादेशिक भाषाग्रों के विकास का भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।

ग्रव जो माननीय सदस्यों ने भारत सेवक समाज, भारत साधू समाज ग्रार सदाचार समिति से मेरे स बन्धों के बारे में कहा, कुछ समय से मैं भी इसके बारे में चिन्तित हूं। गृह-मंत्रालय का इतना भारी कार्य है कि मैं समिति की ग्रध्यक्षता से त्यागपत्र देने का विचार कर रहा हूं। मैं इसके लिये किसी ग्रीर योग्य व्यक्ति की व्यवस्था करने के बारे में सोच रहा था। ग्रीर जब मैं इसकी ग्रध्यक्षता का पद त्याग दूंगा तो जिन माननीय सदस्यों को इस ग्रीर झकाव हो उनसे प्रार्थना करंगा कि वे इस कार्य को ग्रपने हाथ में ले लें। भारत सेवक समाज बिना किसी राजनैतिक उद्देश्य के चलाई जा रही है। जब कभी भी सरकार किसी कार्य में बहुत विलम्ब कर देती है ग्रथवा किसो ग्रपराधी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करती, तो जब भी कोई ऐसी बात हमारी सूचना में ग्राती है तो हम उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। मैं पूरी दायित्व की भावना से कह सकता हूं कि मैं ने कभी भी इसे कांग्रेस के लिये प्रयोग करने का विचार नहीं किया।

Shri Madhu Limaye: You have just copied the name of the Society founded by Gopal Krishan Gokhale.

श्री नन्दा: यह संगठन देश के सभी नेता श्रों के सामने बनाया गया था श्रौर इन सब नेता श्रों ने पंडित नेहरू को इसका अध्यक्ष बनने का अनुरोध भी किया था।

Shri Madhu Limaye: The leaders had opposed the stealing of the name.

श्री नन्दा: इस नाम को देश के सभी नेताग्रों ने स्वीकार किया था। उस समय क सोशिलस्ट दल ने एक संकल्प पारित किया था कि वे संगठन से कोई सम्पर्क नहीं रखेंगे।

Shri Buta Singh: Didn't its volunteers work in the All India Congress Session?

श्री नन्दा: जी नहीं :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): Please say something about obscene literature, films and magazines.

श्री नन्दा: हम ग्रश्लोल साहित्य के बारे में कानून को ग्रीर सुदृढ़ बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं।

माननीय सदस्य श्री कपूर सिंह सोच रहे होंगे कि मैंने वाद-विवाद में उन के भाग के बारे में कुछ नहीं कहा। सिखों ने जो देश के लिये काम किया है ग्रीर दर रहे हैं, उसको हम भूल नहीं सकते। उनको समाज, सरकार तथा देश में यथोचित स्थान दिया गया ग्रीर उनको शिकायत का कोई ग्रवसर नहीं मिलेगा।

मग्र-निषेध को नीति ज्यों की त्यों है। किसी समय मैं स्रवैतिनक मद्य-निषेध स्रायुक्त था, सो मुझे इस के काम के बारे में पूरी जानकारी है। स्रहमदाबाद में मुझे स्रत्यन्त रोमांचकारी स्रनुभव हुए। वहां मद्य-निषेध के लागू होने के पश्चात् जब कि वे ब्रिटिश स्रधिकारी, जिन्होंने पहले इसकी हंसी उड़ाई थी, वहां के अमिक वर्ग के जीवन में स्राश्चर्यजनक परिवर्तन देखकर दंग रह गये। लेकिन यह मेरा दृढ़ मत है कि मद्य-निषेध केवल सरकार, ग्राबकारी विभाग ग्रीर पुलिस के बल पर सफल नहीं हो सकता। राजनैतिक दल कुछ करें, लेकिन स्वैच्छिक संस्थायें इस क्षेत्र में स्रथवा स्रन्य क्षेत्रों में बहुत सहायता कर सकती हैं। यदि उनमें कोई दोष है तो उसे दूर करें लेकिन उनका उत्साह भंग न करें। मैं जानता हूं कि हजारों ईमानदार, कर्त्तव्यनिष्ठ तथा सच्चे कार्यकर्ता हैं। हो सकता है कुछ स्रादमी स्रच्छे न हों।

मैं सदाचार समिति का प्रधान नहीं रहूंगा

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): We want to know what measures have been taken to prevent taking of wines by the Ministers.

श्री नन्दा: मुझे नहीं मालूम। किसी ने भी किसी मंत्री का नाम नहीं बताया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Morarji Desai says that Ministers also drink.

श्री नन्दा: मुझे नहीं मालूम यदि मोरार जी भाई किसी मंत्री के साथ उस समय बैठे थे जब कि मंत्री शराब पी रहे थे ।

Shri Bagri: P. A. to the Prime Minister was arrested while he was drunk.

श्री नन्दा: मैं समझता हूं कि मेरे सदाचार समिति छोड़ ने के पश्चात् सदाचार की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो जायेगी तथा इस पर पिछले चन्द दिनों में की गई व्यंगोक्तियां व उपहास नहीं किया जायेगा। यदि 'सदाचार' शब्द बुरा है तो दूसरा नाम बाद में इससे भी बुरा बन जायेगा। नाम से क्या होता है ? महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम इस बारे में क्या करते हैं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar): Will the hon. Home Minister like to say a word or two about banning the cow-slaughter?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Many bulls are slaughtered at Bombay Port.

Shri Bagri: Swami Rameshwaranand is on hunger strike.

श्रो नन्दा: मैं समझता हूं कि अनेक राज्यों में गोहत्या बन्द हो गई है। मेरा विश्वास है कि कानून की अपेक्षा यह काम समाज के विभिन्न वर्गों की सहायता से अधिक अच्छी प्रकार से किया जा सकता है।

Shri Maurya: Nothing has been done for the most backward and oppressed section of the society, the Scheduled Castes. The Minister has not said even a word about them?

श्री नन्दा: यह विभाग ग्रब मेरे ग्रधीन नहीं रहा। मेरे माननीय मित्र को यह नहीं मालूम कि मैंने ग्रहमदाबाद के हरिजनों की सेवा में ग्रपने जीवन का ग्रधिकांश भाग बिताया है। ग्रन्त में मैं देश की स्थित के विचार में छोटे छोटे झगड़ों को छोड़ कर एकता, संगठन तथा कन्धे से कन्धा मिलाकर संकट का सामना करने के लिये तथा इसके लिये कोई कसर नहीं उठा रखने के लिये ग्रनुरोध करूंगा।

श्री हिर विष्णु कामत: कल मैंने ग्रघ्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में भेंट की थी ग्रीर उन्होंने माननीय मंत्री के भाषण के पश्चात् मुझे यह प्रश्न उठाने की ग्रनुमित दे दी थी। दो महीने से भी ग्रिधिक हुए जब कि मैंने राष्ट्रपित के ग्रिभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव पर ग्रपने भाषण में 22 फरवरी को इसका उल्लेख किया था लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया गया। फिर मैंने एक प्रश्न की सूचना भी दी। लेकिन प्रश्न ग्रभी भी नहीं निपटाया गया है।

1960 की प्रादेश याचिका संख्या 796 पर मद्रास के एक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में वर्तमान खाद्य तथा कृषि मंत्री के आचरण की कटु तथा कठोर भाषा में टिप्पणी की थो। मैं ने अपने भाषण में प्रधान मंत्री से इस टिप्पणी तथा इसको घ्यान में रखते हुए श्री सुब्रह्मण्यम् के मंत्रिमंडल में रहने के बारे में विचार करने के लिये कहा था। इसका उत्तर नहीं दिया गया।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथो): यदि उन्होंने ग्रपने भाषण में इसका उल्लेख किया होता तो मैं इसका उत्तर दे देता। मैं इसका उत्तर देने को तैयार हूं। यह 1960 की पांच साल पुरानी घटना है। मद्रास विधान सभा में इसके बारे में एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा था। श्री भक्तवत्सलम् ने मुख्य मंत्री श्री कामराज का वक्तव्य पढ़ कर सुनाया था। जहां तक न्यायालय के निर्णय का सम्बन्ध है उसमें यह कहा गया था कि किसी नियम, विनियम ग्रथवा कानून का उल्लेखन नहीं किया गया। माननीय मित्र ने जिस टिप्पणी का उल्लेख किया वह तो पार्थ्व-निर्देश (ग्राबिटर डिक्टा) थे। उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी थी।

श्रो हिर विष्णु कामत: वे केवल भ्रम में डाल रहे हैं। मेरे पास निर्णय की एक प्रति है।

श्री हाथी : यदि उनके पास निर्णय की प्रति है तो वे उसका अन्तिम पैराप्राफ पढ़ें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रब यह पढ़ना श्रावश्यक नहीं है।

श्री उ० म्० त्रिवेदी: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय किस विषय पर चर्चा हो रही है? क्या यह वर्तमान चर्चा से सम्बन्धित है?

श्री हाथी: इस मामले पर 1960 में मद्रास के मुख्य मंत्री ने मद्रास विधान सभा में एक वक्तव्य दिया ग्रौर उसके पश्चात् वहां कोई चर्चा नहीं हुई। ग्रव पांच साल बाद श्री कामत उस मामले को फिर से उठा रहे हैं।

उगाव्यक्ष महोदय : पहले मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 84 को मतदान के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है :---

"कि गृह-मंत्रालय शीर्धक के अन्तर्गत मांग को घटा कर 1 रूपया कर दिया जाये।" [बिना मुकदमा चलाये राजनैतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उनका निरोध] (84)

लोक-सभा में मत-विभाजन हुमा ।
The Lok Sabha divided
पक्ष में 32 ; विपक्ष में 108
Ayes 32; Noes 108
प्रस्ताव ग्रस्वोकृत हुमा ।
The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटोती प्रस्ताव संख्या 9 से 14 तथा 32 से 34 मतदान के लिये रखे गये तथा ग्रस्वीकृत हुए ।

Cut Motion Nos. 9 to 14 and 32 to 34 were put and negatived उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव संख्या 94, प्रश्न यह है :--

"िक गृह मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।"

[देश में तेजी से बढ़ती हुई भ्रष्टाचार की बीमारी को गम्भीरतापूर्वक दूर न करना ।]

लोक-सभा में मत-विभाजन हुग्रा ।
The Lok Sabha divided
पक्ष में 31 ; विषक्ष में 105
Ayes 31; Noes 105
प्रस्ताव ग्रस्वीकृत हुग्रा ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 114 मतदान के लिये रखा गया तथा ग्रस्वीकृत हुग्रा ।

The cut motion No. 114 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्रन्य सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा श्रस्तीकृत
हुए ।

All the other cut motions were put and negatived

ग्रव्यक्ष महोदय द्वारा गृह-कार्य मंत्रालय की निम्त्रलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following Demands in respect of Ministry of Home Affairs were put and adopted:

मांग संख	या शीर्षक				राशी
					रुपये
51	गृह-कार्य मंत्रालय	•			4,04,34,000
52	मन्द्रि मण् डल				44,00,000
53	क्षेत्रीय परिषदें	•			1,10,000
54	न्याय प्रशासन				2,69,000
55	पुलिस .				15,00,14,000
56	जनगणना	•			1,15,03,000
57	ग्रंक-संकलन .	•			2,20,35,000
58	भारतीय राजास्रों की निज	ी थैंलियां ग्रौर भ	ात्ते .		86,000
59	दिल्ली	•			19,78,44,000
60	म्रंडमान भ्रौर निकोबार द्व ी	ोप समूह			3,12,42,000
61	दादरा स्रौर नगर हवेली क्षे	रेत .		•	21,19,000
62	लक्षदीवी, मिनिकोय ग्रौर	ग्रमीनदीवी द्वी प	समूह .		48,22,000
63	गृह-कार्य मंत्रालय का ग्रन्य	ा राजस्व व्यय			2,92,69,000
132	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी	परिव्यय			72,73,000

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय

वर्ष 1965-66 के लिये खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं:---

मांग संख	प्रा शीर्षक				राशि
					रुपये
42	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय				. 80,38,000
43	कृषि				. 3,48,10,000
44	कृषि सम्बन्धी गवेषणा				. 5,43,33,000
45	पशु-पालन		•		. 1,07,44,000
46	वन		•		. 1,21,74,000
47	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय क	। ग्रन्य राज	स्व व्यय		. 29, 37, 12, 000
128	वनों पर पूंजी परिव्यय	•			. 1,57,000
129	ग्रन्न की खरीद .			•	3, 33, 13, 75, 000
130	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का	। भ्रन्य पूंज	नी परिव्यय		70,29,77,000

उपाध्यक्ष महोदय: ये मांगें सभा के सामने हैं।

श्री तरिसम्हा रेड्डी (राजमपेट): श्री सुब्रह्मण्यम् दुष्कर कार्यं से दक्षिण में हिन्दी-विरोधी स्नान्दोलन के समय छुटकारा पाना चाहते थे लेकिन श्री कामराज ग्रौर शास्त्री के निष्ठुर हाथों ने उन्हें बिल के बकरे के समान बामपंथियों की कटु ग्रालोचना का लक्ष्य बनने के लिये ग्रच्छी तरह बांध कर बैठा दिया। गेहूं के लिए एक करार करने के लिये श्री सुब्रह्मण्यम् ग्रधिकारियों के ग्रच्छे खासे दल-बल के साथ ग्रास्ट्रेलिया की लम्बी यात्रा पर ऐसे समय गये जब कि वहां सूखा पड़ गया है। वहां की सरकार ने गेहूं देने में ग्रसमर्थता प्रकट की लेकिन ग्रपने मन हंसते हुए संसद सदस्यों के लिये संसद भवन में स्थापित करने के लिये एक दुग्धशाला (मिल्क बार) भेंट की। ग्रधिकांश सदस्यों के विचार में इसकी कोई ग्रावश्यकता नहीं है क्योंकि यहां पहले ही एक दुग्धशाला है। हां, यदि कोई ग्रौर "बार" स्थापित किये जायें तो वे उसका स्वागत करेंगे। इस यात्रा पर विदेशी मुद्रा ग्रादि पर कुल 2 लाख हिपये व्यय हुए जब कि केवल एक रुपये डाक-टिकट पर व्यय करके यह स्थिति पत्र द्वारा पता की जा सकती थी।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि॰ सुब्रह्मण्यभ) : यह अच्छा होता यदि माननीय सदस्य को प्रतिनिधिमंडल में व्यक्तियों की संख्या, विदेशी मुद्रा तथा अन्य बातों के बारे में ठीक जानकारी होती।

श्री नरिसम्हा रेंड्डी: ग्रपने उत्तर में वें ठीक जानकारी दे सकते हैं।

श्री चि॰ सुब्रह्मण्यम्: यह उत्तर देने योग्य बात नहीं है।

श्री नरिसम्हा रेड्डी : खाद्य ग्रीर कृषि की समस्या, चीन के ग्राक्रमण, पाकिस्तान की घुसपैठ ग्रथवा चीन समर्थक साम्यवादियों की लुकी-छिपी गितविधियों, जितनी ग्रथवा उनसे कहीं ग्रधिक महत्वपूणें है। यह सर्वविदित है कि हवा, बाढ़, वर्षा, कीड़ों ग्रादि का उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है ग्रीर इस के ग्रनुसार भावों में उतार-चढ़ाव होता है। फसल की दृष्टि से पिछला वर्ष खराब था। देश के कुछ भागों में न केवल कृषि-मूल्य ग्रत्यधिक बढ़ गये थे बिल्क कुछ ग्रन्य भागों में किसी भी मूल्य पर ग्रनाज नहीं मिल रहा था। सरकार को इसका पूर्वाभ्यास होना चाहिये था तथा स्थिति का सामना करने के लिये बफ़र स्टाक बना लेना चाहिये था। इसी कारण सरकार साम्यवादियों द्वारा कड़ी ग्रालोचना की शिकार हुई, जो हमेशा ऐसे ग्रवसर की ताक में रहते हैं। खाद्य तथा कृषि मंत्री ने शान्त चित्त से काम नहीं लिया ग्रीर मूल्य नियंत्रण, ग्रनाज खरीदना व राज्य व्यापार चालू करके खुली मण्डी में हस्तक्षेप करने की नीति ग्रारम्भ कर दी।

ग्रान्ध्र प्रदेश के सम्बन्धित मंत्री ने विधान-सभा में तथा समाचार-पत्नों में यह वक्तव्य दिया है कि किसी भी परिस्थिति में ग्रनाज उत्पादकों से नहीं लिया जायेगा। लेकिन किसानों को नोटिस दिये गये हैं कि प्रत्येक पखवाड़े में एक बार वे ग्रपने ग्रनाज के भण्डार बताते रहें। इससे किसानों को ग्रनावश्यक कठिनाइयां होंगी तथा यह ग्रनपढ़ किसान को ग्रपना सारा घ्यान खेती की ग्रोर लगाने में बाधक होगा। जनता के प्रतिनिधियों को यह शोभा नहीं देता कि वचन देने के कुछ दिन बाद ही उनसे पीछे हट जायें।

निर्धारित किये गये कृषि मूल्य बाजार भाव से कम हैं। मूल्य निर्धारित करते समय सरकार ने घी, चीनी, दूध, फल, सब्जी कृषि उपकरणों की बढ़ती हुई कीमतों को घ्यान में नहीं रखा

[श्री नरसिम्हा रेड्डी]

है। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के ग्रधीन दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा संसद-भवन में बेचे जाने वाले घी का मूल्य 8 रू० प्रति किलो से 9 रू० 25 पैसे कर दिया है। ग्रौद्योगिक उत्पादनों के मूल्यों का नियंत्रण क्यों नहीं करते? इसका कारण है कि सरकार उद्योगपितयों को ग्रप्रसन्न नहीं करना चाहती क्योंकि वे कांग्रेस को बहुत सा धन देते हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि कांग्रेस दल ग्राज किसानों के बल पर सत्तारूढ़ है। किसान चट्टान के समान ग्रडिंग रहे हैं ग्रौर प्रत्येक चुनाव में साम्यवादियों की विचारधारा व प्रचार टकरा कर रह गई। में सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि वे उनके ग्रान्दोलन से डर न जायें क्योंकि चीन ग्रौर रूस की तरह यहां भी किसानों को निर्बल करना चाहते हैं।

योजना श्रायोग को तो श्रकाल श्रायोग कहना चाहिये। योजना श्रायोग में कम से कम एक तो ऐसा व्यक्ति होता जो कुछ वर्ष गांवों में रहा होता तथा जिसे गांवों के जीवन का पूर्ण ज्ञान होता है। योजना श्रायोग में शहर के ऊंचे भवनों में बैठ कर शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भरने से ग्रामीण भारत में समाजवादी व्यवस्था नहीं हो सकती। ग्रामीण लोग खेती का काम छोड़ कर बड़ी संख्या में शहरों में ग्रा रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं उन्हें वहां श्रिधक मजूरी मिल सकेगी। मंत्री महोदय को कृषि में कमी के मूल कारण को समझना चाहिये, किसान हताश श्रीर निराश क्यों हैं? ट्रैक्टर, बुल-डोजर, कृषि-उपरकण देने के श्रितिरक्त खाद्य जोन समाप्त कर देने चाहियें, मूल्य नियंत्रण समाप्त कर देने चाहियें और निर्वाध व्यापार की श्रन्मित देनी चाहिये तथा बक्तर स्टाक बनाने चाहियें। किसानों को समय पर तथा उचित मूल्य पर उर्वरक नहीं मिलते। उर्वरकों की चोरबाजारी हो रही है। श्राज मैंने तेलगू समाचार पत्नों में श्रान्ध्र प्रदेश कांग्रेस के प्रधान तथा श्रान्ध्र के सम्बन्धित मंत्री का एक वक्तव्य पढ़ा जिसमें इस चोरबाजारी के बारे में कहा गया है। मैंने ग्रपने निर्वाचन क्षेत्र में ग्रधनं किसानों को विपणन समितियों के कार्यालयों पर खड़े श्रीर श्रन्त में खाली हाथ जाते देखा है। ये समितियां धांधली कर रही हैं। केन्द्रीय जांच विभाग (सी० ग्राई० डी०) द्वारा समितियों के कार्यकरण की जांच करानी चाहिये तथा श्र9राधियों को साम्यवाधियों की तरह कठोर दंड देना चाहिये।

ऋणों के संबंध में मेरा सुझाव है कि 2 वर्ष के अल्पकालीन ऋण पर कोई ब्याज नहीं लेना चाहिये तथा दीर्घकालीन ऋणों पर 2 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं होना चाहिये। भारत सेवक समाज, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जैसी संस्थाओं पर करोड़ों रूपया व्यर्थ व्यय किया जा रहा है। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को दिया गया 50 लाख रूपये के ऋण का भुगतान माफ किया जा रहा है। फिर किसानों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जात ।। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर विचार करें तथा राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दें। राजस्थान, गुजरात, रायलसीमा जैसे प्रदेशों में कुओं में नलकूप लगाकर सिंचाई व्यवस्था की जा सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों को भारी कर देने पड़ते हैं । योजना ग्रायोग की प्रेरणा से राज्य सरकारों ने करों में 300 से 400 प्रतिशत वृद्धि कर दी है । सभी ग्रप्रत्यक्ष करों का भार किसानों को उठाना पड़ता है । मेरे दल के विचार से भूमि-कर को समाप्त कर देना चाहिये । किसानों को यह भय है कि उनसे उनकी भूमि छीन ली जायेगी। भूमि की सीमा (सीलींग) सारे देश में एक समान नहीं है । सरकार को भूमि संबंधी सभी विधानों पर तथा संविधान (सातवां) संशोधन प्रादि पर पुनविचार करना चाहिये ।

श्री सुब्रह्मण्यम् को ग्रपने देश व जनता की सेवा करने का ग्रभूतपूर्व ग्रवसर मिला है। उन्हें ग्रब दृढ़ता से काम लेना चाहिये तथा निर्मम, निर्देयी व नास्तिक विचारधारा को हमारे देश की शान्तिपर्ण तथा हरे-भरे जीवन को नष्ट नहीं करने देना चाहिये। मूल्य नियंत्रण, सहकारी खेती, समाहार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण ग्रौर राज्यव्यापार साम्यवाद के ऐसे विभिन्न पहलू हैं जो हमारी कृषि ग्रर्थ-व्यवस्था का गला घोट देंगे तथा हमारी संस्कृति के बचे हुए स्रोतों को सुखा देंगे। मैं उनसे कहूंगा कि ग्रपने पूर्वजों की परम्परा के ग्रनुष्ट्प कार्य करें। वे मार्क्सवादी सिद्धान्तों के ग्रागे झुकें तथा किसानों का गला काटें ऐसा करने से पहले मैं उन्हें सलाह दूगा कि बंगाल की खाड़ी में छलांग लगा लें।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): Mr. Deputy-speaker, I support the demands for grants of the Minister of Food and Agriculture. I am speaking on this subject for the last 13 years yet this department is giving what was expected of it. For the failures the centre blames the states and vice versa and they escape from the responsibility.

First necessity in this field is to increase production. The irrigation facilities were not utilised to the full extent. Why did this happen? Even after 17 years of independence the administration has done very little. In contrast to it Sher Shah ruled only for 5 years yet in that small period he brought about improvement in every field to the construction of department roads. cement, iron etc. are not available and so the peasants cannot dig well to irrigate their fields. The rates of water are exorbitant U.P. and Bihar. In India agriculture has not improved although we have I.C.S. officers and Ph.Ds. Have they got any experience agriculture? They were trained for the purpose of drafting notes etc. They do not have practical experience of agriculture. Farmers who have adequate experience of agriculture, are never consulted in agricultural problems. The majority of the population depends on agriculture and we are not self-sufficient in food. It is a matter of regret that the country has not made any remarkable progress even after 17 years of our independence. It is only because of the fact that adequate attention has not been paid to agriculture and its development. It is, therefore, absolutely necessary that agriculture should be given top priority with a view to achieving our plan targets. Adequate irrigational facilities should be provided to farmers and proper steps taken to check soil-erosion. The field officers of agriculture this Department are not taking keen interest in matters relating to agricultural development. So there is a pressing need to improvethe working of this Department.

Now I come to the Gandak Project. The project should be taken over by the Centre. This is a project which will irrigate many a many acre of land in U.P. and Bihar. A Coordination Board has been constituted but we were not consulted in the matter. There is no Coordination between the officers of Department of agriculture and these working under B.D.O.S. and at the same time they are not in good terms with one another and this tension puts obstacles in the way of agricultural development. With a view to increasing the production of agricultural commodities, it is suggested that this project may be transferred to the Department of Agriculture.

[Shri Bibhuti Mishra]

There was a bumper crop of sugarcane in our State this year. The output was really much more than what the growers actually expected. There are two sugar factories, but they have not the crushing capacity to consume all the sugarcanes produced there. So there is a pressing need to modernise, expand and increase the crushing capacity of these factories with a view to solve this problem hence, Government should take necessary steps to do the needful. One Sen Commission visited this area to make an assessment of the situation. The visit of this Commission has given a feeling to the farmers that all the sugar factories are being shifted to South India. The hon. Minister should, thereof, ensure that the sugar mills are not dislocated.

The Agricultural Prices Commission has been set up and Government have not accepted a suggestion made by the All India Congress Committee regarding integrated remunerative price to be paid to farmers. The representatives of the producers have no place in this commission. It has always been the policy of Government to neglect the farmers. I would suggest that Government should take active steps to see that all the facilities and assistance required for the development of agriculture are provided to the farmers and they are paid more for their production.

Shri Sarjoo Pandey (Rasra): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is really a matter of shame that the grave food problem of the country has not so far been solved even after 17 years of our independence in spite of repeated and continued assurances given by our Ministers regarding self-sufficiency in food.

Today the country is faced with food problem and the prices of all the commodities are persistently increasing. Government have to import lakhs of tonnes of foodgrains. But the Food and Agriculture Minister expects a bumper crop every year. I charge the Government that they did not deliberately take any interest in improving the method of cultivation and they did also not take any active step to increase the output of foodgrains. Many Committees were formed to go into the question of land-reform. They recommended that the land should be given to the tiller with a view to increasing the production. No doubt, the Government took a bold step to abolish the Jamindari system but it did not serve the real purpose as the land was not transferred in the names of tillers. The U.P. Government started consolidation of holdings. But I can say with full confidence that this system has created a new arena of corruption and which is responsible for exploitation and sufferings of the poor farmers. Government servants made a lot of money through this source in the name of consolidation of holdings. Going through various reports on the Land Reforms in the country, we come to the conclusion that the tillers were not benefited at all by these reforms and on the other hand, they involved in litigations and many of them also suffered eviction. These are the outcomes of our land reforms.

Government have established community Development Blocks and Extension Service Blocks for the benefit and development of the people. Hundreds of employees, such as BDOs, ADOs, VLWs,

etc. have been working there. But they do not pay any attention to the problems of farmers. They always furnish wrong data and Government would not succeed in their plan targets if they prepared plans on the basis of the data furnished by these officers. Planning does not mean the setting-up of new departments only. So far as agriculture is concerned, the most pressing need of the day is to provide all the facilities and assistance to the farmers required for the production of agriculture commodities. These Development and Extension Blocks are spending a lot of money on useless purposes. They often organise various exhibitions, cultural shows, cattle shows, social functions, etc. where tea, sweets and other eatables are served and speeches are delivered by some leaders who are invited on such occasions.

Government should take active steps to provide irrigational facilities to the farmer. Minor irrigation projects which are not economical also have not proved useful for the purpose. Many schemes and projects are not being completed as per schedule due to acute shortage of cement, iron and other materials.

Licences are also issued by this Department for starting Cooperative Sugar Factories. Licences in respect of nine Co-operative
Sugar Factories of Uttar Pradesh are lying pending with this Department. I myself addressed letters to the hon. Food and Agriculture Minister in this behalf. There is a proposal to start a Cooperative Sugar Mill at Rasra in the district of Balia. All the
formalities in this respect have been completed. We have been in
correspondence with the Centre for the last three years, but to our
utter surprise, the Department have neither issued a licence in
favour of this proposed mill and not have they been able to take
any decision on the matter. I request the hon. Minister to look
into this case and do the needful.

Corruption is also creeping in these Blocks Farmers are being supplied impure manures. There is need to improve the working of these Blocks.

All cheap foodgrain shops have been allotted to Congress leaders who indulge in blackmarketing. It is desirable that Government should not allot cheap foodgrain shops to any political worker.

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : उपाम्यक्ष महोदय, हर्ष की बात है कि इस समय देश में उत्पादन अधिक हुआ है। खाद्य तथा कृषि मंत्री के लिए कृषकों की कि नाइयों से अवगत रहना तथा उनसे सम्पर्क बनाना वांछनीय है।

देश कृषि पर ग्राधारित उद्योगों की स्थापना तथा उन्हें चलाने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना नितान्त ग्रावश्यक है । रूस ने भी ग्रव कृषि को तथा कृषि सम्बन्धी वस्तुग्रों के मूल्यों को प्रो—त्साहन देने की नीती ग्रपना ली है । रूस इस परिणाम पर पहुंचा है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुग्रों के लिए ग्रधिक मूल्य देना ग्रावश्यक है । ग्रतः उन्होंने हाल में 100 प्रतिशत मुल्य बढ़ा दिये हैं । मूल्य नीति के कारण संयुक्त रूप से खेती करने वाले किसानों पर ऋण का बहुत भार हो गया था किन्तु रूस सरकार ने उन सब ऋणों को रह कर दिया है । किन्तु हमारे देश में मूल्य नीति के परिणामस्वरूप कृषक ऋण से दबे हुए हैं ।

[श्री पु० र० पटेल]

जापान में कीमतें मूल्य समिति जिसमें संसद् सदस्यों, उपभोक्ताग्रों, उत्पादकों तथा व्यवसाय में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, मूल्य निर्धारित करती है। किन्तु हमारे देश में कृषि मूल्य ग्रायोग में संसद्-सदस्यों, उपभोक्ताग्रों तथा उत्पादकों का कोई भी प्रति—िविद्य नहीं है। जापान में सरकारी ग्रिभकरणों के जिरये सरकार चावल एकितत करती है, किन्तु चोरबाजारी वहां भी चलती है। ग्रतः हमें केवल ग्रपने लोगों को ही दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जापान में सरकार खाद्यान्न को ऊंची कीमत पर खरीद कर उन्हें उपभोक्ताग्रों को कम मूल्य पर बेचती है। इस प्रकार जापान की सरकार लगभग 900 करोड़ येन (yen) की हानि सहन करती है। किन्तु हमारे देश में इसके प्रतिकूल मामला है। वहां बाहर से ग्रायात किये गये ग्राज को सरकारी ग्राभकरणों के मार्फत लाभ उठाकर बेचा जाता है ग्रीर ग्रपने देश के ग्रानाज को सरकार ऊंचे मूल्य पर खरीदकर उसे कम मूल्य पर बेच कर उससे होने वाले घाटे को स्वयं वहन करती है। इस प्रकार जापान सरकार कृषि-उत्पादन को प्रोत्साहन देती है।

हमारे देश में सरकार विदेशों से ग्रायात किये गये खाद्यान्नों पर हानि उठा कर उन्हें उपभोक्ताग्रों को कम मूल्य पर बेचती है। दूसरे शब्दों में वह विदेशी कृषकों को प्रोत्साहन देती है। मुझे ग्राशा है कि सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी।

ब्रिटेन में तीन क्रुजिक संघों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाता है। किन्तु हमारे देश में इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए सरकार केवल विशेषज्ञों की नियुक्ति कर देती है। ब्रिटेन में खादों के लिए तक सरकारी सहायता दी जाती है ग्रौर वहां खाद लागत-मूल्य से कम कीमत पर दी जाती है क्योंकि मन्त्रालय ग्रनुदान के रूप में धन देकर विक्रय मूल्य कम करने में सहायक होता है। किन्तु हमारे देश में खाद की कीमत बढ़ायी जा रही है—इसलिए कि कहीं सिन्द्री कारखाने को घाटा सहन न करना पड़े—ग्रतः कृषक को मूल्य-भार सहन करना पड़ता है।

सरकार को किसानों की किसी न किसी तरीके से अवश्य सहायता करनी चाहिये । अमरीका जैसे देश में भी किसान संघों के प्रतिनिधियों से परामर्श लिया जाता है तथा कीमतें निर्धारित की जाती हैं हालांकि वहां पर किसानों की संख्या केवल 11-12 प्रतिशत है। परन्तु हमारे यहां पर तो किसानों की संख्या लगभग 70 प्रतिशत है। इसलिये क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उनके संघों के प्रतिनिधियों से सलाह आदि करें और उन द्वारा पैदा की गई चीजों की कीमतें निर्धारित करें। इसके अतिरिक्त हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम उत्पादन बढ़ाने के लिये उनको सुविधायें प्रदान करें।

परन्तु यहां पर क्या हो रहा है ? कुग्रों से होने वाली सिंचाई के लिये तेल द्वारा चलने वाले इंजनों में प्रयोग किये जाने वाले ग्रशोधित तेल के दाम पिछले पांच वर्षों में दुगुने हो गये हैं। इसके लिये ग्रर्थ सहायता दी जानी चाहिये। ऐसे ही बिजली के दामों में कमी होनी चाहिये ताकि किसान उस का ग्रिधिक से ग्रिधिक प्रयोग कर सकें। परन्तु गुजरात में कृषि के प्रयोग में लाई जानी वाली बिजली हमें 3 ग्राने प्रति यूनिट के हिसाब से मिल रही है। इसलिये सरकार को किसानों की सहायता के लिये कुछ न कुछ ग्रवश्य करना चाहिये।

हम ट्रैक्टरों का ग्रायात करते हैं। हमारे पास पहले ही 40,000 ट्रैक्टर हैं जिनमें से 20,000 पुर्जों के न मिलने के कारण बेकार पड़े हैं। फिर ट्रैक्टर ग्रायात करने की क्या ग्रावश्यकता है, हमें उनके पुर्जों का ग्रायात करना चाहिये।

हम कृषि गवेषणा सम्बन्धी भारतीय परिषद् पर बहुत धन व्यय कर रहे हैं। परन्तु गवेषणा करने ग्रौर उपगवेषणा का खेतों में प्रयोग करने में बहुत ग्रन्तर है। हमें इस बात को देखना चाहिये कि जो भी गवेषणा हो उसको खेती में प्रयोग में लाया जा सके ग्रौर यह तब हो सकता है जब कि गवेषणा के परिणाम किसानों को उपलब्ध हों।

किसान ऐसे होने चाहियें जिन को कृषि विज्ञान स्राता हो । परन्तु यह कैसे सम्भव है जब तक किसान पढ़े न हों । यहां पर जो लोग पढ़े हुए भी हैं स्रीर कृषि विज्ञान में स्रर्हता प्राप्त भी हैं वे खेती में जाकर कामन हीं करना चाहते । इसलिये हमारी खेती का यह दुर्भाग्य ही समझा जाना चाहिये ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का ग्राधार	कटौती की राशि
42	6	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	कृषि विभाग के कार्य को सुव्यवस्थित करने की ग्रावश्यकता।	100 रुपये
42	7	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	ग्रधिक उर्वरकों, ग्रच्छे बीजों, पानी सम्बन्धी सुविधाग्रों, कीटनाशक पदार्थों ग्रादि की ग्रावश्यकता ।	100 रुपये
42	8	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	भावों ग्रौर स्टाक इकट्ठा करने के सम्बन्ध में सुसंबद्ध ग्रौर स्पष्ट नी— तियों की ग्रावश्यकता ।	100 रुपये
42	9	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	भूमि विषयक नीती की ग्रसफलता।	100 रुपये
42	10	श्री वारियर	पैदावार इकट्ठा करते समय काली मिर्च ग्रीर श्रन्य मसालों की फसलों के उचित भाव सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करने की श्रावश्यकता ।	100 रुपये
42	11	श्री वारियर	केरल राज्य में तुरन्त संविहित राशनिंग लागू करने की ग्रावश्यकता।	100 रुपये
42	12	श्री वारियर	केरल राज्य में राशन की मात्ना बढ़ाने की स्रावश्यकता ।	100 रुपये
42	13	श्री वारियर	केरल राज्य में राशन के चावल का भाव कम से कम उस स्तर तक कम करने की श्राश्वयकता जो छै महीने पहले था।	100 रुपये

मांग संख्या	कटाती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम		कटौती का स्राधार कटौती	की राशि
42	14	श्री वारियर		वर्षा ग्रारंभ होने से पहले केरल राज्य में 10 पर्याप्त फालतू भंडार (बफर स्टाक) रखने की ग्रावश्यकता ।	0 रुपये
42	15	श्री वारियर		सभी महत्वपूर्ण नगरों ग्रीर ग्रीद्योगिक 10 केन्द्रों में मानक भोजन (स्टैन्डर्ड मील्स) चाल करने की ग्रावश्यकता ।)0 रुपये∷
42	16	श्री वारियर		केरल राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में राशन 10 के चावल का कोटा बढ़ाने की ग्रावश्यकता।	00 रुपये
42	17	श्री वारियर	•	केरल राज्य में गहरे समुद्र में मछली 10 पकड़ने का प्रशिक्षण केन्द्र स्थिपित करने की श्रावश्यकता ।	00 रुपये
42	18	श्री वारियर	•	खाद्य निगम द्वारा ग्रनाज के सभी वर्त- 10 मान सरकारी डीपूग्रों को कायम रखने ग्रौर उन्हें चलाने की ग्राव- श्यकता।	00 रुपये:
42	19	श्री वारियर		खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार के 10 ग्रानाज डीपूग्रों में माल लादने ग्रीर उतारने वाले कर्मचारियों की नौकरियां कायम रखने की ग्रावश्यकता।	00 रुपये∷
42	20	श्री वारियर	•	कृषिजन्य वस्तुग्रों के ग्रार्थिक मूल्य 10 की दरें निर्धारित करने की ग्राव- श्यकता।	00 रुपये
42	21	श्री वारियर		ग्रौर ग्रिधिक पैकेज कार्यक्रम चालू करने 1 की ग्रावश्यकता।	०० रुपये
42	22	श्री वारियर		श्रनाज के लिये फसल बीमा योजना 1 चालू करने की भ्रावश्यकता ।	00 रुपये
42	23	श्री वारियर		करल राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में मछली 1 पकड़ने से सम्बन्धित बड़े-बड़े गांवों में बर्फ के कारखाने खोलने की ग्रावश्यकता।	०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का ग्राधार	कटौती की राशि
42	24	श्री वारियर	केरल राज्य में मछली पकड़ने की नावों में मशीने लगाने के संबंध में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने की ग्रावश्यकता ।	100 रुपये
42	25	श्री वारियर	केरल राज्य में मछुग्रों को नौकाएं उधार देने की स्रावश्यकता ।	100 रुपये
42	26	श्री वारियर	केरल राज्य में मछली पकड़ने के बन्दर- गाहों का विकास करने और नए बन्दरगाह बनाने की ग्रावश्यकता ।	100 रुपये
42	27	श्री वारियर	केरल राज्य में रियायती दरों पर मछुस्रों को नमक देने की स्रावश्य- कता ।	100 रुपये
42	28	श्री वारियर _.	केरल राज्य में मछिलयों का संग्रह करने के लिए शीत संग्रहागार की सुविधायें कायम करने की ग्रावश्यकता ।	100 रुपये
42	29	श्री वारियर	केरल राज्य में कृषिजन्य पदार्थ, मछली गोश्त ग्रौर दूध से बने हुए पदार्थ लाने- ले जाने के लिए रेलों ग्रौर सड़क परि- वहन में शीत-संग्रहागार की व्यवस्था चालू करने की ग्रावयक्कता।	100 रुपये.
42	30	श्री वारियर .	केरल राज्य में राशन की दुकानों में चावल की बिक्री पर भ्रधिकार की वसूली बन्द करने की ग्रावश्यकता ।	100 रुपये
42	31	श्री वारियर	केन्द्रीय नारियल समिति ग्रौर केन्द्रीय सुपारी समिति को कायम रखने की ग्रावश्यकता ।	100 रूपये
42	32 %	ी वारियर	कीड़ों ग्रादि के कारण केरल राज्य में बड़े पैमाने पर नारियल के पेड़ों को नष्ट होने से बचाने के कार्य को को दृढ़तर करने की ग्रावश्यकता ।	100 रुपये
42	33	श्रीकोया .	. केरल राज्य में मत्स्य-उद्योग चालू करने की स्रावश्यकताः।	100 रुपये

मांग ःसंख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम		कटौती का स्राधार	कटौती की राशि
-42	34	श्री कोया .	•	कटिहार (बिहार) के निकट चीनी के कारखाने खोलने की स्रावश्य- कता ।	100 रुपये
·42	35	श्रीकोया .	•	केरल के समुद्री मीन क्षेत्र में मत्स्यपालन प्रोद्यौगिकी के बारे में उच्चतर शिक्षा देने की स्रावश्यकता।	100 रुपये
-43	36	श्री यशपाल सिंह	•	बंजर भ्मि को कृषि योग्य बनाने की स्रावश्यकता ।	100 रुपये
43	37	श्री यशपाल सिंह	•	खांडसारी लाने ले जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध हटाने की स्राव- श्यकता।	100 रुपये
-43	38	श्री यशपाल सिंह	•	किसानों को उचित मूल्य पर छोटे ट्रैक्टर सप्लाई करने की स्राव- श्यकता।	100 रुपये
·43	39	श्री यशपाल सिंह	•	सिंचाई में सुधार करने के लिए ग्रौर ग्रिधिक नलकूप लगाने की ग्राव- श्यकता।	100 रुपये
.43	40	श्री यशपाल सिंह		उर्वरक के रूप में हरी खाद श्रौर गोबर प्रयोग को लोकप्रिय बनाने की ग्रावश्यकता।	100 रुपये
.43	41	श्री यशपाल सिंह		गन्ने का न्यूनतम मूल्य 3 रुपये प्रति मन निश्चित करने की स्रावश्यकता।	100 रुपये
43	42	श्री यशपाल सिंह	•	वनस्पति घी के लिए उपयुक्त रंग ढूंढ़ने में ग्रसफलता।	100 रुपये
43	43	श्री यशपाल सिंह		श्रनाज की कीमतों में वृद्धि रोकने की स्रावश्यकता।	100 रुपये
43	44	श्री यशपाल सिंह	•	विदेशों से मंगाये गये स्रनाज के वितरण में स्रनियमितताएं विशेषकर वायदे के स्रनुसार उत्तर प्रदेश को गेहूं का न दिया जाना।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव प्रंख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का ग्राधार	कटौती की राशि
43	45	श्री यशपाल सिंह	पशूत्रों के नस्ल में सुधार करने ग्रौर संवर्धन समिति के काम की समी करने की ग्रावश्यकता ।	
43	46	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	किसानों के लाभ के लिये फसल ग्र पशु बीमा योजना चालू क की ग्रावश्यकता ।	
46	56	श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	वन सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाने ग्रावश्यकता ।	की 100 रुपये
130	57	डा० मा० श्री० ग्रणे	सड़े हुए थैंलों में अमोनियम सल्फेट र उर्वरक भेजने की लापरवाही अ समय पर रेलवे रसीदें न भेजना अ सम्बन्धित समितियों और ग्राहकों शिकायतों के प्रति उदासीनता	गैर गौर [∶] की
42	63	श्री सरजू पाण्डेय	. देश को अन्न के लिए ग्रात्मनिर्भर बनाने में ग्रसफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।
42	64	श्री सरजू पाण्डेय	. ग्रनाज की वसूली सम्बन्धी नीति ग्रौर ग्रनाज के भाव । -	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।
42	65	श्री सरजू पाण्डेय	. त्रुटिपूर्ण भूमि सुधार, जिनके कारण जमीन जोतने वालों को नहीं मिलती ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।
42	66	श्री सरजू पाण्डेय	. खेतीहर मजदूरों को बेकार जमीन न बांटना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।
42	67	श्री सरजू पाण्डेय	. कृषि विभाग के कार्य को सुव्य- वस्थित करने की ग्रावश्यकता	100 रुपये
42	68	श्री सरजू पाण्डेय	. स्रधिक उर्वरक, स्रच्छे बीज स्रीर पानी सम्बन्धी सुविधास्रों की स्रावश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का न	 1म	कटौती का ग्राधार	कटौती की राशि
43	69	श्री सरजू पाण्डेय	•	बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने की स्रावश्यकता ।	100 रुपये
43	70	श्री सरजू पाण्डेय		किसानों को उचित मूल्य पर ट्रैक्टर देने की स्रावश्यकता ।	100 रुपये
43	71	श्री सरजू पाण्डेय		पूर्वी-उत्तर प्रदेश म ग्रौर ग्रधिक नलकूप लगाने की ग्रावश्यकता।	160 रुपये
43	7 2	श्री सरजू पाण्डेय		श्चनाज की कीमतों में वृद्धि रोकने की स्रावश्यकता ।	100 रुपये
43	73	श्री सरजू पाण्डेय		विदेशों से मंगाये गये अनाज के वितरण में अनियमिततायें, विशेषकर वायदे के अनुसार उत्तर प्रदेश को गेहूं का न दिया जाना।	100 रुपये
43	74	श्री सरजू पाण्डेय		टिड्डियों के ग्राक्रमण को रोकने में ग्रसफलता।	100 रुपये
43	75	श्री सरजू पाण्डेय		वनस्पति घी को रंगने में श्रसफलता।	100 रुपये
43	76	श्री सरजू पाण्डेय		सस्ते उर्वरक उपलब्ध करने में स्रसफलता।	100 रुपये
43	77	श्री सरजू पाण्डेय		जोरदार खेती की म्रावश्यकता ।	100 रुपये
43	78	श्री सर जू पाण्डेय		विभिन्न प्रकार की तम्बाक्, हल्दी, मिर्च ग्रौर कृषि-जन्य वस्तुग्रों के न्यूनतम भाव निश्चित करने की ग्रावश्यकता।	100 रुपये
43	79	श्री सरजू पाण्डेय		स्रफसरों को कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये संयुक्त राज्य स्मिरिका भेजने की निरर्थकता।	100 रुपये
44	80	श्री सरजू पाण्डेय		कृशि सम्बन्धी गवेषणा का मन्द कार्यक्रम ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौतो प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का श्राधार	कटौती की राशि
44	81 8	श्री सरजू पाण्डेय	. पौधों को कीड़ों से बचाने में ग्रसफलता।	100 रुपये
44	82 8	श्री सरजू पाण्डेय	. धान को रोगमुक्त करने में ग्रसफलता।	100 रुपये
.44	83 8	थी सरजू पाण् डे य	. मक्के की फसल के सुधार में प्र गति का ग्रभाव।	100 रुपये
44	84 8	प्री सर जू पाण्डेय	. ग्रालू की फसल को नष्ट करने वाले कीड़ों की रोकथाम मैं ग्रसफलता।	100 रुपये
44	85 %	प्री सर ज् पाण्डेय	 भारतीय कृषि ग्रनुसंधानशाला में ग्रस्थायी स्त्री कार्यकर्ताग्रों को मर्दों के बराबर वेतन न दिया जाना । 	100 रुपये
44	86	श्री सरजू पाण्डेय	. स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति में विलम्ब ।	100 रुपये
45	87	श्री सर जू पाण्डेय	. पशुपालन योजना में ग्रसफलता ।	100 हपये
4.5	88	श्री सरजू पाण्डेय	. पशुग्रों को पशु महामारी से बचाने में ग्रसफलता ।	100 रुपये
45	89 3	श्री सरजू पाण्डेय	. गोसंवर्धन परिषद् के नाम पर फिजूल खर्च ।	100 रुपये
46	90 3	श्री सरजू पाण्डेय	. वन-सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाने की म्रावश्यकता।	100 रुपये
47	91 3	श्रो सरजू पाण्डेय	. पर्याप्त माल्ना मैं दुग्ध उत्पादन मैं ग्रसफलता।	100 रुपये
47	92	श्रो सरजू पाण्डेय	. दिल्ली दुग्ध योजना में ग्रनियमित तायें	100 हपये
47	93	श्री सरजू पाण्डेय	. खांडसारी के उत्पादन को प्रोत्सा- हन देने में ग्रसफलता।	100 ह्रपये
129	94	श्री सरजू पाण्डेय	. ग्रनाज के थोक व्यापार को सरकारी नियं त्रण में लेने में ग्रसफलता ।	100 रुपये

				III 2/, 1903
मांग सं रू या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौतो का म्राधार	कटौती की राशि
42	95	श्री कोया	फलों पर ग्रतिरिव्त भाड़ा हटाने के सम्बन्ध में रेलवे को प्रभा- वित करने में ग्रसफलता।	100 रुपये
42	96	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	. मैसूर राज्य की तुंगभद्रा परि- योजना के क्षेत्र में कमलापुर की रैंय्यत को एक सहकारी चीनी कारखाना खोलने के लिए ग्रनुमति देने की ग्रावश्यकता ।	100 रुपये
42	97	श्री शिवमूर्ति स्वामी	. तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र में कम से कम पांच और सहकारी चीनी कारखानों की आव- श्यकता।	100 रुपये
42	98	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	. सीमित क्षेत्रों में तथा राज्यों के क्षेत्र के ग्राधार पर ग्रनाज लाने-ले जाने की नीति ।	100 रुपये
42	99	श्री शिवमूर्ति स्वामी	. जिस जमीन पर ग्रनाज बोया जाता है उस पर लगान कम करने की ग्रावश्यकता।	100 रुपये
42	100	श्री शिवमृति स्वामी	 चीनी उद्योग निदेशालय द्वारा सहकारी चीनी कारखानों को लाइसेंस दिये जाने से संबंधित नीति। 	100 रुपये
42	101	श्री शिवमूर्ति स्वामी ,	. मैसूर के तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र के ग्रन्तर्गत सहकारी चीनी कारखानों को लाइसेंस न देना।	100 रुपये
42	102	श्री शिवमूर्ति स्वामी	. कमलापुर सहकारी चीनी कारखाने को लाइसेंस न देना।	100 रुपये
2	103	श्री शिवमूर्ति स्वामी	. तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद स्रनाज का स्रायात बन्द न करना ।	100 रुपये

मांग संरू या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौतो का ग्राधार	कटौती की राशि
42	104	श्री शिवमूर्ति स्वामी	. स्थानीय तथा विदेशी मांग पूरी करने के लिए चीनी का उत्पादन न बढ़ाना।	100 रुपये
42	105	श्री मनोहरन .	स्थानीय ग्रौर विदेशी मांग पूरी करने के लिये चीनी का उत्पादन बढ़ाने में ग्रसफलता ।	1 रुपया कर
42	106	श्री मनोहरन .	ग्रनाज के मामले में देश को ग्रात्मनिर्भर बनाने में ग्रसफलता।	राशिघटा कर 1 रुपया कर दीजाये।
42	107	श्री मनोहरन .	त्रनाजों की कीमतों में वृद्धि रोकने की ग्रावश्यकता।	100 रुपये
42	108	श्री मनोहरन .	बनस्पति घी में रंग डालने में श्रसफलता।	100 रुपये
42	109	श्री मनोहरन .	पशुस्रों को पशु-महामारी से बचाने में श्रसफलता।	100 रुपये
42	110	श्री मनोहरन .	किसानों को उचित दाम पर ट्रैक्टर देने की ग्रावश्यकता ।	100 रुपये
42	111	श्री मनोहरन .	वन-सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाने की ग्रावश्यकता ।	100 रुपये
42	112	श्री मनोहरन .	पशुपालन योजनाम्रों की म्रसफलता	। 100 रुपये
42	113	श्री मनोहरन .	मद्रास राज्य में धर्मपुरी जिले के खेतिहरों को ग्रपने क्षेत्र में एक सहकारी चीनी कारखाना स्थापित करने की ग्रनुमति देने की ग्रावश्यकता।	100 रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : ये कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं।

Shri Chandak (Chhindwara): India is predominantly an agricultural country. Its seventy per cent population lives in the villages. Agriculture is the basic industry of the country. It is also true that much has been done in the field of agriculture, more irrigation facilities have been provided and some improvement has also been

[Shri Chandak]

made. But there has not been sufficient improvement though the three Five Year Plans have been completed.

When we had started the community development programme it was expected that it will change the shape of the villages. But the work has not been done according to our expectations. The work done has been superfluous as Sarvashri Mishra and Patel have said. Fifty two per cent of the allotted money is spent on establishment and 48 per cent on miscellaneous items. Thus agricultural development is totally ignored.

When we have already got the Ministry of Food and Agriculture and the Ministry of Irrigation and Power and the Ministry of Education are also there then what is the need of the Ministry of Community Development. The need of the hour is to entrust the whole work of agricultural development to the agricultural department.

The agriculturists should be given remunerative price. They should also be given incentive price. But to my mind this idea appears to be very vague. How can he get the remunerative price? We can find out the remunerative price if we know the cost price of a thing and the cost price we can know only in the industry. So, we cannot fix cost price of agriculture unless we consider it an industry. We must give remunerative price if we want to develop agriculture. Hence we should consider agriculture as an industry.

The setting up of National Food Corporation will be a welcome measure. But the corporation should come in the market as a trader. Only then the agriculturists can get reasonable prices of their produce and the Government can also have the necessary funds with them unless and until there is a competition in the market the consumers cannot get the desired benefits. The Government should also take this point into consideration.

भ्रध्यक्ष महोदय पोठासीन हुए । Mr. Speaker in the Chair

For the development of agriculture there is a great need of small irrigation facilities. Most of the hon. Members have also drawn the attention of the hon. Minister that cheap electricity should be provided to the agriculturists. Apart from that they should also be given fertilisers at reasonable prices. Though huge dams have been set up but the farmers are not getting water to irrigate their fields. In my constituency there are no irrigation facilities. The canals are not there. The land there can be irrigated with wells. But the wells there are not sufficient and the water in them too is very less. The fertilisers too are not available. Their prices also have gone up. So, unless irrigation facilities and fertilisers at cheap rates are made available to the agriculturists there cannot be any increase in agricultural production. The Government should pay much attention to it.

The Government should also see that the agriculturists get proper training in the use of chemical fertilisers.

There is also disparity in the distribution of foodgrains. The villagers are getting less foodgrains than the urban people though they have to put in more labour. The ratio is 2:13.

Then there is also a Government monopoly in the purchase of foodgrains. In my State, Government is purchasing maize at the rate of Rs. 45 per quintal but sells it at Rs. 53 per quintal. Thus there is a net gain of Rs. 8 per quintal. Had the farmers sold it directly they would have been benefited by Rs. 8 per quintal.

The position of the supply of sugar can also be improved. It is expected that we will be producing 32 lakh tons of sugar this year while our consumption is not more than 22 lakh tons. Thus after exporting sugar we can have this much with us. Hence the ban on sugar can easily be removed.

Lakhs of acres of land are lying waste in the ravines of Chambal. That land should be fully utilised. Farming can be undertaken on that land through co-opertives. So, the Chambal Project needs immediate attention.

Government should give its approval to the setting up of a sugar mill in Betul district because sugarcane is grown there in abundance. Land revenue should be realised in kind instead of in cash. Consumer and producer prices should be fixed. The farmers should get remunerative prices for their produce so that they may feel encouraged to raise their production. These prices should be fixed before the sowing season.

Shri Sivamurthi Swamy (Koppal): The amount earmarked for agriculture is too meagre. 80 per cent of our population depends on agriculture. If a permanent solution of the food problem is to be found, then at least 50 per cent of the total earnings of the country should be set apart for promotion of agriculture.

The agriculture department has many good for nothing organisations, as for example, the National Tractor Organisation. It has no contact with the farmers. It is very difficult to secure a tractor even for a plot of 500 acres of land. Government should see to it that tractors are made available to the needy farmers in time.

Even a suitable colouring material for vanaspati ghee has not been found as yet. In Mysore State sandal wood trees are being destroyed indiscriminately. This precious forest wealth should be preserved and Government should see that these trees are not allowed to be destroyed.

In the Tungabhadra area, a scheme called the localisation scheme has been introduced. If a farmer has started raising rice crop he will have to raise rice crop every year. He cannot raise any other crop. If he does so he will be fined heavily. Similarly if any area has been reserved for sugarcane cultivation, only sugarcane can be sown there. If any farmer starts raising rice crop there he will only be given as much water as would have been sufficient for the sugarcane crop. He is not given more water, no

[Shri Sivamurthi Swamy]

matter if the water flows into the sea unused. Thus, the water of the reservoir is not made use of. Therefore, my submission is that this localisation scheme should be deferred for a period of at least four or five years.

Under this localisation scheme sugarcane is being sown in an area of seventy thousand acres. But there are not enough factories there to crush the sugarcane. After prolonged efforts a sugar mill was licensed in the Co-operative sector. But, strangely enough, the very next year the Co-operative Society itself was ordered to be dissolved and the licence was cancelled. After that a wealthy man Shri Kila Chand formed a joint stock company and he was given licence for that. But nothing came out of that. The people of Tungabhadra have been trying to get the old licence revived for the last 12 years but their efforts to set up a sugar mill in the co-operative sector have not borne fruit as yet. On the other hand, Shri Morarka, an hon. Member of this House, has been allowed to set up another sugar factory there. We welcome the setting up of this factory. But our grievance is this. When we fulfil all the conditions laid down for the setting up a co-operative sugar mill, why a license is not being granted. This year an area of 9 or 10 thousand acres was reserved for the sugar mill owned by Shri Morarka. The result was that the mill could not crush all the sugarcane and the sugarcane standing in an area of 3400 acres totally dried up. The people there have incurred a loss of Rs. 15,000 in this season. Because of the reservation the sugarcane could not be diverted to other mills. The people of that area have been demanding the setting up of a Committee for this. They cannot go on waiting, and have lost patience.

I, therefore, plead to all sections of the House to press the Government to grant a license for setting up a co-operative mill to those people, as this is not a party issue. The Government will not have to bear any financial burden because some co-operatives have also made arrangement for that. Several banks are ready to give loans on nominal interest.

Ten sugar factories can be started in the Tungabhadra area, but at least five are most essential. After being registered as a cooperative society, we come to the Central Government but all in vain. We are not given any licence. If Government has made any agreement with Shri Morarka regarding reservation of certain area for his factories, we are ready to set apart that much area for those factories. The Kamalapur Cooperative Society is ready to make offers in this connection. There is a rivulet there. If a bridge is constructed over it. the whole area can be connected, and there will be so many areas to supply sugarcane to the mills. It is indeed very sad that the sugar Directorate is influenced by wealthy people, and it has adopted a callous attitude towards the cooperative movement. There is a great shortage of sugar in the villages. I do not understand as to why this artificial scarcity is being created in the country. There is no shortage of sugarcane in the south and there have been no instances of underfeeding of mills there. There is, therefore, no justification for not granting any licence to the cooperative societies there.

We have no objection if licences for setting up one or two mills are granted to Shri Morarka. But we cannot tolerate the mortgaging of the whole district to him. We should also be given some licences. If licence is not granted this season, our work would not proceed further. It is regrettable that the report of the committee appointed by the Government has not yet been submitted. Shri Morarka in the annual report pleads for the cancellation of the Kamalapur Cooperative Society and expansion of the joint stock company. The society has incurred a loss of Rs. 15 lakhs this year, and this department is answerable for that. It is very strange that even in spite of the Chief Ministers' recommendation, the society has not been granted licence by the Centre. I submit that the Government should accept this humble appeal and thereby encourage the cooperative movement.

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना): प्रचीन काल में भारत में ग्रनाज की कमी नहीं थी ग्रीर शिक्षा के क्षेत्र में भी वह पिछड़ा हुग्रा नहीं था। यहां तक कि भारत से ग्रन्य देशों को माल जाता था। परन्तु दुःख की बात है कि जबकि यूरोप में कृषि तथा ग्रौद्यो- गिक क्षेत्र में क्रांति हुई ग्रौर वे देश ग्रागे बढ़ गये परन्तु भारत के लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे ग्रौर विश्व में बदलती हुई परिस्थितियों के ग्रनुरूप ग्रपने को नहीं बदल सके।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के ग्रौद्योगीकरण की दिशा में भरसक प्रयत्न किया। परन्तु एक व्यक्ति चाहे व कितना ही महान् क्यों न हो इतने बड़े देश को थोड़े से समय में ग्रौद्योगीकरण के पथ पर ग्रग्नसर नहीं कर सकता। इसका कारण यह था कि परिश्रम को महत्व देने की बजाय सचाई तथा ग्रध्यात्मवाद पर ही जोर दिया गया। उत्पाद की ग्रोर ख्याल ही नहीं गया।

यह बड़े दु:ख की बात है कि ग्रपने देश के लोग ग्रपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने की बजाय ग्रपने बाप दादा की मर्यादा का ही ग्रधिक ख्याल रखते हैं। वे ग्रब भी ग्रन्धविश्वासी हैं। वे सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। उनके इस दृष्टिकोण को बदलना बहुत जरूरी है ग्रौर यह तभी हो सकता है जब शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाये।

कृषि शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये जिससे किसान को पता लग सके कि किस भिम पर क्या पैदा करना है, क्या उपकरण इस्तेमाल करने हैं और कितना खाद, कितना बीज तथा कितना पानी आदि चाहिये और खेत कितना बड़ा होना चाहिये। जब किसानों को इन बातों की जानकारी हो जानेगी तथा कृषि एक लाभदायक उद्योग का रूप ले सकती है। भारत में कृषि शिक्षा देने वाली संस्थाओं की बहुत कमी है। इसलिए देश में अधिक संख्या में कृषि कालेज खोले जाने चाहिये। उद्योगों के विकास से पहले कृषि का विकास करना जरूरी है। अन्य उद्योग तभी पनप सकते हैं जब कृषि खब तरक्की पर हो।

किसान को ग्रन्य रोजगारों में लगे हुए व्यक्तियों से कम ग्राय होती है। इसका कारण यह है कि वह इनसे कम शिक्षित होता है ग्रौर उसका ग्रपना कोई संगठन नहीं

[श्रो कु० चं० शर्मा]

है। इसिलये प्रितिव्यक्ति उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयाप्त शिक्षा का उपबन्ध किया जाना चाहिये। किसानों को खाद, ग्रन्छा बीच, सिंचाई का पानी ग्रादि उपलब्ध किया जाना चाहियें। इस संबंध में खण्ड विकास ग्रधिकारी उनकी सहायता कर सकते हैं। वे उन्हें बतला सकते हैं कि कितना खाद, बीज ग्रादि इस्तेमाल किया जाना चाहिये ग्रौर सीमेंट तथा ग्रन्य चीजें कैसे प्राप्त की जा सकती हैं। वे इस दिशा में ग्रन्छा काम कर रहे हैं। हां, कभी कभी विभागीय किठनाइयां उनके काम में बाधक सिद्ध होतं। हैं। कृषि वस्तुग्रों की मांग भी बढ़ानी पड़ेगी। कृषि वस्तुग्रों के मूल्यों में वृद्धि की जानी चाहिये। किसान को उसकी मेहनत के मुताबिक मंजूरी नहीं मिलती है। किसान को इससे नुक्सान होता है कि फसल ग्राने पर मूल्य कम हो जाते हैं। इन सब की ग्रोर ध्यान दिये जाने की ग्रावश्यकता है।

सभी देशों में बिचौलिया किसान के लिए एक ग्रभिशाप साबित हुग्रा है ग्रौर भारतीय किसान के बारे में भी यह सही है। जहां तक किसान को ग्रर्थ सहायता देने का प्रश्न है वह संभव नहीं है। परन्तु किसान की ग्राय को बढ़ाने के लिए उसको सीधा ग्रनुदान दिया जाना चाहियें।

कृषि का एक र.मन्वित कार्यक्रम होना चाहिये। ग्रब प्रश्न उत्पन्न होता है कि मशीनों से सहकारी खेती शुरू की जानी चाहियं। जो फालतू लोग कृषि के काम में लगे हुए हैं उन्हें वहां से निकाला जाना चाहिये। किसानों का एक संगठ होना चाहिये जो किसानों का पक्ष पेश कर सके।

मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में ऋांतिकारी परिवर्तन लाना जरूरी है।

श्रीमती ग्रकम्मा देवी (नीलिगरी): खाद्य तथा कृषि केवल इस मंत्रालय का ही उत्तरदायित्व नहीं है ग्रिपितु सामुदायिक विकास तथा सहकार तथा सिंचाई ग्रीर विद्युत् मंत्रालयों का भी इस विषय से संबंध है। ग्रितः इन मांगों पर चर्चा के समय तीनों मंत्रालयों के मंत्रियों को सभा में उपस्थित रहना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय पेठासीन हुए । Mr. Deputy Speaker in the Chair

भारतीय खाद्य निगम को कृषिकों को छोटी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम भी सौंपा जाना चाहियं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विशेषकर मैंतु गलारम, ग्रविनाशी तथा सुलूर में सिंचाई सुविधाग्रों का बहुत ग्रभाव है। 1962 से भी पहले कुण्डा परियोजना के फालतू पानी से इन क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करने का फैसला किया गया था। परन्तु खेद की बात है कि ग्रब तक कुछ भी नहीं हुग्रा है। राज्य सरकार का ध्यान इस ग्रोर दिलाया जाना चाहिये।

फालतू भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों को दिया जाना चाहिये। इससे उन्हें रोजगार भी मिल जायेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। हमारे यहां खाद्य में ही मिलावट नहीं की जाती ग्रिपितु खाद्य तथा कीट नाशक दवाइयों में भी मिलावट की जाती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा हुग्रा है। मिलावट करने वालों को दण्ड दिया जाना चाहिय।

मैं जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर ग्राई हूं वह एक पहाड़ी क्षेत्र है। परिवहन तथा संचार की किठनाइयों के कारण पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करना ग्रासान नहीं है। इन्हीं किठनाइयों को ध्यान में रखकर ही पहाड़ी क्षेत्र विकास मंत्रणा सिमिति बनाई गई थी। इसकी पहली बैठक पिछले वर्ष 1 मई को हुई थी ग्रौर उसके बाद इसकी कोई भी बैठक नहीं हुई है। उस बैठक में इस सिमिति ने पहाड़ी क्षेत्रों के, जो हमारे सिमान्त क्षेत्र भी हैं, विकास के लिये बहुत-सी सिफारिशें पास की थीं। परत्रु खेद है कि ग्रभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुग्रा है। ग्रतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

भूमि के कटाव को रोकने के लिये भूमि संरक्षण योजना बनी हुई है। विकास म्रिधिकारी ग्रामीणों की सहायता करने की बजाय उनके मन में भ्रम पैदा करते हैं ग्रीर उनके लियं ग्रनावश्यक समस्यायें पैदा कर देते हैं। प्रतिवेदन में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बातें दी जाती हैं। ग्रतः सामुदायिक विकास मंत्री को स्वयं गांवों में जा कर इन ग्रधिकारियों द्वारा किये गये कार्य की जांच करनी चाहिये। फायलों को इधर-उधर भेजने में देरी नहीं होनी चाहिये ताकि काम को शुरू करने में देरी नहों सके ग्रीर किसानों को वित्तीय सहायता ग्रादि समय पर प्राप्त हो सके।

सहकारी खेती सिमितियों को मंजूरी देने में बहुत श्रिधक देर की जाती है। इस श्रोर ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि इससे न केवल लोगों को रोजगार ही मिलेगा श्रिपतु उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

श्री कन्डप्पन (तिरचेनगोड): इस मंत्रालय का इतिहास स्वतंत्रता प्राप्ति से श्रब तक बहुत शोकजनक रहा है। यह बहुत ही खेद की बात है कि जब कृषि उत्पादन की बात बढ़ाने के लिये देश में पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं तब भी श्रनाज बाहर से मंगाया जा रहा है।

भिन्न-भिन्न जल वायु तथा भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी वाले इस देश में इस बारे में सर्वेक्षण करना बहुत जरूरी है कि कहां कहां पर क्या क्या फसल उगाई जानी चाहिये। चीनी उद्योग के बारे में विशेषकर मैं कुछ कहना चाहता हूं। गन्ना गरम जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। परन्तु इस ग्रोर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन तीन गुणा से भी ग्रधिक है। इसलिये इस बात की ग्रोर ध्यान दिया जाना चाहिये कि दक्षिण भारत में ग्रिधक माला में गन्ने की काश्त हो ग्रीर वहां पर चीनी मिल खोलने के लिये लोगों को लाइसेंस दिये जायें। इससे चीनी की कमी काफी हद तक दूर हो जायेगी।

श्रि कन्डप्पन]

बाजार में अनाज की कमी के लिए व्यापारी वर्ग अथवा किसानों पर सारा दोष थोपना उचित नहीं है। यह हो सकता है कि व्यापारी लोगों ने अनाज जमा करके रखा हो। परन्तु यदि उत्पादन पर्याप्त मात्ना में हुआ हो, तो वे ऐसा करने के लिये प्रेरित नहीं होंगे। जहां तक उत्पादन में वृद्धि करने का प्रश्न है, किसानों के सम्मान को ध्यान में रखा जाना चाहिये। यह आरोप सही नहीं है कि हमारे किसान कृषि के आधुनिक तरीकों के खिलाफ हैं। इसके विपरीत, वास्तविक स्थिति यह है कि आधुनिक उपकरणों की उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है?

तामिलनाड में किसानों को बिजली उपलब्ध कराने की ग्रोर ग्रीर ग्रिधक ध्यान दिया जाना चाहिये। पानी की कमी के कारण भी वहां पर कृषि उत्पादन नहीं बढ़ पाया है। मैं इस बारे में ज्यादा विस्तार में न जा कर मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सरकार थीरुमनीमुत्तर—पोन्नायार योजना को हाथ में ले ग्रीर उस पर बिना विलम्ब कार्रवाई की जाये।

जिन क्षेत्रों में प्रति एकड़ उत्पादन ग्रिधिक होता है ग्रौर किसानों का कृषि की ग्रोर यिक सम्मान है, वहां पर किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहियें ताकि थोड़े समय में ग्रिधिक उत्पादन हो सके।

सिचाई को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये। खाद के वितरण के बारे में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जहां उसका ठीक प्रकार से उपयोग होता है।

Shri Radhelal Vyas (Ujjain): Government has been trying during all these years to make the country self-sufficient, so far as production of foodgrains is concerned. But the stark reality is this that now we are importing foodgrains in far larger quantities than in previous years. This is not something we can be proud of. This year the food situation became very acute. It has eased some what now. But we have to think over it very seriously that we cannot depend on imports for all time to come. We should strive to achieve self-sufficiency in the matter of foodgrains production.

The yield per acre in our country is very low as compared to other countries. Serious thought should be given to this matter and all the resources should be mobilised to raise agricultural production. We do not have much expectations from the plans. We have an imminent danger on our borders and the population is also increasing at a fast pace. So the reconsideration of the whole issue is required and some positive steps should be taken to effect a considerable increase in agricultural production in the country.

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ग्रपना भाषण कल जारी रखें।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

छत्तोसवां प्रतिवेदन

श्री राते (बुजडाना) : मैं कार्य मंत्रणा सिमिति का छत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता है।

इसके पश्चात लोक-सभा बुभवार, 28 अप्रैल, 1965 / 8 वैशाख, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 28, 1965/Vaisakha 8, 1887 (Saka).